आतंक के बीज तलाशें जम्मू-कश्मीर में

पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की चर्चा हो रही थी। अब लगातार हो रहे आतंकी हमलों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे से चुनौती पैदा की है। जम्मू में रियासी, कठुआ और डोडा में चार दिनों में चार आतंकी हमले हुए हैं। रविवार को रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस के चालक पर हुए हमले के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। जिसमें नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। फिर कठुआ व डोडा में हुए आतंकी हमलों में एक जवान और दो आतंकवादी मारे गए हैं। इन घटनाओं में छह जवानों समेत पचास के करीब लोग घायल हुए हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और हथियार भी बरामद हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की है। इसमें आतंकवाद की नई चुनौती से मुकाबले की रणनीति पर विचार हुआ है। दरअसल, नई सरकार बनने की प्रक्रिया के दौरान हुए इन हमलों में पाक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। चिंता की बात यह है कि एलओसी से लगते जम्मू के इलाके में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। मारे गये दो आतंकवादियों के पास से पाकिस्तानी हथियार व सामान की बरामदगी बताती है कि पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठानों की मदद से यह आतंक का खेल फिर शुरू किया जा रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में बनी गठबंधन सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पाक पोषित आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में दखल दे सकते हैं। कहा जा सकता है कि राज्य में लोकतंत्र को मजबूत होते देख बौखलाहट में ये आतंकवादी हमले किये जा रहे हैं। दरअसल, केंद्रशासित प्रदेश का शांति-सुकून की तरफ बढ़ना आतंकवादियों की हताशा को ही बढ़ाता है। हाल के दिनों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का घाटी में आना और लोकसभा चुनाव में बंपर मतदान सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं को रास नहीं आया है। वहीं इन हमलों का चिंताजनक पहलू यह है कि अब तक आतंकी घटनाओं का केंद्र दक्षिण कश्मीर आदि इलाके होते थे, अब की बार ये हमले जम्मू क्षेत्र में हुए हैं। जम्मू के इलाके में आतंकी घटनाओं में वृद्धि शासन-प्रशासन के लिये गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इन हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उल्लेखनीय है कि रविवार को हुए हमले की जिम्मेदारी जहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी गुट टीआरएफ ने ली तो डोडा में हुए हमले की जिम्मेदारी पाक पोषित जैश-ए-मोहम्मद के एक गुट कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी संगठन ने ली है। बहरहाल, भारतीय सेना व सुरक्षा बल आतंकवादियों को भरपूर जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस माह के अंत में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का निर्बाध आयोजन सुरक्षा बलों के लिये बड़ी चुनौती होगी। जिसको लेकर विशेष चौकसी बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर हाल के आतंकी हमले केंद्र सरकार व राज्य प्रशासन को भी आत्ममंथन का मौका देते हैं। केंद्र सरकार विचार करे कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद क्या वाकई घाटी में स्थिति सामान्य हो पायी है? हाल के लोकसभा चुनाव में हुआ बंपर मतदान क्या चरमपंथियों को संसद भेजने का उपक्रम था? क्या वजह है कि राज्य में लंबे समय से लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दिग्गज राजनेता लोकसभा चुनाव में धराशायी हो गए? हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाली को लेकर जो दावे किये जा रहे थे तो क्या जमीनी हकीकत ऐसी ही है? देश के नीति नियंताओं को आत्ममंथन करना होगा कि क्यों कश्मीर का जनमानस राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पा रहा है? क्या कश्मीरी लोगों में नई व्यवस्था में अपने अधिकारों की सुरक्षा व संपत्ति के अधिकारों को लेकर मन में संशय की स्थिति में वृद्धि हुई है? हमें यह तथ्य स्वीकारना चाहिए कि किसी भी राज्य में आतंकवाद का उभरना स्थानीय सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। वहीं यह भी हकीकत है कि कश्मीरी जनमानस का दिल जीतना शक्ति से नहीं बल्कि उनके अनुकूल नीतियां बनाने व लोकतंत्र की बहाली से ही संभव है।

संघ के बिना भाजपा का कोई वजूद ही नहीं

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत मृदु स्वभाव वाले और मितभाषी हैं। वे किसी खास मुद्दे या अवसर पर ही अपनी बेबाक राय रखते हैं। लेकिन, जब भी वे कुछ कहते हैं तो उसे गौर से सारा देश सुनता और समझने की कोशिश करता है। उनके वक्तव्यों की पूरे देश में विभिन्न कोणों से व्याख्या होने लगती है। हाल ही में आए लोकसभा चुनावों के बाद डॉ. मोहन भागवत ने भाजपा नेताओं पर सांकेतिक और परोक्ष रूप से 'अहंकारी' होने के आरोप लगाकर राजनीतिक क्षेत्रों में, खासकर भाजपा कार्यकताओं के बीच भूचाल सा ला दिया है।

मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ₹एक सच्चा सेवक काम करते समय मयार्दा बनाए रखता है। उसमें कोई अहंकार नहीं होता कि ह्लमैंने यह किया।ह्व केवल ऐसा व्यक्ति ही सेवक कहलाने का अधिकारी है।₹ आखिर वे अहंकार पर चर्चा करके क्या कहना चाहते हैं? एक आम राय यह भी है कि डॉ. भागवत की दृष्टि में भाजपा के कुछ नेता सत्ता पर काबिज होने के बाद विनम्र नहीं रहे। वे अहंकारी हो गए। वे आम जनता के सरोकारों से दूर हो गए। उन्होंने जन सेवा के कामों से अपने को दूर कर लिया। इसी कारण के चलते ही जनता ने लोकसभा चुनावों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं दी । मुझे भाजपा के एक प्रमुख सहयोगी संगठन के शिखर पदाधिकारी बता रहे थे कि वे कुछ माह पहले किसी जरूरी काम के सिलसिले में एक बार अति प्रमुख स्थान रखने वाले एक केन्द्रीय मंत्री से मिले। मंत्री जी उन महोदय के काम से और संघ निष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे उम्र और तजुर्बे में मंत्री जी से बड़े हैं क मंत्री जी को पता था कि उन्होंने संघ के कार्यकर्ता के रूप में अपना सारा जीवन खपा दिया है। इतना सब कुछ होने पर भी जब उन्होंने कहा कि संघ ने मुझे यह दायित्व दिया है और आपका सहयोग चाहिये क तब मंत्री जी ने कहा कि, यह दायित्व आपने मुझसे पूछकर लिया था क्या ?ह्व उन केन्द्रीय मंत्री जी ने उन संघ निष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता सज्जन को खड़े-खड़े ही चलता कर दिया। मंत्री जी भूल गए कि भाजपा को मजबूती संघ और उसके सहयोगी संगठनों से ही मिलती है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के उन नेताओं को अपनी सोच में बदलाव तो लाना होगा जो संघ के महत्व और विचारधारा से परिचित नहीं है। संघ के बिना भाजपा का कोई वजूद ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी संघ के नाम पर भाजपा के शीर्ष पर पहुँच गये, जिनका स्वयं का संघ कार्य का न तो कोई अनुभव है न ही कभी वे संघ में किसी दायित्व के पदों पर रहे हैं क हाँ, यह अवश्य है कि वे संघ परिवार से आते हैं और उनके पिता या बड़े भाई संघ-निष्ठ कार्यकर्त्ता या पदाधिकारी रहे हैं क

अपने भाषणो में मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तो हमेशा तारीफ करते रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय, मोहन भागवत ने कहा था-ह्य इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने से पहले प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरा उनसे पुराना परिचय है और मैं जानता हूँ, वो तपस्वी हैं ही।₹ संघ भाजपा का अभिभावक संगठन है तो यह स्वाभाविक है कि उसका भाजपा पर असर तो रहेगा ही, साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सक्रिय जीवनदानी पूर्णकालिक प्रचारक भी रहे हैं। अतः मोदी जी, राजनाथ सिंह आदि की बात अलग है क वे संघ को समझते हैं क कुछ समय से दबी-जुबान से यह भी चर्चा होती रही है कि क्या भाजपा हमेशा संघ के प्रभाव में ही काम करती है? अगर नहीं तो संघ का भाजपा पर नियंत्रण किस हद तक है। सही बात तो यह है कि संघ के पचासों अनुषांगिक संगठन अपना-अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं क पर संघ का परोक्ष नियंत्रण और मार्गदर्शन तो रहता ही है जिसे सभी मानते भी हैं। क्या नड्डा को संघ और भाजपा के संबंधों पर यह सब कहना चाहिए था या नहीं, पर कहीं न कहीं संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही संघ और भाजपा के कुछ नेताओं के बीच कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। हालांकि मैं इस संबंध में कुछ भी पुख्ता रूप से नहीं कह सकता कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में चुनाव में हार के बाद संघ की ओर से ही उम्मीदवारों के चयन के लिए दिए गए सुझावों पर ध्यान नहीं दिया। संघ और भाजपा लंबे समय से सभी चुनावों में मिलकर काम करते रहे हैं। हां, यह सच है कि भाजपा में अन्य दलों से बहुत सारे नेता शामिल होते रहे हैं। मुमकिन है कि संघ की सोच को लेकर उनकी कोई बहुत निष्ठा न भी हो। पर यह कोई नहीं मान सकता कि भाजपा को अब संघ के साथ और सहयोग की जरूरत नहीं रही है। भाजपा को संघ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का अनुसरण करना ही होगा। पंडित दीनदयाल जी और अटल जी अहंकार से कोसों दूर थे। वे सज्जनता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ही मुझे 1966 में भारतीय जनसंघ में लाये और उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं उनका प्रवास सहयोगी रहा क वे एक गंभीर दार्शनिक एवं गहन चिंतक होने के साथ-साथ समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता एवं गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किये। जब मैंने उनके साथ बिहार में 1960 के दशक में काम किया तब मैं किशोर ही था । उनकी शख्सियत में दंभ का नामो-निशान तक नहीं था। एक बार हम प्रवास में झारखण्ड के एक सुदूर कस्बे में एक ही कमरे में ठहरे थे और मैंने उनकी धोती साफकर बाहर फैला दिया था क मुझे उनकी डांट पड़ी थी क उन्होंने कहा था कि ह्लयह कामह्व मैं स्वयं करता हूँ, तुमने बिना पूछे क्यों किया क भाजपा के नेताओं को सदैव इन महान संस्थापकों के विचारों और जीवनशैली का अनुसरण करना होगा।

याद रख लें कि किसी ठोस विचारधारा के बिना किसी राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं है। संघ की मार्फत ही भाजपा ह्लराष्ट्रीयह्व शब्द को गहराई से समझती है। मोहन भागवत ने एक बार कहा भी था कि राष्ट्रवाद शब्द समाज के लिए ठीक नहीं है। यह शब्द सीमित करता है। वहीं राष्ट्रीयता शब्द विस्तार देता है। ह्लवादह्व शब्द हमेशा स्वार्थ के लिए होता है। स्वार्थ की पूर्ति होते ही मोह भंग हो सकता है, जबकि राष्ट्रीयता से आत्मीय जुड़ाव होता है।

मोहन भागवत साफ बोलते हैं। मणिपुर की अशांति पर भी मोहन भागवत ने अपनी राय रखी हैं। ₹मणिपुर एक साल से शांति की तलाश में है। इस पर प्राथमिकता से चर्चा होनी चाहिए। राज्य पिछले 10 वर्षों से शांत था। ऐसा लग रहा था कि पुरानी 'बंदूक संस्कृति' खत्म हो गई है। वहां जो अचानक तनाव पैदा हुआ या करवाया गया, उसकी आग में वह अभी भी जल रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? इसे प्राथमिकता देना और इस पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है,₹ यह बेबाक टिप्पणी डॉ. मोहन भागवत की है ।

निस्संदेह पिछले लगभग एक साल से मणिपुर जल रहा है। वहां पर हिंसा और कत्लेआम जारी है। स्थिति काबू में आ ही नहीं रही है। जब लगता है कि अब मणिपुर में अमन की बहाली होने वाली है, तब ही उधर से कोई बुरी खबर सामने आ जाती है। मणिपुर की स्थिति ने सारे देश को परेशान किया हुआ है। जाहिर है कि मोहन भागवत की मणिपुर पर राय से सारा देश अपने को जोड़ता है। अब देश की चाहत है कि मणिपुर में अमन की बहाली हो जाए और संघ-भाजपा के संबंधों में पहले वाली गर्मजोशी दिखाई दे। यह होगा तभी जाकर भाजपा कार्यकताओं और राष्ट्रवादी सोच के नागरिकों का मनोबल बढ़ेगा।

चुनावी 'घावों' पर दोस्ती की मरहम

महेश खरे

आज की सियासत में ऐसा दृश्य कम ही दिखाई देता है...जो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी की ताजपोशी में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी नेताओं की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दिखा दिया।12 जून को चौकीदार पुत्र मोहन माझी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी भारी भरकम टीम के 15 मंत्रियों के साथ भुवनेश्वर में सजे सजाए मंच पर ही थे कि तभी नवीन पटनायक वहां पहुंच गए। नवीन बाबू को देखकर शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो चौंका ना हो। कारण ओडिशा के चुनाव में नवीन पटनायक की बीजेडी और मोदी की बीजेपी मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। लोकसभा चुनाव के प्रचार में सारी मयार्दाएं तार तार होती रहीं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। बीजेपी ने भी नवीन बाबू और उनके तत्कालीन सहयोगी पांडियन पर ताबड़तोड़ आरोप जड़े। नवीन बाबू के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए बीमार साबित करने की कोशिशें हुईं। चूंकि ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटों के साथ 147 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे।

अब चुनाव कटुता बढ़ाने लगे हैं। विरोधी की छवि बिगाड़ने की होड़ में जहर बुझे शब्द एक दूसरे को बाण की तरह चुभते हैं। नफरत के घाव दिखें भले ही नहीं, पर जल्दी भरते भी नहीं हैं। चुनाव अपने तयशुदा समय पर खत्म हो जाते हैं मगर इनसे उपजी दुश्मनी सालों साल चलती रहती है। कभी कभी नेता तो राजनीतिक स्वार्थवश दुश्मनी भुलाकर एक मंच पर आ जाते हैं। लेकिन, कार्यकर्ता नफरत की आग में झुलसते रहते हैं। चुनावी हिंसा इसी का नतीजा है जिसमें कई परिवार उजड़ जाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी की बलि चढ़ती है सो अलग। ऐसे नफरत भरे माहौल में सब कुछ भुलाकर अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वह समाज में उदाहरण बनता ही है... दिल को सुकून भी देता है। लोग कह उठते हैं- रात गई और बात गई।

चुनावी कटुता को पाले रखने में फायदा कुछ ही नहीं...बस, घाटा ही घाटा है। संघ प्रमुख ने नफरत की राजनीति करने वालों को यही तो नसीहत दी है। चुनाव एक स्पर्धा है कोई युद्ध नहीं। ओडिशा में ऐसे ही दृश्य ने लोगों का मन मोह लिया।

आज की सियासत में ऐसा दृश्य कम ही दिखाई देता है...जो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी की ताजपोशी में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी नेताओं की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दिखा दिया।12 जून को चौकीदार पुत्र मोहन माझी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी भारी भरकम टीम के 15 मंत्रियों के साथ भुवनेश्वर में सजे सजाए मंच पर ही थे कि तभी नवीन पटनायक वहां पहुंच गए। नवीन बाबू को देखकर शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो चौंका ना हो। कारण ओडिशा के चुनाव में नवीन पटनायक की बीजेडी और मोदी की बीजेपी मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। लोकसभा चुनाव के प्रचार में सारी मयार्दाएं तार तार होती रहीं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला।

बीजेपी ने भी नवीन बाबू और उनके तत्कालीन सहयोगी पांडियन पर ताबड़तोड़ आरोप जड़े। नवीन बाबू के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए बीमार साबित करने की कोशिशें हुईं। चूंकि ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटों के साथ 147 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे। इस कारण भी मुकाबला जंगी था। गरीबी, अराजकता, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता के आरोप भी जड़े गए। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि चुनावी कड़वाहट को अनदेखा कर नवीन बाबू शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाएंगे। सबको झुठलाते हुए नवीन बाबू वहां पहुंचे और उपस्थित मोदी एवं मोहन मांझी से तो मिले ही... केन्द्रीय मंत्रियों के पास जाकर उन्हें जीत की बधाई दी।

दरअसल आज ऐसी ही सियासत की जरूरत है। चुनाव खत्म तो चुनाव की रंजिश भी खत्म। इसके लिए दिल नवीन पटनायक जैसा चाहिए। गांधी परिवार तो अभी तक चुनावी मोड में ही है। 77 वर्षीय नवीन पटनायक लगातार 24 साल तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। इसके पहले उनके पिता बीजू पटनायक राज्य के दो टर्म तक सत्ता की बागडोर संभाले रहे। अनोखी बात यह है कि 24 साल में नवीन पटनायक ने अपने लिए सरकारी आवास ही नहीं लिया। जब नए मुख्यमंत्री के लिए सरकारी आवास खोजा जा रहा था तब यह पता चला कि नवीन बाबू 24 साल तक अपने निजी 'नवीन भवन' से ही सरकार का संचालन करते रहे। उन्होंने अपने लिए सरकारी आवास लिया ही नहीं। आज के नेता तो सरकारी आवास पर कब्जा जमाए रखने के लिए क्या क्या नहीं कर गुजरते। सियासत के गलियारों में अनेक रोचक किस्से कहे सुने जाते हैं। सही भी है- कुछ भी हो जाए, सरकारी आवास मिल जाए। नए सीएम भी चौकीदार के बेटे हैं। वे पहली बार जब विधायक बने तो भुवनेश्वर में फुटपाथ पर ही सो गए। रात में कोई अज्ञात व्यक्ति उनका मोबाइल चुरा ले गया। यह घटना जानकर फिलहाल कहा जा सकता है कि ओडिशा में सत्ता का हस्तांतरण सही हाथों में हुआ है।

आज के जमाने में भाई भाई में प्रेम के उदाहरण दुर्लभ हैं। कभी वैचारिक मतभेद तो कभी जायदाद का मोह भाइयों में दुश्मनी का कारण बनते हैं। विजयवाड़ा में भ्रातृ प्रेम का ऐसा उदाहरण मिला कि उपस्थित लोग भावुक हो उठे। अवसर था आंध्र के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह का। शपथ नायडू ने ली लेकिन वहां चर्चा दो लोगों की हो रही थी। एक- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और दूसरे थे जनसेना के मुखिया एवं आंध्र के नए डिप्टी सीएम पवन कल्याण। नायडू के साथ जनसेना प्रमुख ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। सबसे मिलने के क्रम में बड़े भाई चिरंजीवी के पास पहुंचे तो झुक कर पैर छू लिए। चिरंजीवी ने भी भावुक होकर पवन को गले से लगा लिया। सियासी मतभेदों के कारण पवन कल्याण की बड़े भाई चिरंजीवी से बनती नहीं है। विजयवाड़ा के मंच पर पता चला कि दोनों भाइयों मतभेद हैं मनभेद नहीं। तभी तो दोनों इतनी आत्मीयता से मिले कि लोग भी हैरत में पड़ गए। दोनों भाई तमिल फिल्मों के सुपर स्टार हैं इसलिए भी प्रशंसकों की नजरें उन पर टिकी रहती हैं। भाजपा ने इस बार नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी और तेलुगु स्टार पवन कल्याण की जन सेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। इस गठबंधन ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ-साथ लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। आंध्र विधानसभा की कुल 175 सीटों में से 164 सीटें उन्हें मिलीं, जिनमें टीडीपी की 135 सीटें, जन सेना की 21 और भाजपा की 8 सीटें शामिल हैं। आंध्र से लोकसभा की 25 में से 21 सीटें गठबंधन ने जीतीं और मौजूदा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। नीतीश ना विजयवाड़ा पहुंचे और ना भुवनेश्वर। उनका शपथ समारोह में नहीं पहुंचना खासी चर्चा का विषय बना रहा। जेडीयू नेता को लेकर यही संशय बना रहता है कि कहीं कोई नाराजगी तो नहीं। राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट पहले से ही थी कि नीतीश बाबू मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जेडीयू के कोटे से तीन मंत्री चाहते हैं- बने दो। ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। दिन गुजरते जा रहे। धड़कनें बढ़ती जा रहीं। बिहार को स्पेशल पैकेज पर मोदी ना हां बोले और ना ना। नतीजतन कयासों में शंका कुशंकाएं मुखर होती रहती हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

मनुष्य जीवन की संघर्षमय गाथा है इस जगत में?

मनुष्य का जीवन कई कई राहों से गुजरते अनुभव करता जाता है। दुख से पाला पड़ता रहता है। समस्याओं और उलझन ओके जाल में उलझाता है। किसी को सब कुछ प्राप्त कर आता है और किसी को कुछ भी नहीं देता है यही तो जीवन है जिसमें सब कोई जीते हैं इस जगत में। इस आधुनिक काल में मनुष्य सुख सुविधाओं से जीना चाहता है। लेकिन जीने के लिए उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक नहीं अनेकों ऐसी बातें हैं, जो आदमी के जीवन में लगी होती हैं और आदमी उससे से निजात पाने के लिए हर दम लगा रहता। इस प्रयास में उसे सफलता तो मिलती है, लेकिन बड़ी ही कठिनाई से और जीना तो कठिनाइयों के बीच ही होता है। इसलिए हर आदमी अपने अपने जीवन के संघर्षों में जी रहा है।यह भी कि अनेक कठिनाईया आमआदमी को सुख से जीने नहीं देती और सरकारी व्यवस्था उसकी कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल लेता है।आदमी आज हर तरह के तरह तर्दुद करने पर आमदा है और देश के लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए वे समस्या निदान की दिशा तलाशने के बजाय, जिन्हे देश की जनता की बेहतरी के लिए देश की सत्ता सौंपी जाती है। वे सत्ता संचालन कर्ता अपने ही चाल में मशगूल दिखते हैं। अपनी पार्टी और अपने हित की बातें ही उन्हें समय नहीं दे पाती कि वो कुछ और कर सकें, उन्हें तो बस किसी तरह इस देश की सत्ता पर काबिज होकर अपने लिये सुख-सुविधाओं से जीवन जीने की ख्वाहिश रहती है। वे दूसरे के जीवन की कठिनाइयों को तरजीह देकर अपनी कठिनाइयों को बढ़ाना नहीं चाहते। राजसत्ता पर बैठने के लिए पार्टियां जिस तरह के चुनावी तमाशा दिखाती हैं वह निश्चित रूप से लोकतंत्र के इस देश के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती। देश की आजादी के बाद इस देश के लोगों को स्वतंत्रता के साथ सुखमय जीवन जीने के लिए जो संक्लप लिये गये उसे पूरा करने के लिए जो कुछ लोग तब सता में आये, उन्होंने अपनी पूरी कर्तव्यनिष्ठा निभाई त्याग कोअपना समंवल बनाया। लेकिन लोकतंत्र में वोट की राजनीति का जो समावेश हुआ, तो फिर लोकतंत्र में जो भी सत्ता संचालन के लिए अपने अपने दल के बलबूते सता की प्राप्ति में लगे वे अपने ही ढंग से सत्ता के संचालन को अपने अनुरूप बनाया। उनमें त्याग, सद्भाव, समभाव कहने भर को रही, लोग कहते है सत्ता संचालन के लिए त्याग और संभाव की बाते अब वेमानी सी दिखती है, क्योकि उनकी नजर में अपने के बाद, अपनो और फिर अपना समाज ही सर्वोपरी होता है, उसके बाद ही फिर और कुछ। देशवासियों को रोटी कपड़ा और मकान के साथ जीने की सुविधाएं मुहैया कराने की जिन पर जिम्मेवारी है, केंद्र से लेकर राज्य तक में अपनी अपनी चाल ही मजबूत करते दिखते हैं।?उन्हें आम लोगों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें जनता से मिलने वाले हर तरह के टैक्स से जो सुख सुविधा मिलती है, उसमें वे मस्त और व्यस्त रहते हैं।जनता पर टैक्स का भारी बोझ जनता को ही उठाना और सहना पड़ता है, ना चाह कर भी उसे हर चीज के लिए, हर जगह टैक्स का भुगतान करना होता है। चाहे वह जिस काम को भी करें उसमें उसे एक टैक्स देना पड़ता है। एक आदमी अपने जीवन में जो कमाई करता है, टैक्स के रूप में भुगतान करता रहता है।उसी के टैक्स के बलबूते सत्ता संचालन करने वाले लोग मौज मस्ती काटते हैं, उन्हें हर तरह की सुविधाएं, आम लोगों की लोगों के द्वारा भुगतान किये गये टैक्स से ही मिलता है। इसके उलट यहां रोजगार की जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हो रही, रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन यह किया जा रहा है कि तर्ज पर चल रहा है बावजूद इसके कि आम आदमी को एक नहीं अनेकों ऐसे समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जो उसके जीवन को कठिन से कठिन बनाता जा रहा है। मनुष्य को तो जीना ही पड़ता है और जीना कठिन हो या सरल आदमी के बस की बात तो होती ही नहीं वह तो करने वाले यानी जीने वाले की बस की बात होती है इस तरह भी जीना है जीना तो है ना इसलिए लाख मजबूरियों के बावजूद आदमी को जीना पड़ता है और आदमी जी रहा है। इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए धर्म और कर्म का सहारा लेना होता है। यही इस जीवन की गाथा है।

प्रभात वर्मा

पतंजलि का योग

ब्रह्मचर्य के आचरण से हर प्रकार की जिम्मेदारियां निभाने का समर्थ पैदा होता है

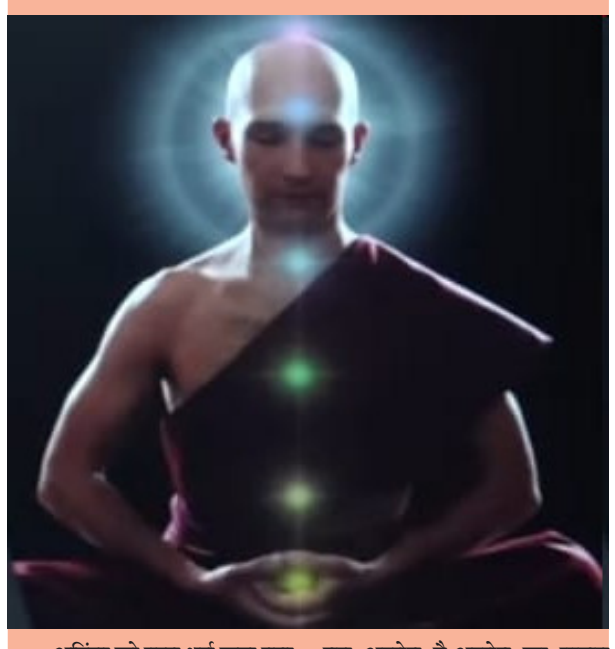

अहिंसा को परम धर्म कहा गया है.हिंसा के आगे 'अ' उपसर्ग लगा होने से अहिंसा को मनाही या निषेधात्मक माना जाता है. जबकि व्यापक अर्थो में सेवा, सहायता, सुश्रुषा सहयोग, करुणा, दया, अभय, सांत्वना, आदि भी अहिंसा हैं. ये सभी अहिंसा के विधेयात्मक रूप हैं. यह अहिंसा परम सत्ता के साथ एकात्मता का प्रतिफल होती है. इसी अहिंसा की प्रतिष्ठा के सन्निद्ध से वैर त्याग की उक्ति चरितार्थ होती है.सत्य में प्रतिष्ठित होने से बिना किये भी क्रिया फल के आश्रयत्व प्राप्ति सम्भव है. (योग सूत्र 2/36) यानि सत्य का आचरण करने वाले की इच्छा मात्र से अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं.भारत में महात्माओं के आशीर्वाद या भले लोगों की दुआएं इसी कारण फलीभूत हुईं. जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है.तीसरा यम अस्तेय है.अस्तेय का पालन करने वाले को जरूरत के अनुसार साधन उपलब्ध हो जाते हैं. भले ही वे हीरे जवाहरात की कीमत के ही क्यों न हों.अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न उपस्थानमह्न ब्रह्मचर्य के आचरण से हर प्रकार की जिम्मेदारी पूर्ण करने की सामर्थ्य पैदा होती है. वैज्ञानिक खोजों से भी सिद्ध हुआ है कि ब्रह्मचारी के रक्त में कई प्रकार की क्षमताएं बढ़ाने वाला स्पर्मायडिन नामक क्रिस्टल अधिक मात्रा में पाया जाता है.यह क्रिस्टल या हार्मोन व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है.अपरिग्रह के पालन से स्मृति तीक्ष्ण होती है. यहाँ तक कि विगत जन्मों की याद भी आ सकती है.आगे घटने वाली परिस्थितियों का आभास हो सकता है.अगले जन्मों का ज्ञान होना भी सम्भव है. **क्रमशः..**

दस्तक प्रभात/

खोज परक यथार्थ

लोकगाथाओं की उत्पत्ति

भावनाएँ जब मचलती हैं, संभावनाएँ जब कुछ बुनती हैं, संवेदनाएँ जक ताना-भरनी देने को तैयार हो जाती है, प्रेम, पौरुष, आह और आँसू भी कुछ व्यक्त करने लग जाते हैं, प्रकृति का सौंदर्य तब और बिखरने लग जाता है, तब कविता और गीत को पंख लग जाता है और कवि और गायक संभावनाओं के साथ धरती को परखने और आकाश को नापने तक भाव भरे गीत, पौरुष से भरी कविता और बौद्धिक गद्य लेखन भी होने लग जाता है। कभी ऊँचे पर्वत के मुड़ेरे से गीत का अलाप होने लगता है तो कभी नदियों के कछार पर बैठा कवि और गायक चंचल धाराओं से लय और धुन सीखने लग जाता है।

जब हरे-जीवित बाँस के घर्षण से अग्निं पैदा हो सकती है जब सूखे बांस की बासुरी से मधुर धुन निकल सकती है तो क्यों नहीं जिज्ञासु-भावुक मन के तान से गीत और संगीत पैदा हो सकता है।कलम और स्याही जिसने स्पर्श नहीं किया वह महान् कवि हुआ। कवि और गायक के कंठ में जब सरस्वती बस जाती है तो कलम और स्याही के बिना भी गाथा जन-मानस के साथ अपनंत्व पैदा कर लेती है। पता नहीं कब से गाथा लिखने और गाने की परंपरा चली है। साहित्य से जुड़ने वाला सामान्य व्यक्ति भी पहले गीत और कविता ही लिखता है, तो स्वाभाविक है, गाथा जो गीत है लेकिन है कहानी। कहानी में कहने वाला होता है तो सुनने वाला भी होता है। कहानी, गाथा, कथा एक नहीं है लेकिन सबके साथ जुड़ाव है, अपनत्व है।नदियों का वीरों का उद्गम खोजना सदा कठिन रहा है, इसी प्रकार यह खोजना गाथाओं का जन्म कैसे हुआ और गाथाओं का रचयिता कौन हुआ। आदमी जिज्ञासु प्राणी है इस कारण खोज का काम सदा होता रहा है और आज भी हो रहा है।जब-जब राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना कमजोर पड़ती है तब-तब कभी ज्ञात तो कई बार अज्ञात कवि-लेखक और संत भावों को जागृत करने का अलख जगाते हैं और यह क्रम हमेशा से जारी है।शिष्ट साहित्य में लेखन हुआ है इस कारण इसके ज्ञात रचयिता का नाम जाना जा रहा है लेकिन गाथा तो कंठ में सुरक्षित रही है इस कारण इसके खास रचयिता के नाम सामने नहीं है, लेकिन जो गीत का, कविता का मापदण्ड माना जाता है उसके अनुसार किसी न किसी ने संवेदना के कारण संभावनाओं के तहत गाया होगा। वह गाने के साथ कथा भी सामने आ गयी होगी तभी तो स्वछन्द भाव के गीतों के गायकों के और उसके अनुसरण करने वालों की खोज सदियों से जारी है। विस्तारित गीतों को जिसके साथ जुड़ा है कोई कथा उसे ही लोकगाथा नाम से जाना जा रहा है। संसार के प्रायः भाषाओं में कोई न कोई गाथा है इस कारण इन गाथाओं की उत्पत्ति पर सिद्धान्त रखा गया है। लोकगाथाओं की उत्पत्ति पर पाँच सिद्धान्त विदेशी विद्वानों के हैं तो एक सिद्धान्त भारतीय विद्वान का है।1. ग्रिम का सिद्धान्तः 2. समुदायवाद ।2. श्लेगल का सिद्धान्तः व्यक्तिवाद।3. स्टेन्थल का सिद्धान्तः जातिवाद। 4. विशायपर्सी का सिद्धान्तः चारणवाद ।5. चाइल्ड का सिद्धान्तः व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद । 6. डॉ. कृष्ण देव उपाध्याय का सिद्धान्तः समन्वयवाद । उपरोक्त सभी सिद्धान्तों से स्पष्ट होता है कि गाथाओं की रचना, गायन और परंपरागत तरीके से विकास में उपर्युक्त सभी व्यक्ति या समुदाय की भागीदारी है। भारत में तो वैदिक साहित्य काल से ही गाथाओं का प्रचलन है और बाद में बहुत दिनों तक कंठों में सुरक्षित रहने के बाद लिखित साहित्य का हिस्सा बना है। समाज के विकास के साथ लिखित साहित्य का आकार चाहे चार वेदों के रूप में या रामायण और महाभारत जैसे काव्यों के रूप में सामने है। गाथाओं की रचना में सबसे बड़ी भूमिका व्यक्ति की होती है इसके बाद समाज की होती है लेकिन दोनों के बिना मिले यह संभव नहीं है। गाथाओं के वर्गीकरण-देशी और विदेशी विद्वानों ने लोकगाथा, गीतों को विभिन्न वर्गों में रखकर वर्गीकरण किया है। प्रो० गुमर ने लोकगाथा गीतों को छः वर्गों में विभाजित कियाः 1. प्राचीनतम गाथाएँ 2. पारिवारिक या कौटुंबिक 3. शोकपूर्ण एवं अलौकिक 4. पौराणिक 5. सीमांत 5. 6.अरण्यक । पश्चिमी देशों के विद्वानों ने लोकगाथाओं के चार प्रकार बताए हैं:1.परंपरागत2.चारण द्वारा प्रस्तुत 3.प्रकाशित 4. साहित्यिक ।डॉ. बलदेव उपाध्याय ने तीन वर्गों में बाँटा है:1.प्रेम कथात्मक 2.वीर कथात्मक 3.रोमांचक कथात्मक 4.विषयवस्तु की दृष्टि से बलदेव उपाध्याय का वर्गीकरण विचारणीय है लेकिन किसी भी लोकगाथा में आदि से अन्त तक एक ही प्रवृत्ति नहीं होती है, लोक जीवन की भाव-भंगिमा के अनुसार परिवर्तन भी होता है। वीरगाथा गीतों में प्रेम का भाव भी होता है। विजयी कुंवर मल के गाथा में एक तरफ प्रेम है तो दूसरी तरफ पौरुष की ललकार भी है। लोकगाथा के गायन परंपरा के अनुसार व्यक्ति अपने मन के भाव आत्मसुख के लिए गाता है। जाडे की रात बड़ी होती है तो नींद पूरी हो जाने के बाद जब तक सुबह नहीं होती तब तक सौरठी-बृजाभार, विजयमल और आल्हा के गीत प्रायः गाने का प्रचलन है। यह सभी गीत मन लगाने के लिए गाए जाते हैं। धार्मिक भावना के गीत कई बार समारोह और मेले के समय गाया जाता हैः ऐसे गीतों में गौरा बिआह (विवाह) श्रवण कुमार और राजा हरिश्चन्द्र के गाथा गीत है। कुछ गीत जैसे बिहुला विषहरी के गीत प्रायः सांप काटने और नाग पंचमी के समय बिहार में खासकर भागलपुर के आस-पास गाने का प्रचलन है। कई बार आत्म गौरव के लिए और जातीय गौरव के लिए भी गीत गाया जाता है। लोरिकायन यादव जाति के लोग विशेष मौके पर और सेवक राम के गीत सात पिण्डी के पूजन के अवसर पर गाते हैं तो रेशमा चुहड़मल के गीत जातीय गौरव के प्रतीक मानकर दुसाध जाति के लोग गाते हैं। इसी प्रकार कई व्यापारी जाति के लोग भी गीत गाते हैं। गायकों की परंपरा-गाथा गायकों की परंपरा में शौकिया गायकों का अलग महत्व है। ये गायक स्वान्तः सुखाय के भाव से गाते हैं। गायक कई बार अकेले गाते हैं तो कई बार एक में अधिक व्यक्ति गाते हैं। वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में चौहट का गायन या चैता के गायन समूह के रूप में गाते हैं। गाथा गायन परंपरा में गीत के साथ कथा भी कही जाती है। वातार्लाप शैली का उपयोग होता है। शौकिया गायक बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीय गीत गाते हैं तो मध्य प्रदेश में पांडवानी गीत गाने वालों की संख्या है। कंवर जाति के लोग पंडवानी को शौकिया रूप में अपना लेते हैं। पंडवानी गाथा तो देश-विदेश में श्रवण किया जाता है। शौकिया गायन करने वालों के अतिरिक्त उत्तर भारत में प्राचीन काल से छः प्रकार की गाथा गाने वाले लोग हैं जिसके कारण गाथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पायी है। (1) मागध-ये लोग मगध के मूल निवासी है और मधुर गीत गाने में महारथ हासिल है। इनकी जाति के सम्बध में भ्रामक बातें हैं लेकिन इन मागधों ने शिष्ट साहित्य खासकर वैदिक साहित्य का प्रचार और व्याख्या प्रस्तुत की है। राजा पृथु की प्रशंसा में गाए गीतों से प्रसन्न होकर राजा पृथु ने मगध देश का राज्य प्रदान किया था। ये शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य के जानकार माने जाते हैं। (2) सूत-क्षत्रीय से ब्राह्मणी स्त्री द्वारा उत्पन्न हुआ व्यक्ति जिसका पेशा रथ संचालन अथवा वंदना करना होता है सूत माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध का आँखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाने वाले संजय सूत ही थे। (3) बन्दी-शुद्ध बुद्धिवाले, समय और प्रकरण के अनुकूल गीत गाने वाले, राजाओं की स्तुति करने वाले बन्दी कहे जाते हैं। (4) कुशीलव-महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जन्म लेने वाले लव और कुश ने रामायण पाठ को कंठस्थ कर लिया था। दोनों भाई गाकर ऋषियों को रामायण की घटनाओं के साथ सीता जी की परित्यकता जीवन पर भी गायन करते हैं। रामायण का गायन करने वाले लव और कुश तो पिता राम जी के साथ अयोध्या गए लेकिन उनकी परंपरा को जीवित रखने वाले लोग कुशीलव के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर रामायण का पाठ करने पर ब्राह्मणों के द्वारा रोक होने के बाद भी उत्तर रामायण का गायन कायम हैं। लव और कुश के जैसा भेष बनाकर वीणा के साथ गीत और संगीत का गायन होता है।(5) वैतालिक-राजाओं को प्रातः काल गीत गाकर जगाने वाले को वैतालिक कहा जाता है। ये लोग भैरव राग से राजाओं का यशोगान करते हैं। इस ढंग के गाने वाले मध्य युग में पाए जाते रहे हैं।(6) चारण-चारण भी कुशीलव की परंपरा के होते हैं। इनका कार्य नृत्य तथा राजा के ऐश्वर्य का गुणगान करना होता है। हिन्दी साहित्य का आदि युग इन्हीं चारणों का युग है। पृथ्वीराज के दरबारी कवि परममित्र चन्दबरदाई चारण ही था। ये लोग युद्ध क्षेत्र में जाते थे और योद्धाओं को ललकारते थे।उपरोक्त गाथा गायकों के जैसा योगी और भाट भी गाते रहे हैं लेकिन प्राचीन साहित्य के ये दो नाम नहीं है। गाथा गाने वालों की परंपरा में "वसदेवा" जाति का नाम भी महत्वपूर्ण है। ये लोग मूलतः वैष्णव गायक होते हैं। वसदेवा अपना संबंध कृष्ण के पिता वासुदेव से जोड़ते हैं।वैष्णव भक्ति गीतों के गायन में वसदेवा जाति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग भ्रमणशील भी होते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और मिजार्पुर आदि क्षेत्रों के मूल निवासी हैं।

दस्तक प्रभात
राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर

विश्व रक्तदाता दिवस

रक्तदान करने से आत्मिक आनंद मिलता है

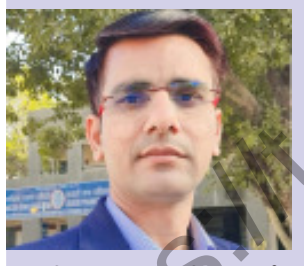

विश्व रक्तदाता दिवस शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की याद में पूरे विश्व में मनाया जाता है। महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। उन्होंने मानव रक्त में उपस्थित एग्ल्युटिनिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त कणों का ए, बी और ओ समूह की पहचान की थी। इसलिए एक दूसरे के जीवन बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 जून को रक्त दान दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन लोगों से रक्तदान करके जीवन बचाने का आग्रह करता है और सभी लोगों को रक्तदान करने में सक्षम होने के लिए मूल बातों के बारे में बताया जाता है। जो की बहुत ही आवश्यक है। रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारे पूरे शरीर में विभिन्न कार्यों का संचालन करता है। जब व्यक्ति अत्यधिक रक्त को खो देता है तो उसे किसी भारी स्रोत से रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में रक्तदान अहम भूमिका निभाता है बीमार लोगों की मदद करने के लिए आप जो सबसे नेक काम कर सकते हैं। वह रक्तदान प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से रक्त लिया जाता है और दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है रक्तदान करने का मुख्य कारण किसी की जान बचाना है। रक्त की आवश्यकताः हर साल हमारे देश में 5 यूनिट करोड़ रक्त की आवश्यकता होती है जिसमें से केवल 2.5 करोड़ यूनिट रक्त उपलब्ध होता है। इससे भी बदतर स्थिति यह है कि लगभग 8 मुख रक्त प्रकार हैं। यह संकेत देता है कि सही समय पर सही प्रकार का रक्त उपलब्ध होना चाहिए और भारत जैसे विकासशील देश में यह है संभव नहीं है। इसलिए लोगों के जीवन को बचाने के लिए स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1997 से 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस मुहिम के पीछे मकसद विश्व भर में रक्तदान की अहमियत को समझाना था लेकिन भारत में इस मुहिम को इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए। रक्त को एकत्रित करने का एकमात्र उपाय रक्तदान है। रक्तदान कौन कर सकता हैः लोगों को यह धारणा है कि रक्तदान से कमजोरी आती है यह पूरी तरह बेबुनियाद है। ऐसा प्रत्येक पुरुष अथवा महिला जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो, जिसका वजन 100 पॉन्ड या 48 किलो से अधिक हो, जो क्षय रोग, रतिरोग, पीलिया, मलेरिया, मधुमेह, एड्स आदि बीमारियों से पीड़ित नहीं हो, जिसने पिछले तीन माह से रक्तदान नहीं किया हो, रक्तदाता ने शराब अथवा कोई नशीली दवा नहीं ली हो, गर्भावस्था तथा पूर्ण अवधि के प्रसव के पश्चात शिशु को दूध पिलाने की 6 माह की अवधि में किसी स्त्री से रक्तदान स्वीकार नहीं किया जाता है। एक बार में कितना रक्तदान कर सकते हैं : प्रतिदिन हमारे शरीर में पुराने रक्त का क्षय होता रहता है तथा प्रतिदिन नया रक्त बनता रहता है। एक बार में 350 मिलीलीटर (कुल रक्त का 20 वां भाग) जो शरीर 24 घंटे में दिए गए रक्त के तरल भाग के पूर्ति कर लेता है। रक्तदान से होने वाले फायदेः 1. रक्तदान के समय बजन, बी.पी. हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, मलेरिया, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वी.डी.आर.एल.की निशुल्क जांच हो जाती है।2. नियमित रक्तदान से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। 3. रक्तचाप सामान्य रहता है जिससे कैंसर जैसी घातक रोगों के होने का खतरा कम रहता है। 4. हृदयघात की संभावना में 90 प्रतिशत की कमी होती है। 5. नए ब्लड सेल बनते हैं। 6. मोटापा में कमी आती है। 7. लिवर स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। 8. कोलेस्ट्रोल का लेवल कम होता है। 9. रिसर्च में पाया गया है कि ब्लड डोनेट करने से खुशी मिलती है और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। 10. आध्यात्मिक आनंद और आंतरिक शांति मिलती है। रक्तदान कहाँ करें: रक्तदान किसी भी लाइसेंस युक्त ब्लड बैंक में किया जा सकता है। यह सुविधा सभी जिला चिकित्सालयों में भी उपलब्ध है। मान्यता प्राप्त प्राइवेट ब्लड बैंक को, रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं, संगठनों के माध्यम से समय-समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। जहां स्वैच्छा से निश्चिंत होकर रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करके किसी को नवजीवन देकर जो आत्मिक आनंद मिलता है उसका ना कोई मूल्य आंका जा सकता है और नहीं उसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। चिकित्सकों का यह मानना है कि रक्तदान खून में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता रक्त प्रभाव में बाधा डालती है। रक्तदान शरीर द्वारा रक्त बनाने की क्रिया को भी तीव्र कर देता है। रक्त के कणों का जीवन सिर्फ 90 से 120 दिन तक का होता है। प्रतिदिन हमारे शरीर में पुराने रक्त का क्षय होता रहता है और नया रक्त बनता जाता है बहुत से स्त्री पुरुषों ने नियमित रूप से रक्तदान करने का क्रम बना रखा है। अतः सभी को नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए जिससे रक्त की हमेशा उपलब्धता बनी रहे। कोई सुहागिन विधवा नहीं बने, कोई वृद्ध मां-बाप बेसहार नहीं हो, खिलता यौवन काल कल्वित नहीं हो। आज किसी को आपके रक्त की आवश्यकता है, हो सकता है कल आपको किसी के रक्त की आवश्यकता हो, इसलिए निडर होकर स्वैच्छिक रक्तदान करें। दूसरों के दर्द को जो महसूस करता है, वही तो सच्चा इंसान है। रक्तदान वही कर सकता है, जो दिल का महान है। आप भी रक्तदान करके मानवता का फर्ज निभाओ, रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत पाओं।

दस्तक प्रभात
मदन मोहन भास्कर

कविता

अब बरस भी जाओ

बादल भैया, बादल भैया,
क्यों हो गए हो हमसे नाराज,
गरमी सही नहीं जाती भैया,
अब बरस भी जाओ आज।
जिधर देखो सूखा पड़ा है,
जनजीवन हाहाकार मचा है,
पेड़ पौधे सूखे हैं पत्ते डाल,
कब बरसोगे, है हाल बेहाल।
माना सूरज संग रहते हो,
हर पल साथ निभाते हो,
एक नजर हमको भी देखो रे,
धरती की प्यास बुझाओ रे ।
माना पर्यावरण हमने बिगाड़ा,
समझ न आए,
कहाँ ढूँढे सहारा,
हाथ जोड़ अब तुम्हे पुकारा,
सदा विपदा से
तुमने ही उबारा।
बादल भैया गुस्सा त्यागो,
गर्मी से राहत हमें दिलवाओ,
वादा करते हैं हम आज,
सरंक्षण के सदा करेंगे काज।
बस, अब बरस भी जाओ,
और न अब हमें तरसाओ,
उमड़ घुमड़
नभ पर छा जाओ,
जनजीवन सुकून भर जाओ।

दस्तक प्रभात/नीरजा शर्मा

कविता

'टूटन'

कुछ सपने अब टूट रहे हैं...
अपनों के संग छूट रहे हैं।
सफल राह की उम्मीदों में,
गाँव गली सब दूर हुए हैं।
कुछ सपने अब टूट रहे हैं...
पक्की सड़कों की उम्मीदें,
सपने सच करती ताकीदें,
परिवारों से छूट परिंदे-
शहरी पिंजरों में
सिसक रहे हैं।
कुछ सपने अब टूट रहे हैं...
जीवन तो बस यंत्र बना है,
आधुनिकता को ओढ़ चला है।
पश्चिमीकरण की
आग में झुलसे!
रंग गुलाबी श्याम हुए हैं।
कुछ सपने अब टूट रहे हैं...
घर परिवारों से दूरी कर,
तन्हाई को जीता यौवन!
हसरतें कमजोर पड़ गईं,
जो चाहा वह कहाँ बने हैं!
कुछ सपने अब टूट रहे हैं,
अपनों के संग छूट रहे...।

दस्तक प्रभात
डॉ शैली जग्गी

कविता

प्यार का पहला खत

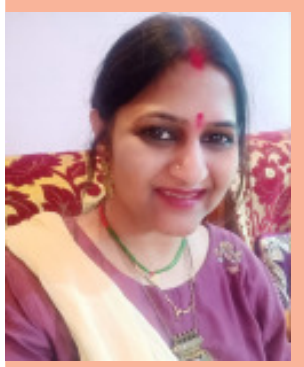

ना लिख सके कोई खत .....
जब - जब मैंने कलम उठाई,
याद आई कैरियर और पढ़ाई।
मात-पिता की होगी जग हँसाई,
समाज में भी
होगी बड़ी रुसवाई....
उनका मुझ पर बहुत भरोसा,
सपनों को नहीं
देना धोखा ऐसा।
जब भी दिल ने
दिल को भटकाया,
खुद को उनके
सपनों में मैंने पाया....
दिन - रात मुझे
मेहनत करना है,
अपने अरमानों
को पंख देना है, ।
नहीं यह नहीं है
कोई सही घड़ी,
प्यार के लिए
अभी जिंदगी पड़ी.....
प्यार का पहला
खत लिखने को
जब - जब मैंने कलम उठाई।
हर बार दिल से
इक आवाज आई,
हमारी अधूरी कहानी
फिर कभी.....।।

दस्तक प्रभात/शैलजा गुप्ता

https://epaper.dastakprabhat.com

भयानक गर्मी

विभीषिका का कारण

भयानक गर्मी और जल संकट उत्तर भारत में अनेक लोगों की जान ले चुका है और इससे राहत की उम्मीद अभी नहीं है। भयानक गर्मी और पानी की कमी से बहुत लोगों की जान चली गई है। भारत के उत्तरी हिस्सों तथा राजधानी में इसकी विभीषिका का संकट बना हुआ है। अत्यधिक गर्मी, लू तथा बरसात कम होने से मौसम बहुत खराब है। लाखों लोगों के लिए यह स्थिति असहनीय है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तथा पानी की सप्लाई बहुत कम हो गई है। उत्तर भारत अब तक के ज्ञात इतिहास में सबसे भयानक लू का सामना कर रहा है। अनेक स्थानों पर तापमान नियमित रूप से 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है और कई जगह इससे बहुत अधिक हो गया है। ऐसे में लू लगने, निर्जलीकरण तथा गर्मी संबंधी अन्य बीमारियां फैल रही हैं। संकटग्रस्त लोगों, खासकर छोटे बच्चों और वृद्धों के लिए खतरा और बढ़ गया है। अस्पतालों में भी गर्मी के शिकार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि स्वास्थ्यरक्षा संसाधन सीमित हैं। इन समस्याओं की गंभीरता इसलिए बढ़ रही है कि मानसून की गति असामान्य रूप से धीमी है। आमतौर से गर्मी से राहत दिलाने वाली बरसात अनियमित है तथा उसमें देर हो रही है। इस विलंब के शहरी और ग्रामीण समुदायों पर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में बरसात की कमी गर्मी को बहुत दु:खदायी तथा जीवन स्थितियों को लगभग असहनीय बना देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून में देरी कृषि के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है क्योंकि यह अधिकांशत: समय पर बरसात पर निर्भर है। फसलें खराब होने या उपज घटने से खाद्य सुरक्षा तथा लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। उत्तर भारत में लू तथा मानसून में विलंब के कारण गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। इसके कारण प्रमुख नदियों और जल भंडारों में जल का स्तर खतरनाक रूप से घटा है तथा भूमिगत जल स्तर भी गिरा है।

दिल्ली की जल सप्लाई ऐतिहासिक रूप से यमुना का जल स्तर गिरने से प्रभावित हुई है और वास्तव में कुछ क्षेत्रों को दिन में कुछ ही घंटे पानी मिल रहा है। इससे जलजनित रोगों का खतरा भी बढ़ गया है, पानी तक पहुंच के लिए विवाद हुए हैं तथा अनेक लोगों को प्रदूषित जल पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं जिनमें पानी की राशनिंग, शीतलन सुविधाओं की स्थापना तथा समुदायों को पेयजल का वितरण शामिल हैं। लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इन कदमों के ज्यादा सफल होने की संभावना नहीं है। विभीषिकाओं की संभावना को देखते हुए दीर्घकालीन उपाय जरूरी हैं। इसके लिए जल संरक्षण हेतु ढांचागत संरचनाओं, प्रभावी सिंचाई व्यवस्थाओं तथा वर्षा जल संचयन में निवेश के साथ ही भूमिगत जल संसाधन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा ताकि उनका टिकाऊ प्रयोग हो सके। शहरी 'हीट आईलैंड' प्रभाव से निपटने के लिए शहरी नियोजन में हरित स्थलों तथा शीतलन रणनीतियों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों पर लोगों की जानकारी बढ़ाने से एक मजबूत संस्कृति विकसित करने में सहायता मिल सकती है। लाखों लोगों पर जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी और जल संकट का दुष्प्रभाव खासकर उत्तर भारत में पड़ रहा है। हालांकि, लोग अपनी सामूहिक शक्ति और परस्पर सहायता से जलवायु संकट से निपट सकते हैं। भारत की जनता मानवीय और पर्यावरणीय संकट से निपटने में अपनी शक्ति दिखा रही है।

लोकरंजक नीतियों से बिजली संकट

बिजली संकट का कारण एटीएंडसी लॉस या बिजली चोरी तथा कुछ राज्यों में किसानों को दी जाने वाली बिजली का पैसा न मिलना है। यह समस्या लगभग पिछले 25 साल से बनी हुई है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों-डिस्काम को पुनर्जीवित करने तथा तकनीकी नुकसान घटाने के लिए 'पारेषण फाइनेंसिंग' जैसी एक 'अन्य' योजना बन रही है ताकि समुचित पूंजीगत खर्च जुटाया जा सके। डिस्काम बिजली सप्लाई और वितरण व्यवस्था के केन्द्र में हैं। इन पर अधिकांशत: राज्य सरकारों का नियंत्रण है। वे सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनियों-जेन्कोस, जैसे नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन-एनटीपीसी से बिजली खरीदते हैं। इसके अलावा वे निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों-स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों या आईपीपी से भी बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को सप्लाई करते हैं। तकनीकी नुकसान या एग्रीगेट टेक्निकल एंड कामर्शियल लासेज़-एटीएंडसी बिजली चोरी का दूसरा नाक है।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के अनुसार एटीएंडसी नुकसान 27 प्रतिशत हैं। इसका अर्थ है कि जब बिजली उत्पादक स्टेशनों से 100 यूनिट बिजली पारेषण और वितरण के लिए दी जाती है तो उसमें से 27 यूनिट की चोरी हो जाती है और उसका पैसा नहीं मिलता है। इस कारण डिस्काम के कामकाज पर विकलांगकारी प्रभाव पड़ता है। 27 यूनिट चोरी बिजली से कोई राजस्व 'नहीं' मिलने के कारण डिस्काम बाकी 73 यूनिटों पर ज्यादा पैसा ले सकते हैं। लेकिन यह भी एक सैद्धान्तिक स्थिति है। इस प्रकार डिस्काम को बिजली चोरी के कारण भारी घाटा होता है। एक अन्य कारण से भी उनको भारी नुकसान होता है। बिजली कानून, 2003 तथा उसके अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्काम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दरें इस आधार पर तय कर सकते हैं कि उसकी बिक्री से प्राप्त औसत राजस्व प्राप्ति-एआरआर, खरीद, पारेषण और वितरण की औसत लागत-एसीएस के बराबर हो।

राज्य सरकारों के एक और आदेश के अनुसार वे कुछ परिवारों से दिल्ली-पंजाब में 200-300 यूनिट तक उपभोग पर कोई पैसा नहीं ले सकते या दिल्ली में 201-400 यूनिट तक 800 रुपये की सब्सिडी देते हैं। इसके साथ ही वे पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली देते हैं।

डिस्काम इस प्रकार कम प्राप्ति के कारण हुए घाटे की पूर्ति उद्योगों और बिजनेसों को बढ़ी दरों पर बिजली सप्लाई से पूरी करते हैं, हालांकि इनके लिए भी यह दर 16 रुपये यूनिट से अधिक नहीं हो सकती है। यही मुख्य कारण है कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में भारतीय उत्पाद और सेवायें ज्यादा प्रतियोगी नहीं रह पाते हैं। हालांकि, राज्य इस घाटे के बड़े हिस्से की प्रतिपूर्ति का वादा करते हैं, पर इनमें से अधिकांश केवल आंशिक प्रतिपूर्ति करते हैं और इसमें भी काफी विलंब होता है। इसके कारण डिस्काम का घाटा और बढ़ता है। बिजली संकट का कारण एटीएंडसी लॉस तथा कुछ राज्यों में किसानों को दी जाने वाली बिजली का पैसा न मिलना है। यह समस्या लगभग पिछले 25 साल से बनी हुई है। वर्ष 2000 के प्रारंभ में केन्द्र ने डिस्काम की सहायता के लिए चार वित्तीय पुनर्गठन पैकेज-एफआरपी जारी किए थे। इनमें से 2002 व 2012 का उद्देश्य मुख्यत: उनके नुकसान को माफ करना था, जबकि नवंबर, 2015 में जारी तीसरे पैकेज यानी उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना-उदय का उद्देश्य डिस्काम की व्यवस्था सुधारन तथा वित्तीय सहायता के बदले कुछ मानक प्राप्त करना था। उदय के अंतर्गत डिस्काम के लगभग 400,000 करोड़ कर्ज को माफ किया गया था। इसमें से 75 प्रतिशत का भार राज्यों पर डाला गया था, जबकि बाकी के लिए उनको सस्ती ब्याज दरों पर बांड जारी करने का अधिकार मिला था। एफआरपी के बदले डिस्काम को एटीएंडसी लास को 2015-16 तक घटा कर 20.7 प्रतिशत तथा 2018-19 तक 15 प्रतिशत पर लाना था। इसके साथ ही उनको एसीएस-एपीआर अंतर घटा कर 2015-16 में प्रति यूनिट 0.59 तथा 2018-19 में 'शून्य' पर लाना था, लेकिन डिस्काम ऐसा करने में विफल रहे हैं।

2019-20 में उनका एटीएंडसी लास 18.9 प्रतिशत था, जबकि 2018-19 के लिए 15 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था। एसीएस-एपीआर अंतर 2019-20 में 0.42 प्रतिशत था, जबकि 2018-19 में इसका लक्ष्य 'शून्य' था। 2020-21 में इन सीमित सुधारों से भी एटीसी नुकसान 22.3 प्रतिशत तथा एसीएस-एआरआर अंतर 0.69 प्रति यूनिट था। इसके परिणामस्वरूप डिस्काम का घाटा 2015-16 में 52,000 करोड़ से घट कर एफआरपी के कारण 2017-18 में 17,000 करोड़ रुपये रह गया था। यह 2019-20 में बढ़ कर 30,000 करोड़ तथा 2020-21 में 58,000 करोड़ रुपये हो गया। इसके परिणामस्वरूप कुल कर्ज 2020-21 के अंत में 620,000 करोड़ रुपये हो गया।

इसके कारण केन्द्र को चौथा पैकेज जारी करना पड़ा जिसे 'रिफार्म लिंक्ड, रेजल्ट बेस्ड स्कीम फार डिस्ट्रीब्यूशन'-आरएलआरबीएसडी नाम दिया गया था। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में की थी। 300,000 करोड़ रुपये के इस पैकेज का उद्देश्य एटीएंडसी लासेज़ को घटा कर 12-15 प्रतिशत करने तथा धीरे-धीरे मार्च, 2025 तक एसीएस-एआरआर अंतर शून्य करना था। इसके लिए वितरण ढांचे का उच्चीकरण तथा क्षमता संवर्धन करना था ताकि बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके अंतर्गत 220 मिलियन परिवारों समेत पूरी बिजली सप्लाई श्रृंखला में अनिवार्य रूप से प्री-पेड व स्मार्ट मीटर लगाना शामिल था। केन्द्र द्वारा लगभग 100,000 के ग्रास बजटरी सपोर्ट-जीबीएस के साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन राज्य संचालित विशेष क्षेत्र कर्जदाताओं, जैसे पावर फाइनेस कार्पोरेशन-पीएफसी व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम-आरईसी को अपरिवर्तनीय राज्य सरकार गारंटी के रूप में शामिल किया गया था। डिस्काम को जारी फंड इस शर्त के आधार पर था कि वह पूर्व निर्धारित आधार का पालन करेगा तथा सुधारों के न्यूनतम बेंचमार्क लागू करने में सफल होगा। वित्तवर्ष 2021-22 में शुरू आरएलआरबीएसडी में लक्ष्य प्राप्ति की बात की गई थी जिनको 2018-19 में प्राप्त किया जाना था, पर अब उनको बढ़ा कर मार्च, 2025 तक कर दिया गया है। यह अपने आप में हास्यास्पद है। इसमें होने वाली प्रगति पर गौर करें। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, सरकार के अनुमान से 32 राज्यों व संघशासित क्षेत्रों के 57 डिस्काम ने यह योजना लागू कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-डीपीआर तैयार की हैं। संसद में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिसंबर, 2023 में कहा था, 'आज तक नुकसान घटाने के लिए 120,000 करोड़ रुपये की डीपीआर मंजूर की गई हैं तथा स्मार्ट मीटरिंग के लिए 130,000 करोड़ निर्धारित किया गया है।' लेकिन इसके बावजूद जनवरी, 2024 तक पीएफसी-आरईसी आधारित कुल कर्ज वितरण 16 राज्यों द्वारा 112,000 करोड़ तक पहुंचा था, जबकि इसके लिए निर्धारित धनराशि 133,000 करोड़ रुपये थी।

जहां तक सकल बजटीय समर्थन की बात है, केन्द्र द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में इसके लिए केवल 6,000 करोड़ रुपये जारी किए जबकि बजटीय आबंटन 12,000 करोड़ रुपये था। चीजें बहुत धीमी गति से चल रही हैं। यह इस तथ्य से भी पता चलता है कि '220 मिलियन परिवारों में स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्य की तुलना में अभी तक केवल 0.8 मिलियन मीटर ही लगाए जा सके हैं।' ऐसे में आश्चर्य होता है कि क्या आबंटित पैसे का प्रयोग डिस्काम केवल पहले हुए नुकसानों की भरपाई के लिए कर्ज पाटने में कर रहे हैं, जैसा कि उदय योजना के अंतर्गत हुआ था। अब इस योजना का समय 10 महीने में 31 मार्च, 2025 में समाप्त हो जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि इस योजना के लिए निर्धारित धन का प्रयोग लगातार बढ़ते डिस्काम कर्ज की अदायगी में न हो जाए।

इस प्रकार एक दुष्चक्र जारी है। यह समस्या केवल राजनीतिक है। चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी 'खैरातों' का वादा करती है जिसमें परिवारों को सस्ती या मुफ्त बिजली शामिल है। इसके कारण झुग्गी-झोपड़ियों में होने वाली बिजली चोरी को भी अनदेखा किया जा रहा है। इस प्रकार लोकरंजक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डिस्काम का प्रयोग 'बलि के बकरे' की तरह किया जा रहा है।

मोदी के तीसरे कार्यकाल में विदेश नीति

"उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका आने वाले दिनों में परीक्षण और तराशी जारी रहेगी।"

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

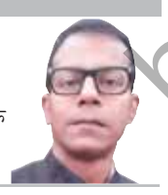

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह से भी कम समय में, श्री मोदी वापस अपने उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां वे जाने जाते हैं। वे इस सप्ताह इटली में थे, जहां उन्होंने जी-7 के नाम से जाने जाने वाले शक्तिशाली राष्ट्रों के समूह के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान अफ्रीकी और अरब देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें हुईं, साथ ही मुख्य रूप से अमेरिकी और यूरोपीय समूहों के नेताओं को कई स्पष्ट संदेश भी दिए गए।

तीसरी बार पदभार ग्रहण करने (अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि) के बाद, यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा थी, जहां लगभग 670 मिलियन मतदाताओं ने सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को चुनने के लिए लगभग दो महीने की अवधि में अत्यधिक कठोर गर्मी की धूप में धैर्यपूर्वक कतारों में प्रतीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी, महत्वाकांक्षी अपेक्षाएं रखने के बावजूद, अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुनाव-पूर्व गठबंधन राजनीतिक दलों के एक समूह पर निर्भर हैं। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है, जब यूरोप के कई हिस्से, अमेरिका का उल्लेख नहीं करना, अपने आप में लोकतांत्रिक मंथन का दौर चला रहे हैं। अमेरिका में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और दोनों पक्षों की आवाजें तीखी और तेज होती जा रही हैं।

इसी तरह, यूरोपीय संसद के चुनावों में दक्षिणपंथी दलों का फिर से उभार हुआ है, जिसका भू-राजनीतिक गतिशीलता पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ने की संभावना है। श्री मोदी को इस बात से राहत मिल सकती है कि पश्चिमी देशों को भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के बारे में बताते समय उन्हें सावधानीपूर्वक लिखे गए कूटनीतिक बयानों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। पिछले कुछ वर्षों में, पश्चिमी देशों और अमेरिका में भारतीय लोकतंत्र की सेहत, अल्पसंख्यक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस के अस्तित्व आदि पर इसके रिपोर्ट कार्ड के बारे में कई सवाल उठाए गए हैं। भारतीय मतदाताओं द्वारा लगभग बहुमत का फैसला, जिसमें सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन की गुंजाइश है, संसद में विपक्ष की मजबूत उपस्थिति प्रधानमंत्री और उनके राजनयिकों के लिए कई देशों के साथ बातचीत करते समय लोकतंत्र के लिए स्वर्ण मानक स्थापित करने के लिए एक स्पष्ट चर्चा का विषय होगी। राज्य और राष्ट्र के प्रमुख के रूप में अपने लगभग तीन दशकों के अनुभव के साथ, श्री मोदी कूटनीति के लिए नए नहीं हैं और आम चुनावों से पहले कई साक्षात्कारों में, उन्होंने भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाने के अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया है। जी20 के इर्द-गिर्द भव्य तमाशा (संयुक्त बयान पर पहुंचने के लिए गुप्त कूटनीतिक वार्ता को न भूलें), कई उच्च-स्तरीय राजकीय दौरे, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों और पड़ोसियों के लिए किए गए कई बचाव अभियान, कोविड के दौरान आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति, ये सभी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वैश्विक प्रतिष्ठा प्रबंधन पर दिए जाने वाले ध्यान की ओर इशारा करते हैं।

जी7 में प्रधानमंत्री की तीसरी बार की यात्रा निरंतरता का आश्वासन देती है और वर्तमान और संभावित सहयोगियों के साथ नई जुड़ाव रणनीतियों की खोज करती है, जिसमें निरंतरता और नवाचार पर जोर दिया जाता है। श्री मोदी की इटली यात्रा ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है, और गंभीर अनिच्छा के बावजूद, आक्रामक रूस के प्रति एकजुट यूरोपीय दृष्टिकोण में खामियां दिख रही हैं। उनमें से कई लोगों को, आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के युद्ध के बारे में भी ऐसी ही चिंता होगी, जो महीनों से कम होने से इनकार कर रही है। यह याद किया जा सकता है कि इजरायल और रूस दोनों ही भारत के करीबी सहयोगी हैं, और भारत ने इन दोनों अस्थिर स्थितियों पर टिप्पणी करते समय अब ??तक बहुत ही सावधानी बरती है। पिछले संबंधों की गतिशीलता, जबकि अमेरिका जैसे हाल के सहयोगियों के साथ गहरे संबंध बनाना एक संवेदनशील कूटनीतिक रूपक होने की संभावना है।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पीएम मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान हासिल की गई निरंतरता और विदेश नीति फोकस को बनाए रखने के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में एक अनुभवी राजनयिक एस जयशंकर को चुना है। उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका आने वाले दिनों में परीक्षण और तराशी जारी रहेगी।

आप की बात

दर्दनाक दुर्घटना

कुवैत के मंगाफ शहर की छहमंजिला इमारत में लगी आग से 45 श्रमिकों के मारे जाने के समाचार हृदयविदारक है, जिनमें अधिकांश भारतीय हैं। खाड़ी और अन्य देशों में जाने वाले भारतीय श्रमिक बहुत ही बुरे हालतों मैं अपना जीवन बिताते हैं। उनके आवास में रेलवे बर्थ की तरह पटिए लगाकर एक-एक कमरे में 20-20 मजदूरों को ठहराया जाता है। वे अधिकतर खेराती भोजन से अपना काम चलाते हैं और अपनी कमाई का अधिकांश पैसा देश में अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए भेजते हैं। भारतीय रुपए की विनिमय दर के चलते वे वहां 1000 से लेकर 3000 दिनार महीने मैं 16 घंटे कार्य करते हैं जो भारतीय मुद्रा में यहां 75,000 से 2,25,000 तक होता है इसीलिए बड़ी तदाद मे श्रमिक वहां जाते हैं। उन्हें खाडी देश में पर्यटक वीजा पर काम दिलाने वाली एजेंसीज भी भारी मुनाफ कमाती है और उनकी 1 साल की कमाई यह लोग हजम कर जाते हैं। अनेक महिला श्रमिकों का देह शोषण होता है। वहां के कानून के अनुसार पर्यटक वीजा पर आने वाले श्रमिकों को अवैध श्रमिक माना जाता है। इस दर्दनाक दुर्घटना को देखते हुए भारत सरकार को विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों को सरकारी या निजी एजेंसियों से अनुबंध के आधार पर भेजना चाहिए। इससे नियंत्रण बना रहेगा।

-सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

जी-7 सम्मेलन

जी-7 देशों का 50 वां शिखर सम्मलेन इटली के अपुलीया शहर में आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक के एजेंडे पर काम होना शुरू हो गया है। सातों सदस्य राष्ट्रों ने एकमत से निर्णय लिया है कि यूक्रेन की सहायता में जब्त की गई रूसी संपत्तियों से अरबों डॉलर जुटाए जांएगे। यह जी-7 की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अमेरिकी प्रस्ताव के मुताबिक यूक्रेन के लिए प्रति वर्ष 50 बिलियन डालर पश्चिमी देशों में रूस का 325 अरब डॉलर का जो जब्त सम्पति के ब्याज से दी जाएगी, ताकि रूस द्वारा नष्ट की गई आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण हो सके। पहली बार इसमें पोप प्रांसिस भी शामिल हो रहे हैं जो इन सात अमीर देशों को एआई द्वारा सम्पूर्ण मानवता पर खतरे की बात समझाना चाहते हैं। लेकिन शायद ही कोई देश उनकी बात पर गौर करे, हालांकि पोप का सम्मान करते हुए एआई जैसी तकनीकों पर कुछ नियंत्रण की चर्चा हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति को अमेरिका के साथ 10 वर्षीय सुरक्षा समझौता करने में सफ्लता मिली है। देखना होगा कि इस समझौते पर रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी तथा इससे विश्व राजनीति कैसे प्रभावित होगी। कहीं यह नए शीतयुद्ध का बीज न बो दे।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

सरकार से उम्मीदें

वर्तमान मोदी सरकार की क्षमता और कामकाज पर विपक्ष काफी भ्रम पैदा करने के प्रयास कर रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल के गठन तथा उसके बाद की घटनाओं से यह विपक्ष की कोरी-कल्पना अधिक लगती है। मोदी के पिछले दो कार्यकाल में सरकार ने बिना किसी दबाव के काम किया था। हालांकि, वर्तमान सरकार में गठबंधन सहयोगियों की संख्या थोड़ी अधिक है, पर भाजपा अपने संख्याबल के वर्चस्व से उनके आगे संभवत: झुकेगी नहीं। मोदी ने न केवल प्रमुख मंत्रालय पुराने वरिष्ठ मंत्रियों को देकर नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित की है, बल्कि प्रधानमंत्री के सचिव व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर पुराने लोगों को बनाए रख कर भी स्पष्ट संकेत दिए हैं। भले ही कुछ चुनावी वादे पूरे करना कठिन हो, पर राजग देश के विकास में तेजी लाने पर व्यापक सहमति विकसित करने में सफल होगा। यदि विपक्ष सकारात्मक रूप से मोदी सरकार की योजनाओं में राष्ट्रहित में सहयोग करे तो इससे देश-विदेश में उसकी भी प्रशंसा ही होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनता की जीवन सुगमता को बजट का मुख्य लक्ष्य बताया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार करदाताओं को राहत देगी।

- मनमोहन राजावत, शाजापुर

आतंकी घटनायें

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनायें बढ़ रही हैं। आतंकी आम नागरिकों व पुलिस तथा सेना के जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले से 9 निर्दोष श्रद्धालुओं की मौत के साथ ही सुरक्षा बलों व पुलिस पर हमले बढ़े हैं । पिछले कुछ वर्षों में हुए 2262 से अधिक आंतकी हमलों में 363 नागरिकों व 596 सेना व पुलिस के जवान शहीद हो गए। ठोस कदम उठाने के बाद भी ये आतंकी घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि चिन्ताजनक है। मारे गए आतंकियों के पास से मिले हथियारों व अन्य सामग्री से स्पष्ट है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाक से प्रशिक्षित आतंकियों के घुसपैठ के रास्तों को खोज कर घुसपैठ के पहले ही इनको ढेर किया जाना चाहिए। आतंकी जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में हुए भारी मतदान तथा आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इनके प्रति हमदर्दी रखने वाले भारतीयों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करने वालों को भी हाशिए पर धकेला जाना चाहिए।

-हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत

सम्पादकीय

संघ बड़ा या मोदी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में इशारों ही इशारों में नसीहतें दे दी हैं। उनका इशारा किस ओर था ये टिप्पणियों या नसीहत से ही पता चल जाता है। आरएसएस के एक कार्यक्रम में भागवत ने लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार की तरीके, हिन्दु-मुस्लिम कर धार्मिक उन्माद भड़काने या वोटों के ध्रुवीकरण, जातिगत भेदभाव, चुनाव के दौरान अमर्यादित आचरण सहित कई मसलों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। जिस तरीके से उन्होंने बार बार मर्यादित व्यवहार और अहंकार का उल्लेख किया उससे जाहिर है उन्हें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान भी नागवार गुजरा जो उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था। आरएसएस चीफ डॉ मोहन मधुकरराव भागवत ने संगठन के 'कार्यकर्ता विकास वर्ग-द्वितीय' के समापन कार्यक्रम में आरएसएस प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए ये तक कह दिया कि जो सच्चा सेवक होता है वह मर्यादित होता है और मर्यादा में अहंकार नहीं आता। भागवत ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि समाज ने अपना मत दे दिया और उसके अनुसार काम हो रहा है। संघ के लोग इसमें नहीं पड़ते, हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं। दरअसल, भागवत की ये तल्ख टिप्पणी उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी जो भाजपा अध्यक्ष जेपी नडडा की ओर से आई थी। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक साक्षात्कार में आरएसएस को पार्टी का वैचारिक मोर्चा करार दिया था। नड्डा ने ये भी कहा था कि पार्टी की संरचना मजबूत हो गई है, भाजपा अब अपने भरोसे ही चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त और वर्तमान की तुलना से जुड़े एक सवाल के जवाब में नड्डा ने कहा था कि वाजपेयी के समय पार्टी को खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत थी क्योंकि उस समय बीजेपी कम सक्षम और छोटी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन आज हम बढ़ गए हैं, पहले से अधिक सक्षम हैं। बीजेपी अब अपने आप को चलाती है। जेपी नड्डा ने कहा था कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन हैं जबकि भाजपा एक राजनीतिक दल है। हम अपने मामलों को अपने तरीके से संभालते हैं। संभवतः नड्डा का ये बयान भागवत को रास नहीं आया और उन्होंने अपने तरीके से इसका जवाब दिया। भागवत ने कहा कि चुनाव में स्पर्धा रहती है लेकिन इसमें भी मर्यादा रहती है। असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। भागवत ने दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। प्राथमिकता देकर उस पर विचार करना चाहिए। भारतीय समाज विविधतापूर्ण है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह एक समाज है और वे इसकी विविधता को स्वीकार भी करते हैं, सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और एक-दूसरे की उपासना पद्धति का सम्मान करना चाहिए। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या सहित अन्य धार्मिक स्थलों और देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में इस तरह के नतीजों की उम्मीद आरएसएस को भी नहीं थी। भागवत ने जिस तरह से कहा कि यह देश हमारा है और इस भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोग हमारे अपने हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अतीत को भूल जाना चाहिए और सभी को अपना मानना चाहिए।

पिता-पुत्र के संबंधों की संस्कृति को जीवंत बनाएं

हमारे ग्रन्थों में माता-पिता और गुरु तीनों को ही देवता माना गया है। इनकी सेवा और भक्ति में कसर रह जाए तो फिर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। और अगर हमने इनकी सेवा पूरे मन से की तो भगवान स्वयं कच्चे धागे से बंधे भक्त के पीछे-पीछे चल पड़ते हैं। आखिर श्रवण कुमार में ऐसा क्या खास था कि किसी भी भगवान से उनकी अहमियत कम नहीं है।

– ललित गर्ग –

किसी के भी जीवन में पिता की क्या भूमिका होती है, इसे शब्दों में बयां करने की भी जरूरत नहीं है। पिता हर संतान के लिए एक प्रेरणा हैं, एक प्रकाश हैं और संवेदनाओं के पुंज हैं। इसके महत्व को दर्शाने और पिता व पिता तुल्य व्यक्तियों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस यानी फादर्स डे मनाया जाता है। इस साल 16 जून 2024 को भारत समेत विश्वभर में यह दिवस मनाया जायेगा। फादर्स डे 2024 की थीम ''सेलिब्रेटिंग फादरहुड्ः स्ट्रेंथ, लव, एंड सैक्रिफाइस'' पर केंद्रित है यानी पितृ दिवस का जश्न- शक्ति, योगदान, प्रेम और बलिदान के प्रति सम्मान दर्शाने का एक विशेष अवसर है। दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग दिन और विविध परंपराओं के कारण उत्साह एवं उमंग से यह दिवस मनाया जाता है। हिन्दू परंपरा के मुताबिक पितृ दिवस भाद्रपद महीने की सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है। पिता एक ऐसा शब्द जिसके बिना किसी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसकी तुलना किसी और रिश्ते से नहीं हो सकती। हमारे ग्रन्थों में माता-पिता और गुरु तीनों को ही देवता माना गया है। इनकी सेवा और भक्ति में कसर रह जाए तो फिर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। और अगर हमने इनकी सेवा पूरे मन से की तो भगवान स्वयं कच्चे धागे से बंधे भक्त के पीछे-पीछे चल पड़ते हैं। आखिर श्रवण कुमार में ऐसा क्या खास था कि किसी भी भगवान से उनकी अहमियत कम नहीं है। माता-पिता की भक्ति और सेवा ने उसे भक्त प्रह्लाद और ध्रुव के बराबर का आसन दिलाया है। पिता चाहे कैसे भी वचन बोले, कैसा भी बर्ताव करे, संतान को उनके प्रति श्रद्धा और विनम्रता से आज्ञाकारी होना ही चाहिए। केवल इतना सूत्र भर साध लेने से हम उस ईश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं, जिसे पाने के लिए जाने कितने तपस्वियों ने शरीर गलाया, बरसों साधना की। कन्धे पर माता-पिता को लेकर तीर्थ कराने निकला श्रवण जब उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी भरते हुए राजा दशरथ का एक तीर लग जाने से प्राण त्यागता है, तब वह अन्तिम इच्छा में यही कहता है- 'मेरे माता-पिता प्यासे हैं, आप उन्हें जाकर पानी पिला दें।' प्राण त्यागते हुए भी जिसे अपने माता-पिता का ध्यान रहे, वह संतान उस युग में ही नहीं, इस युग में भी धन्य है। उसे किसी काल की परिधि में नहीं बांध सकते। मानवीय रिश्तों में दुनिया में सबसे बड़ा स्थान मां को दिया जाता है, लेकिन एक बच्चे को बड़ा और सभ्य बनाने में उसके पिता का योगदान कम करके नहीं आंका जा सकता। बच्चे को जब कोई खरोंच लग जाती है तो जितना दर्द एक मां महसूस करती है, वही दर्द एक पिता भी महसूस करते हैं। यह अलग बात है कि बेटे को चोट लगने पर मां पुचकार देती है, चोट लगी जगह पर फूंक की ठंडक देती है, वहीं पिता अपने बेटे की चोट पर व्यथित तो होता है लेकिन उसे बेटे के सामने मजबूत बने रहना है। ताकि बेटा उसे देख कर जीवन की समस्याओं से लड़ने का पाठ सीखे, सख्त एवं निडर बनकर जिंदगी की तकलीफों का सामना करने में सक्षम हो। माँ ममता का सागर है पर पिता उसका किनारा है।

माँ से ही बनता घर है पर पिता घर का सहारा है। माँ से स्वर्ग है माँ से बैकुंठ, माँ से ही चारों धाम है पर इन सब का द्वार तो पिता ही है। उन्हीं पिता के सम्मान में पितृ दिवस मनाया जाता है। आधुनिक समाज में पिता-पुत्र के संबंधों की संस्कृति को जीवंत बनाने की अपेक्षा है।

सोनेरा डोड जब नन्ही-सी थी, तभी उनकी मां का देहांत हो गया। पिता विलियम स्मार्ट ने सोनेरो के जीवन में मां की कमी नहीं महसूस होने दी और उसे मां का भी प्यार दिया। एक दिन यूं ही सोनेरा के दिल में ख्याल आया कि आखिर एक दिन पिता के नाम क्यों नहीं हो सकता? इस तरह 19 जून 1910 को पहली बार फादर्स डे मनाया गया। 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कोली ने फादर्स डे पर अपनी सहमति दी। फिर 1966 में राष्ट्रपति लिंडन जानसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की आधिकारिक घोषणा की। एक शिल्पकार प्रतिमा बनाने के लिए जैसे पत्थर को कहीं काटता है, कहीं छांटता है, कहीं तल को चिकना करता है, कहीं तराशता है तथा कहीं आवृत को अनावृत करता है, वैसे ही मेरे पूज्य पिताश्री रामस्वरूपजी गर्ग ने मेरे व्यक्तित्व को तराशकर उसे महनीय और सुघड़ रूप प्रदान किया। आज वे देह से विदेह होकर भी हर पल मेरे साथ प्रेरणा के रूप में, शक्ति के रूप में, संस्कार के रूप में रहते हैं। हर पिता अपने पुत्र की निषेधात्मक और दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करके नया जीवन प्रदान करता है। वरुण जल का देवता होता है। जैसे जल वस्त्र आदि के मैल को दूर करता है, वैसे ही पिता पुत्र की मानसिक कलुषता को दूर कर सद्संस्कारों का बीजारोपण करता है एवं उसके व्यक्तित्व को नव्य और स्वच्छ रूप प्रदान करता है। चन्द्रमा सबको शांति और अह्लाद प्रदान करता है, वैसे ही पिता की प्रेरणाएं पुत्र को मानसिक प्रसन्नता और परम शांति देती है। जैसे औषधि दुख, दर्द और पीड़ा का हरण करती है, वैसे ही पिता शिव शंकर की भांति पुत्र के सारे अवसाद और दुखों का हरण करते हैं। पय का अर्थ है- दूध। जैसे माता का दूध पुष्टि प्रदान करता है, वैसे ही पिता पुत्र के आत्मिक बल को पुष्ट करते हैं। मेरे लिये मेरे पिता देवतुल्य एवं गहन आध्यात्मिक-धार्मिक जीवट वाले व्यक्तित्व थे। उनकी जैसी सादगी, उनकी जैसी सरलता, उनकी जैसा समर्पण, उनकी जैसी धार्मिकता, उनकी जैसी पारिवारिक नेतृत्वशीलता और उनकी जैसी संवेदनशीलता को जीना दुर्लभ है। उन्होंने परिवार एवं समाज को समृद्धशाली और शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किया। मेरे लिये तो वे आज भी दिव्य ऊर्जा के केन्द्र हैं। पिता आंसुओं और मुस्कान का एक समुच्चय है, जो बेटे के दुख में रोता तो सुख में हंसता है। उसे आसमान छूता देख अपने को कद्दावर मानता है तो राह भटकते देख अपनी किस्मत की बुरी लकीरों को कोसता है। पिता गंगोत्री की वह बूंद है जो गंगा सागर तक एक-एक तट, एक-एक घाट को पवित्र करने के लिए धोता रहता है। पिता वह आग है जो घड़े को पकाता है, लेकिन जलाता नहीं जरा भी। वह ऐसी चिंगारी है जो जरूरत के वक्त बेटे को शोले में तब्दील करता है। वह ऐसा सूरज है, जो सुबह पक्षियों के कलरव के साथ धरती पर हलचल शुरू करता है, दोपहर में तपता है और शाम को धीरे से चांद को लिए रास्ता छोड़ देता है। पिता वह पूनम का चांद है जो बच्चे के बचपने में रहता है, तो धीरे-धीरे घटता हुआ क्रमशः अमावस का हो जाता है। पिता समंदर के जैसा भी है, जिसकी सतह पर असंख्य लहरें खेलती हैं, तो जिसकी गहराई में खामोशी ही खामोशी है। वह चखने में भले खारा लगे, लेकिन जब बारिश बन खेतों में आता है तो मीठे से मीठा हो जाता है। बचपन में चॉकलेट, खिलौने दिलाने से लेकर युवावर्ग तक बाइक, कार, लैपटॉप और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने तक संतान की सभी माँगों को पिता ही पूरा करते रहते हैं लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भागदौड़ भरी इस जिंदगी में बच्चों के पास अपने पिता के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसी को ध्यान में रखकर पितृ दिवस मनाने की परंपरा का आरम्भ हुआ।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार, ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92)

प्रताड़ना के शिकार है बुजुर्ग

– बाल मुकुन्द ओझा

देश और दुनिया में हर साल 15 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें जागरूक करना और इसे रोकने के प्रयास करना। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यव्हार और अन्याय पर रोकथाम के लिए यह दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। हमारे देश में बुजुर्गों को अपने ही घर में प्रताड़ित होने के समाचार निश्चय ही दिल दहलाने वाले है। आश्चर्य की बात तो यह है इन्हें प्रताड़ित करने वाले कोई दूसरे नहीं अपने ही है। इनमें लाखों बुजुर्गों ने अदालतों में अपने ही लोगों के खिलाफ न्याय की गुहार की है। ये बुजुर्ग अपनी बची खुची जिंदगी बिना - विघ्न बाधा परिवारजनों के साथ काटना चाहते है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में हर 6 में से 1 बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। समाज के दो तिहाई से अधिक बुजुर्गों का कहना है कि वे घर में बच्चों समेत परिवार के सदस्यों के हाथों उत्पीड़न, अपमान और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। 'एजवेल फाउंडेशन'नामक एक गैर सरकारी संगठन ने 5 हजार बुर्जुगों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। रिपोर्ट के अनुसार जिन बुजुर्गों से बातचीत की गयी, उनमें दो तिहाई से अधिक ने कहा कि घर में परिवार के लोग, बच्चे, रिश्तेदार या अन्य उन्हें झिड़कते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उनका अपमान करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर बुजुर्गों (करीब 77 प्रतिशत) का कहना है कि उन्हें अपने मानवाधिकारों की जानकारी नहीं है तथा उनसे जब बुरा बर्ताव किया जाने लगता है तो वे उसका विरोध नहीं करते हैं और ऐसे में यह एक पैटर्न (चलन) बन जाता है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बुजुर्गों को दो विशेष अधिकार देता है। पहला-अगर संतान गुजर-बसर के लिए खर्च नहीं देते हैं तो बुजुर्ग कानूनन उनसे प्रतिमाह भत्ता लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा-बच्चे बुजुर्गों को घर से नहीं निकाल सकते हैं। जबकि बुजुर्गों को यह अधिकार है कि वे परेशान करने पर बालिग संतान को घर छोड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसके लिए बुजुर्ग को एसडीएम से शिकायत करनी होगी या कोर्ट जाना होगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में साल 2021 में बुजुर्गों की संख्या 13.8 करोड़ पर पहुंच गयी है। इनमें 6.7 करोड़ पुरुष और 7.1 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने की वजह मृत्यु दर में कमी आना बताई गई है। इस अध्ययन में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को बुजुर्ग माना गया है। सांख्यिकी अध्ययन में कहा गया है कि 2011 में भारत में बुजुर्गों की आबादी 10.38 करोड़ थी, जिसमें 5.28 करोड़ पुरुष और 5.11 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। वही साल 2031 में बुजुर्गों की संख्या 19.38 करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के मधे नज़र यह देखना भी जरुरी है की बुजुर्ग आज किस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे है। बुजुर्ग देश और समाज के लिए एक समस्या है या गौरव है। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या देखकर ख़ुशी होती है की व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हो रही है मगर बुजुर्गों की उपेक्षा को देखकर दु:ख भी होता है। हर एक को याद रखना चाहिए की बुढ़ापा एक दिन सब को आएगा। जिस दिन यह सच्चाई हम स्वीकार कर लेंगे उस दिन समाज बुजुर्गों की इज्जत और सम्मान करना सीख लेंगा। विश्व में बुजुर्गों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में प्रत्येक पांच में से एक बुजुर्ग अकेले या अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। यानी वह परिवार नामक संस्था से अलग रहने को विवश है। ऐसे बुजुर्गों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अशिक्षित बुजुर्गों की हालत और भी ज्यादा दयनीय है। अधिकतर बुजुर्ग डिप्रेशन, आर्थराइटिस, डायबिटीज एवं आंख संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं और महीने में औसतन 15 दिन बीमार रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन वरिष्ठ नागरिकों को होती है, जिनके पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है। हेल्पेज इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट बताती है कि देश के लगभग 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों में से पांच करोड़ से भी ज्यादा बुजुर्ग आए दिन भूखे पेट सोते हैं। देश की कुल आबादी का आठ फीसदी हिस्सा अपने जीवन की अंतिम वेला में सिर्फ भूख नहीं, बल्कि कई तरह की समस्याओं का शिकार है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

भीष्म पितामह की लोन गारंटी

– रामविलास जांगिड़

हुआ यूं कि अचानकली सडनता से राम राज्य आ गया। पिछले दिनों सरकार ने जो वादा किया था, वह पूरा हो गया। कहीं कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दंगा-फसाद नहीं! परम शांति! झूठ झपट जाल सब बंद! पुलिस महकमा खतम हो गया। कुछ तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों ने आसपास की सर्कस कंपनियां ज्वाइन कर ली। सर्कस में वे रात-रात भर इसका हाथ छोड़कर, उसका हाथ पकड़ते और हवा में झूलते। बच्चे लोग पुलिस के ऐसे कारनामे देखकर तालियां पीटते। कुछ पुलिस कुर्मी जो बेचारे ढीले-ढच थे, उन्होंने कविता बाजी करना शुरू कर दिया। वे इधर-उधर मारामारी करके कविताएं लिखते और उसे फेसबुक पर फेंक मारते। एक-एक लाइक के लिए वे अपनी जाजम बिछाते। ताजी राते हिंद दफा 305 के तहत मुलजिम को बाय इज्जत बरी किया जाता है, जैसी आवाजें आना बंद हो गई। न्यायकर्मी एकाएक बेरोजगार हो गए। वे सब पड़ोस की सब्जी मंडी में शिफ्ट हो गए। वहां वे मिलॉर्ड टमाटर ले लो! मिलॉर्ड भिंडी ले लो जैसे शास्त्रीय गीत हवा में उछालने लगे। महकमा-ए-इंसाफ शानदार ढंग से साफ हो गया।

रावण ने अपना अहंकार गुस्सा आदि हिंद महासागर में दफन कर दिया। वह एक नदी किनारे प्रेम-प्यार से रहने के धंधे में कूद कर प्रवचन बांचने लग गया। उसके सिरों पर बच्चे बढ़िया तरीके से झूला झूल सकें, इसके लिए प्रवचन कंपनी के इवेंट मैनेजर द्वारा टिकट का प्रावधान भी था। कुछ बच्चे रावण की दोनों मूंछों को खींचते, तब रावण बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से मंद-मंद मुस्कुराता। कुछ सयाने मां-बाप उसके गदे को बच्चों के हाथों में थमा कर स्वीट सेल्फी लेते और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते। शीघ्र ही रावण कथा बांचने के धंधे का बड़ा खिलाड़ी हो गया।

इधर दुशासन ने साड़ी खींचने जैसा राजकीय कार्य छोड़-छाड़ कर शहर में एक साड़ी शोरूम खुला खोल लिया। शोरूम की किस्तें टाइम पर चली जाए इसके लिए लोन की गारंटी आदरणीय भीष्म पितामह ने दी। जो भी महिलाएं दुशासन के शोरूम पर जाती वह उन्हें हाथ जोड़ता। उन्हें दंडवत प्रणाम करता। पड़ोस के शोरूम से पानी-पतासे खिलाता और माता श्री -भगनी श्री जैसे मृदुल वचनों से उन्हें साड़ी की वैरायटी दिखाने लगता। वह एक साड़ी खरीदने पर तीन साड़ियां भी मुफ्त में देने लगा था। दुशासन देश का जाना माना साड़ी व्यापारी हो गया।

सीन यह बना कि कंस ने सारी मामागिरी छोड़कर यमुना किनारे एक आइसक्रीम का ठेला लगा लिया है। वह साइकिल के करियर के पीछे बांधकर 3 किलोमीटर दूर स्थित आइस फैक्ट्री से बर्फ की एक सिल्ली लाता। उसे ठेले पर रखना और रंदा मार कर बर्फ का कचरा कूट करता। वह बर्फ का गोला बनाकर पांच पैसे में तीन तीन बर्फ के गोले बच्चों को पकड़ाता। बर्फ के गोले चूसते हुए बच्चे बाकायदा कंस के मोटे से पेट पर गुदगुदी कर सकते थे। उसकी पीठ में चिकोटी काट सकते थे। बच्चों के गुदगुदी करने की कोई मनाही नहीं थी। चारों ओर राम राज्य ठांठें मारने लगा था।

(उत्तम नगर, घूघरा, अजमेर)

कविता

गर्माहट

बहुत अच्छा लगता
है न
तुमको जीवों को
पका कर
स्वाद से खाना।

प्रकृति भी तो
पका रही हैं
अब तुमको
सूर्य की तप्त
किरणों में।

उसको भी तो
थोड़ा स्वाद आना
चाहिए
तुम को रुलाने में।

बहुत अच्छा लगता
है न
तुमको चुपचाप
अग्नि को सुलगा
कर
वनों को
जलता हुआ
देखकर।

प्रकृति भी तो
सुलग रही हैं
आग
सूर्य की किरणें
बन कर।

उसको भी तो
थोड़ा आनंद
आना चाहिए
तुम को तपा कर।

डॉ. राजीव डोगरा
(युवा कवि व लेखक, गांव जनयानकड़, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश)

मप्र की इस जोड़ी ने ही 2020 में फिर कमाल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ को पदच्युत कराकर अपने अपमान का बदला लिया और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवा दी थी। 2020 से ही ये जोड़ी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नजरों में थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस जोड़ी ने हाड़तोड़ मेहनत कर मप्र में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाकर भाजपा की सरकार बनवाई।

सिंधिया और शिवराज पर भरोसे के निहितार्थ

– राकेश अचल

केंद्रीय मंत्री मंडल में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करने के पीछे क्या वजह है यह जानने में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। भाजपा की यह दो हंसों की जोड़ी 2018 के विधानसभा चुनाव में आमने-सामने थी। तब महाराज यानि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे और चौहान मप्र के मुख्यमंत्री थे इस चुनाव में भाजपा ने 'माफ़ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज' का नारा दिया था और कांग्रेस की ओर से 'माफ़ करो शिवराज, हमारे नेता महाराज' का नारा उछला और कामयाब भी हुआ था। शिवराज सत्ताच्युत हो गए थे, लेकिन महाराज अपनी पार्टी के सत्ता में आने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे।

मप्र की इस जोड़ी ने ही 2020 में फिर कमाल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ को पदच्युत कराकर अपने अपमान का बदला लिया और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवा दी थी। 2020 से ही ये जोड़ी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नजरों में थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस जोड़ी ने हाड़तोड़ मेहनत कर मप्र में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाकर भाजपा की सरकार बनवाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो 2020 के करतब के लिए पुरस्कार के रूप में राज्यसभा की सदस्यता और केंद्रीय मंत्री मंडल में स्थान मिल गया था, किन्तु शिवराज सिंह को कोई इनाम-इकराम नहीं मिला था। उलटे उनके स्थान पर मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब शिवराज सिंह मंजे हुए खिलाडी निकले। उन्होंने अपमान का कड़वा घूँट बिना ना-नुकुर के पी लिया। नतीजा ये हुआ कि 2024 के आम चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शिवराज सिंह चौहान को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गयी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो मंत्री बनना ही था क्योंकि वे प्रधानमंत्री के गांव-गौड़े के नाते दामाद लगते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को उनकी योग्यता और मौन साधना की वजह से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वैसे एक समय उनका नाम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भी सुर्ख़ियों में आया था। प्रधानमंत्री ने केंद्र में सरकार का गठन करने के फौरन बाद अपने मंत्रिमंडल में सिंधिया और चौहान को एक खास मकसद से जगह दी है। इन दोनों को मंत्रिमंडल में लिए जाने से जातीय संतुलन बना या नहीं ये भी हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि मोदी जी के पूर्व मंत्रिमंडल के कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की वजह से मोदी जी

और उनकी पार्टी को किसान आंदोलन के दौरान जो फजीहत झेलना पड़ी उसे देखते हुए ही शिवराज सिंह चौहान को नया कृषि मंत्री बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मध्यप्रदेश से ही थे। वे किसान आंदोलन को ढंग से हैंडिल नहीं कर पाए थे। दरअसल तोमर यानि ग्वालियर के मुन्ना भैया, मौन सिंह साबित हुए थे। वे न किसानों को मना पाए और न किसान यूनियनों को। उन्हें किसान संगठनों से संवाद स्थापित करने में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। उलटे सरकार के माथे पर 700 किसानों की हत्या का दाग और लग गया था। विवादास्पद क़ानून वापस लेने पड़े थे सो अलग। देश के किसान अभी भी आंदोलित है। किसान आंदोलन किसी भी समय भड़क सकता है। किसान आंदोलन का खमियाजा भाजपा ने आम चुनावों में भी उठाया। ऐसे में वाचाल, मिलनसार और किसानों से सीधा रिश्ता कायम करने में समर्थ शिवराज सिंह चौहान को चुना गया। हालाँकि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी मंदसौर गोलीकांड का दाग लगा हुआ है। बहरहाल अब शिवराज सिंह को आपने आपको एक बार फिर प्रमाणित करना है। उनके पास एक मुख्यमंत्री के रूप में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है, जो प्रधानमंत्री जी के अनुभव से भी कहीं ज्यादा है।

अब आइये महाराज यानि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं। सिंधिया के डीएनए में संघ, भाजपा और कांग्रेस के गुण समाहित हैं। सिंधिया की दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया पहले कांग्रेसी, फिर जनसंघी और अंत में भाजपा में रहीं। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया पहले जनसंघ में फिर कांग्रेस में रहे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में पहला कदम कांग्रेस के माध्यम से रखा और 20 साल तक कांग्रेस में मान-सम्मान पाने के बाद अपमान मिलते ही कांग्रेस से किनारा कर भाजपा की सदस्यता ले ली। सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे उनका गुजरात से रिश्ता होने के साथ ही उनकी कर्मठता और ईमानदारी भी मानी जाती है। मेरे अपने सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बहुत सोच-विचार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय के साथ ही पूर्वोत्तर के विकास की जिम्मेदारी दी है। सिंधिया को संचार मंत्रालय देने के पीछे मकसद आने वाले दिनों में होने वाले 5 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी भी है। आपको याद होगा कि इसी देश में कांग्रेस की सरकार के जमाने में अब तक का सबसे बड़ा 2 जी घोटाला हुआ था। इस घोटाले में कांग्रेस के सहयोगी द्रमुक के नेता और मंत्री के शामिल होने के आरोप लगे थे। तत्कालीन संचार मंत्री ए.राजा को तो पंद्रह महीने जेल में भी काटना पड़े थे। हालाँकि राजा बाद में बरी हो गए थे। मोदी जी नहीं चाहते कि 5 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में कोई घोटाला हो इसलिए सिंधिया को इसकी जिम्मेदारी दी गयी। केंद्रीय मंत्री मंडल में फिलहाल सिंधिया अकेले ऐसे मंत्री हैं जिनका दामन पाक-साफ़ दिखाई देता है। उनके पिता के साथ तो नैतिकता का भी तमगा जुड़ा था। उन्होंने एक मामूली सी हवाई दुर्घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीव्ही नरसिम्हाराव को अपना त्यागपत्र सौंप दिया था। हवाला कांड में नाम आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने उफ़ तक नहीं की और एक निर्दलीय के रूप में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वे चाहते तो भाजपा में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं किया। मौजूदा सरकार को पूर्वोत्तर में जड़ें जमाने के लिए एक उत्साहीलाल की जरूरत थी। इस कसौटी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खरे उतरे इसीलिए उन्हें संचार मंत्रालय के साथ पूर्वोत्तर मामलों की भी जिम्मेदारी दी गयी। पूर्वोत्तर में मणिपुर सबसे ज्वलंत मुद्दा है। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने भी मणिपुर को लेकर नयी सरकार को आगाह किया है। पूर्वोत्तर में हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली है। अब देखना ये है कि नए कृषि मंत्री और नए संचार मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने कामयाब हो पाते हैं? इन दोनों नेताओं की कामयाबी ही इनके बच्चों की कामयाबी के दरवाजे खोलेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि चौहान और सिंधिया दोनों के बेटे राजनीति में पदार्पण के लिए कमर कसकर तैयार बैठे हैं।

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 15 जून 2024

निशाने पर चुनाव

घाटी की जगह जम्मू में आतंकियों का ज़ोर

जम्मू-कश्मीर में पिछले दिनों एक के बाद एक चार आतंकी हमलों ने सुरक्षा बलों और सरकारी हलकों में ठीक ही चिंता जगाई है। ये हमले न सिर्फ आतंक के पैटर्न में बदलाव का संकेत हैं बल्कि देश-दुनिया को यह संदेश देने की भी कोशिश है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है।

हमले की टाइमिंग | यह संयोग नहीं हो सकता कि इन हमलों की शुरुआत के लिए 9 जून की तारीख को चुना गया। वह दिन जब लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने नया कार्यकाल शुरू किया। जाहिर है, जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होना और उसमें लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखना आतंकवादी तत्वों को रास नहीं आया। यह अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को हासिल विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद पहला चुनाव था। अब 30 सितंबर से पहले वहां विधानसभा चुनाव करवाए जाने हैं। आतंकियों का अगला लक्ष्य चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना हो सकता है।

सीमा पार से साज़िश

बदलती आतंकी रणनीति | सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नकेल कसने के जो प्रयास पिछले कुछ वर्षों में किए हैं, उनका असर आतंकी घटनाओं में आई कमी में ही नहीं, आतंकियों की लगातार बदलती रणनीति में भी दिखता है। पहले आतंकियों ने टारगेटेड किलिंग का सहारा लेते हुए आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, जो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते थे। अब घाटी में सुरक्षा बलों के कड़े बंदोबस्त को देखते हुए जम्मू के उन इलाकों में गतिविधियां बढ़ाई गई हैं जो लंबे समय से शांत और आतंकवाद से मुक्त माने जाते रहे हैं।

तीर्थयात्रियों पर निशाना | गौर करने की बात यह भी है कि आतंकियों ने रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया। चरम उग्रवाद के दौर में भी जम्मू-कश्मीर में टूरिस्टों और अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने से बचने का ट्रेंड दिखता था। वजह यह बताई जाती थी कि इससे राज्य की टूरिज्म पर आधारित इकॉनमी का नुकसान होगा। लेकिन सीमा पार से संचालित आतंकवादियों से ऐसे संयम और सोच की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आशंका है कि आगे चलकर ऐसे हमले और बढ़ सकते हैं।

शरीफ बंधुओं की पेशकश | पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जरूर दोस्ती की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन उनकी इस इच्छा को पाकिस्तानी फौज की असली मंशा का संकेत नहीं माना जा सकता। अतीत में इन दोनों का फर्क खतरनाक रूप में सामने आता रहा है।

न टलें चुनाव | ऐसे में 90 के दशक के पैटर्न पर सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला वक्त की जरूरत है। मगर इसके साथ ही सरकार को यह संकल्प बनाए रखना होगा कि किसी भी सूरत में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव आगे खिसकाने की नौबत नहीं आने देनी है।

अंतर्दृष्टि

भगवद गीता से लें ज़िंदगी के तीन बड़े सबक

सुंदर चंद ठाकुर

भगवद गीता भारतीय धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता का संभवतः सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगर आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को संवारना चाहते हैं, तो इसकी शरण जाएं। आज मैं इसके तीन प्रमुख श्लोकों की बात करूंगा। अकेले ये तीन श्लोक ही हमारे जीवन को ऐसी राह पर ले जा सकते हैं, जहां सफलता और आनंद सहज ही आपको मिल जाएंगे। जिन्हें नहीं मालूम, उनके लिए एक बुनियादी तथ्य - भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और इसमें भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। अब जरा तीन प्रमुख सबक जानते हैं :

1. कर्मयोग: अपने कर्तव्य का पालन करना

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।। (2.47)

भगवद गीता का पहला प्रमुख सबक है यह। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें अपने कार्य को बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। इस बात को समझ लें कि जब भी आप ऐसा करेंगे, तो आपका काम श्रेष्ठ हो जाएगा क्योंकि फल की चिंता न रहने से आप सारा फोकस काम पर देंगे। कुछ लोग नादानी में सवाल उठाते हैं कि फल ही नहीं मिलना, तो कर्म क्यों करना। ऐसा नहीं होता। यह सिर्फ श्रीकृष्ण के बात कहने का अंदाज है। असल में तो ज्यादा फोकस से काम करने के कारण आपको और भी बड़ा फल मिलता है।

2. समभाव: सुख-दुख में समानता

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।। (2.38)

भगवद गीता का दूसरा प्रमुख सबक है समभाव यानी सुख और दुख में समान रहना। श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें जीवन में आने वाले सभी अनुभवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सुख में ज्यादा सुखी होने से दुख में दुख भी ज्यादा होता है। अमूमन हम ऐसे व्यक्ति को योगी की संज्ञा देते हैं। सांसारिकता में फंसे व्यक्ति के लिए यह पहली नजर में मुश्किल काम प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप इसे मन में रखकर इसके प्रति सचेत रहना शुरू कर दें, तो कुछ समय में आप भी समभाव में रहना सीख सकते हैं।

3. भक्ति योग: परमात्मा में पूर्ण समर्पण

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः।। (9.34)

भगवद गीता का तीसरा महत्वपूर्ण सबक है भक्ति योग यानी परमात्मा के लिए पूर्ण समर्पण। इस श्लोक में श्रीकृष्ण कहते हैं-अपने मन को मुझमें लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम अपनी आस्था और समर्पण के साथ मुझमें समाहित हो जाओगे। हमारे जीवन में दुखों और तकलीफों की वजह ही यह है कि हम खुद को नियंता मानने लगते हैं। खुद को ही कारक समझने लगते हैं।

ऑफ दि ट्रैक

दिमाग में चिप

दिलीप लाल

डॉक्टरों के लिए दिमाग पर लगी चोट को ठीक करना आज भी बड़ी चुनौती है। इस तरह की स्थिति में सबसे मुश्किल यह जानना होता है कि दिमाग के भीतर चल क्या रहा है, वह कैसा रिएक्ट कर रहा है। यह मुश्किल अब आसान होती दिख रही है। चीन की Huazhong University ने ऐसा सेंसर बनाया है, जिसे इंसानी दिमाग के भीतर लगाया जा सकता है। इसका आकार केवल दो मिलीमीटर है, चावल के एक दाने के बराबर। इसे हाइड्रोजेल से तैयार किया गया है, जो एक तरह का ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। इस सेंसर को बनाने वाली टीम का कहना है कि यह दिमाग के भीतर होने वाले बदलावों को रेकॉर्ड कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि यह पूरी तरह वायरलेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स से फ्री। टीम ने अभी इसका प्रयोग सुअर और चूहों पर किया है। सेंसर ने दिमाग में ब्लड प्रेशर, तापमान, pH लेवल और नजदीकी रक्त वाहिनियों में खून के बहाव को दर्ज किया। इसे एक सुई के जरिये इंसर्ट किया गया था। काम होने के बाद इस सेंसर को दिमाग से निकालने की जरूरत भी नहीं है। टेस्ट के दौरान पाया गया कि चार से पांच हफ्तों के भीतर यह अपने आप घुल गया। इससे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे components निकले, जिनका जानवरों के दिमाग पर बुरा असर नहीं पड़ा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस छोटे-से उपकरण के जरिये दिमाग में झांककर बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है।

यूक्रेन युद्ध पर शुरू हो रहे स्विस शांति सम्मेलन में मध्यस्थता का मौका

मोदी बन सकते हैं शांतिदूत

हर्ष वी. पंत

नए कार्यकाल की शुरुआत में ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ एक अच्छा मौका आया है। यह मौका है उस शांति सम्मेलन में मध्यस्थता करने का, जिसे पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे महत्वपूर्ण शांति सम्मेलन बताया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी आज सबसे वरिष्ठ और लंबे समय से सत्तारूढ़ वैश्विक नेताओं में शामिल हैं। खास बात यह भी है कि ग्लोबल साउथ का अग्रणी स्वर माना जाने वाला भारत पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने का जोरदार पक्षधर रहा है।

ग्लोबल साउथ का हितरक्षक | शांति सम्मेलन में शिरकत करना भारत को ग्लोबल साउथ के प्रमुख हितरक्षक की भूमिका में सामने लाएगा, खासकर सप्लाई चेन की बाधाओं को दूर करने और ऊर्जा संकट व खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने के लिहाज से। इसलिए, भारत को यूक्रेन में शांति और क्षेत्र में स्थायी स्थिरता लाने लाने वाले तीन स्तंभों के रूप में लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद की अहमियत पर जोर देना चाहिए।

सम्मेलन की टाइमिंग | यह शांति सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब नए जनादेश की चमक तो मोदी के साथ जुड़ी ही हुई है, भारत के G-20 नेतृत्व की सफलता की आभा भी बरकरार है। रूस की सीधी निंदा न करने के कारण जो यूरोपीय देश शुरू में भारत की आलोचना कर रहे थे, वे भी आलोचना का स्वर धीमा करते हुए उसे लुभाने में लगे हैं। जाहिर है, यह सम्मेलन भारत और पीएम मोदी को शांति के अपने संदेशों के जरिए वैश्विक मध्यस्थ के रूप में नई दिल्ली की साख मजबूत करने का एक बेशकीमती अवसर दे रहा है।

ग्लोबल साउथ का संकट | रूस-यूक्रेन युद्ध ने कई महत्वपूर्ण डिवेलपमेंट फंड को ग्लोबल साउथ से दूर कर दिया। इन देशों पर युद्ध का आर्थिक दुष्प्रभाव और बढ़ गया है। अपने गुटनिरपेक्ष रुख और दोनों देशों के साथ संबंधों के कारण, भारत शांति वार्ता में असरदार भूमिका निभा सकता है।

G-20 अध्यक्षता का असर | विकासशील देश कहते रहे हैं कि अमीर देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं की मदद के प्रयास बढ़ाने चाहिए। कोरोना महामारी में ये अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। युद्ध ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। इसी का उदाहरण है ग्लोबल साउथ को मिलने वाली आधिकारिक विकास सहायता में कमी और इन अर्थव्यवस्थाओं पर कर्ज के बोझ में बढ़ोतरी। 2023 में भारत की सफल G-20 की अध्यक्षता उभरती वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भारत के बढ़ते प्रभाव का साफ संकेत है।

स्विस सम्मेलन पर निगाहें : क्या निकलेगा शांति का सर्वमान्य फॉर्म्युला?

भारत पर निगाहें
- यूक्रेन, रूस से भारत के करीबी रिश्ते
- मोदी ने कहा था, यह युद्ध का दौर नहीं
- शांति के पक्ष में है हिंदुस्तान

यूरोप की दिलचस्पी | भारत की संभावित प्रभावी भूमिका में यूरोप की भी दिलचस्पी है। ध्यान रहे, इस बात का अहसास हाल के दिनों में बढ़ा है कि यूरोपीय देश विकासशील देशों का भरोसा जीतने के लिए खास कुछ नहीं कर सके हैं। ऐसे में जब पश्चिम और ग्लोबल साउथ दोनों भारत के नेतृत्व और प्रभाव को स्वीकार करते हैं, उसके पास एक ऐसा रास्ता निकालने का अनुकूल अवसर है जो अतीत के बोझ से मुक्त हो।

खाद्य संकट की तलवार | थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि युद्ध के कारण अगर सचमुच रूस और यूक्रेन से गेहूं का निर्यात पूरी तरह बंद हो जाए, तो ग्लोबल साउथ के देशों को होने वाली इसकी सालाना सप्लाई में भारी कमी आएगी। दक्षिण एशिया में 19%, सब-सहारा अफ्रीका में 57%, दक्षिण पूर्व एशिया में 26%, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में 39% तक की कमी हो जाएगी। इससे गंभीर खाद्य संकट होगा। दुनिया के प्रमुख एनर्जी सप्लायर देश रूस पर प्रतिबंधों के कारण वैसे भी कीमतों में तेज बढ़ोतरी के झटके लगे हैं।

मौका भी है, दस्तूर भी | पूर्व और पश्चिम दोनों का दोस्त होने के नाते भारत की विशिष्ट स्थिति और जलवायु वार्ताओं में ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर उभरने की उसकी आकांक्षा रूस-यूक्रेन शांति के संभावित फॉर्म्युले को संभव बना सकती है।

रूस से खरी-खरी | ध्यान रहे, भारतीय प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन से सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि 'यह युद्ध का दौर' नहीं है। इस संदर्भ में देखें तो एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में रूस को खरी-खरी सुनाने की भारत की क्षमता उसे मौजूदा माहौल में महत्वपूर्ण स्वर बना देती है।

भारत का हित | यूरोप में शांति बहाल होना भारत के भी हित में है। इस युद्ध ने भारत को रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखने के रस्सी पर चलने जैसे मुश्किल हालात में डाल रखा है। भारतीय प्रधानमंत्री की अगुआई में चली शांति वार्ता न केवल एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी व्यक्तिगत साख को मजबूत करेगी, बल्कि भारत की सफल मध्यस्थता के दीर्घकालिक फायदे भी होंगे। वैश्विक अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभरती ताकत के तौर पर नई दिल्ली के लिए ऐसी नेतृत्वकारी भूमिका वक्त की मांग है।

(लेखक इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

कैसे बदल रहे रोबॉट

लंदन के एक स्टार्टअप का रोबॉट मॉडल Lingo-2 कार चला सकता है। Robotics startup Figure का मॉडल समस्याएं सुलझाने की कला सीख रहा है। कैसे समझदार होते जा रहे हैं रोबॉट, समझते हैं :

AI की ताकत से लैस

Chatgpt जैसे चैटबॉट की ताकत है large language models। इससे ही चैटबॉट भाषा को समझते और जवाब देते हैं। इसी तरह AI के विजन लैंग्वेज मॉडल तस्वीरों पर काम कर सकते हैं। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की यही ताकत अब रोबॉटिक्स में अप्लाई की जा रही।

VLAM का करिश्मा

भाषा और तस्वीरों में डील करने के साथ ही रोबॉट को आसपास के माहौल को पढ़ना भी सिखाया जा रहा है। ये मॉडल्स कहलाते हैं VLAM यानी vision-language-action models। इससे रोबॉट बाहरी दुनिया को समझ पा रहे हैं।

AI image

रोबॉट का दिमाग

हम कुछ देखते या सुनते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देने से पहले अपने दिमाग में आकलन करते हैं कि क्या यह सही रहेगा। VLAM से लैस रोबॉट भी इसी प्रॉसेस को फॉलो करते हैं। कह सकते हैं कि यह मॉडल दिमाग है रोबॉट का। इससे न केवल रोबॉट किसी कमांड को पूरा कर सकते हैं बल्कि यह भी तर्क देकर बता सकते हैं कि उन्होंने वह काम उसी तरह से क्यों किया।

पुराने रोबॉट की तरक्की

अमेरिका की कंपनी Covariant ने rfm-1 नाम का एक मॉडल बनाया है। इसे 30 से अधिक तरह के रोबॉट के डेटा के जरिये ट्रेंड किया गया है। यह कंपनी खुद का रोबॉट नहीं बनाती, बल्कि अपने इस मॉडल से पुराने रोबॉट को ही नए कामों के लिए प्रोग्राम करती है। एक तरह से Covariant दिमाग बना रही है।

सुधार हुआ आसान

रोबॉट को अब बिना किसी ट्रेनिंग के नया काम सिखाया जा सकता है। टेक वर्ल्ड में इसे कहते हैं zero-shot learning। इससे रोबॉट में सुधार और उसे नए कामों के लिए ट्रेंड करना आसान हो गया है। यह काम अब टेक्स्ट prompts से हो जा रहा है।

प्रस्तुति : **शैलेंद्र पांडेय**

एक सेंटर से इतने टॉपर्स जांच का विषय

NEET-UG परीक्षा के रिजल्ट में बड़े स्तर पर सामने आईं गड़बड़ियों के बाद नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) सवालों के घेरे में है। राष्ट्रीय स्तर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम में कहां हैं गड़बड़ियां, क्या है हल, इस पर CBSE के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली से ***कात्यायनी उप्रेती*** *ने बातचीत की। पेश हैं अहम अंश :*

■ NEET को लेकर कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या कहेंगे?

NEET भारत का बहुत बड़ा प्रफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। यह ऑफलाइन और सिंगल टियर एग्जामिनेशन है। देश और देश से बाहर इतने बड़े स्तर पर एग्जामिनेशन करवाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। अगर हर एंगल पर सावधानी नहीं बरतेंगे, तो फिसलने का चांस रहता ही है। NEET को लेकर इस वक्त गलतियां निकालने से ज्यादा हल निकालने की जरूरत है।

■ NEET ही नहीं, CUET, NTET जैसे एंट्रेंस में भी NTA का कुप्रबंधन नजर आया है। ऐन वक्त पर एग्जाम रद्द, सेंटर बदल दिए जाते हैं। क्या NTA का फेलियर मानेंगे?

NTA नई संस्था है। किसी भी संस्था को स्थापित होने में, सही मैनपावर लाने में, करेक्ट यूनिट खोलने में समय लगता है। NEET, JEE का आयोजन पहले CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के नाम से कराता था। CBSE बहुत ही स्थिर संस्था रही है। सही मैनपावर, सही टीम, सही सिस्टम की बदौलत कई साल परीक्षाएं संचालित कीं। इन परीक्षाओं में जब स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा बढ़ी, तो CBSE क्लास 10 और 12 पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा था। तब ये एंट्रेंस NTA को दिए गए।

■ क्या मानते हैं कि NTA के पास एक्सपर्ट टीम की कमी है?

NTA का गठन अच्छी नीयत से किया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम प्रफेशनल एंट्रेंस एग्जाम अलग से कराएं। इसके बनने से न्यूट्रैलिटी आ गई है, मगर इसकी फैकल्टी बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है कि NTA में ज्यादातर लोग डेप्युटेशन पर लिए गए हैं। एजेंसी में अलग-अलग विंग होने चाहिए। जब CBSE NEET और JEE करवाता था, तब दोनों को अलग-अलग विंग देखते थे। अगर इन सब चीजों पर मंथन होगा, सही टीम बनेगी, तो निश्चय ही सिस्टम में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

■ परफेक्ट स्कोर के साथ 67 टॉपर्स। एक ही सेंटर से 6 टॉपर हैं। कितना उचित लगता है?

यह पैन इंडिया एग्जामिनेशन है, विदेशों में भी होता है। 23 लाख उम्मीदवार हैं, तो टॉपर्स की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन क्या एक ही क्षेत्र या रीजन या सेंटर से ऐसे स्टूडेंट्स हैं! अगर हैं, तो सवाल उठता है और यह जांच का विषय है।

सप्ताह का इंटरव्यू

अशोक गांगुली

■ NTA ने 'टाइम लॉस' के नाम पर 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए थे, जिसका काफी विरोध हुआ। ग्रेस मार्क्स का क्या प्रावधान है?

NTA ने अब इनका रिजल्ट रद्द कर इनके लिए फिर से एग्जाम रखा है, यह वेलकम स्टेप है। दरअसल, प्रफेशनल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 10 और 12 की परीक्षा की तरह नहीं है, जिसमें बच्चा पास होने से कुछ नंबर से रह गया तो उसे ग्रेस नंबर देकर आगे बढ़ा दिया जाए। यहां पास या फेल की बात नहीं, चुनने की बात है। ऐसे में ग्रेस मार्क्स दिया जाना उचित नहीं है। हां, अगर किसी कारण से परीक्षा में कोई दिक्कत हुई है, तो उसी अनुरूप स्टूडेंट्स को अतिरिक्त टाइम दें या उस एग्जाम को स्थगित कर दें।

■ स्टूडेंट्स की मांग है कि सभी का NEET एग्जाम दोबारा हो। क्या हल है?

जब तक पेपरलीक का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक यह एग्जाम दोबारा रखना सही नहीं होगा। पेपरलीक का पता करने में इतना समय नहीं लगता। हमें कोर्ट के निर्णय की भी प्रतीक्षा करनी होगी।

■ क्या कॉम्पिटीटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव की जरूरत है?

> अभी का सिस्टम बेस्ट हुनर नहीं, बेस्ट कोच किए गए स्टूडेंट्स चुन रहा है। जहां 10 लाख से ऊपर बच्चे हैं, उस एग्जाम को सिंगल टियर की बजाय डबल टियर में कराया जाए, जो प्री-मेडिकल एंट्रेंस में पहले भी होता था। इंजीनियरिंग दाखिले के लिए भी JEE दो एग्जाम में पहले ही बंट चुका है- मेन और अडवांस्ड

अभी जो सिस्टम है वह बेस्ट हुनर नहीं बल्कि बेस्ट कोच किए गए स्टूडेंट्स चुन रहा है। आवश्यकता है कि जहां 10 लाख से ऊपर बच्चे हैं, उस एग्जाम को सिंगल टियर की बजाय डबल टियर में कराया जाए, जो प्री मेडिकल एंट्रेंस में पहले भी होता था। इंजीनियरिंग दाखिले के लिए भी JEE दो एग्जाम में पहले ही बंट चुका है- JEE मेन और JEE एडवांस्ड।

■ विदेश में भी कई बड़े एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जैसे चीन में Gaocow, यूएस में SAT। क्या उनके सिस्टम से भी कुछ सीखा जा सकता है?

बिल्कुल, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेज से हम सीख सकते हैं। आवश्यकता है कि हम पड़ताल करें, होमवर्क करें, रिसर्च करें। जो व्यवस्था अभी है, वह 25-30 साल पुरानी हो गई है। आज के दौर में चीजें तेजी से बदल रही हैं। इस सबके अनुसार हमें अपनी व्यवस्था भी बदलनी चाहिए।

■ एडमिशन एंट्रेंस, रिक्रूटमेंट एग्जाम में पेपरलीक के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। कहां गड़बड़ी है?

पेपरलीक की आशंका तभी रहती है जब पेपर बहुत सारे हाथों से गुजरता है। पहले पेपर सेटिंग होती है, फिर मॉडरेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, इसके बाद प्रिंटिंग के लिए पेपर जाता है, फिर डिलिवरी के लिए एग्जामिनेशन सेंटर भेजा जाता है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि डिस्ट्रिब्यूशन या सेंटर के स्तर पर पेपरलीक होते हैं। हर पॉइंट को हम बहुत टाइट रखेंगे तो पेपर लीक नहीं होगा।

■ UGC ने साल में दो बार एडमिशन की इजाजत दी है। क्या फायदे हैं?

हमारे यहां कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद अगस्त में रिजल्ट आता है। तब तक कॉलेजों में सीटें लगभग भर जाती हैं और बच्चों का साल बर्बाद हो जाता है। दो बार दाखिले होंगे तो वे दिसंबर-जनवरी में दाखिला ले सकेंगे। मगर लागू करने से पहले हमारी टीचिंग कम्युनिटी से बात करना जरूरी है कि क्या वह तैयार है? तैयारी के बिना लागू करेंगे तो गड़बड़ियां ही सामने आएंगी।

इलाज की खातिर अहसान की तहें

रिजवान महबूब मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालते हैं। बात पिछले साल की है। जुलाई में अचानक उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। स्थानीय डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ कामचलाऊ दवाइयां दे दीं। रिजवान को तब दवा से आराम मिल गया। लेकिन दिसंबर में फिर से दर्द होने लगा। फिर एक दिन जब दर्द हद से पार हो गया तो किसी तरह से बोरीवली के अस्पताल पहुंचे। पता चला कि दिल में कई ब्लॉकेज हैं, तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी।

ओपन हार्ट सर्जरी काफी महंगी होती है। डॉक्टरों ने छह-सात लाख रुपये का इंतजाम करने के लिए कहा था। मेरे पास आए। मैंने उनको महाराष्ट्र सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के बारे में बताया और उसके लिए रिजवान से अप्लाई करवा दिया। आखिरकार वह दिन आ गया और इसी साल जनवरी में योजना के तहत उनकी सर्जरी भी हो गई। सर्जरी के दस दिन बाद रिजवान घर भी आ गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले ही महीने यानी फरवरी में उन्हें सीने में फिर से तेज दर्द होने लगा। मामला मुझे पहले से ही पता था, तो इस बार मैंने एक मित्र रीमा सिंह से मदद मांगी। रीमा कई साल से गरीब तबके के बाल रोगियों का चैरिटी से फंड जुटाकर इलाज करवाती रही हैं।

खुद अपनी आंख से

हरगोविंद विश्वकर्मा

हम दोनों बड़ी उम्मीद से उनके पास पहुंचे और उन्होंने भी हमें निराश नहीं किया। वह हमें लेकर अस्पताल गईं। वहां फिर से एंजियोग्राफी हुई तो पता चला कि सर्जरी ठीक से नहीं हुई, जिससे दिक्कत बढ़ रही है। इसके बाद रीमा और मैं रिजवान को मुंबई के कई अस्पतालों में लेकर गए। हर जगह कहा गया कि दोबारा सर्जरी में लगभग छह-सात लाख रुपये खर्च आएगा। इतने पैसों का इंतजाम करना लगभग असंभव था। लेकिन हिम्मत न हारने वाली रीमा ने दिन-रात एक कर दिया।

फिर एक दिन काम बनता नजर आया। एक डॉक्टर ने मदद की आस बंधाई। उन्होंने रिजवान की जांच की और कहा कि दो-तीन महीने के भीतर ही दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी में बड़ा रिस्क है, लेकिन सर्जरी न कराना और भी बड़ा रिस्क। पैसे का इंतजाम हो जाए तो उनकी टीम कोशिश कर सकती है। वहां भी बजट लगभग छह लाख रुपये था। रिजवान फिर मायूस हो गए। रीमा और मैं इंतजाम के लिए भाग-दौड़ करते रहे। हमारी नीयत देखकर डॉक्टर साहब ने भी कोशिश करके सर्जरी के बिल में बड़ी छूट दिला दी।

आखिरकार अप्रैल में रिजवान का सफल ऑपरेशन हुआ। ठीक होने के बाद रिजवान को उसके घर पहुंचा कर जब मैं और रीमा निकलने लगे तो रिजवान बहुत भावुक हो गए और हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, 'आप मेरे लिए फरिश्ते हैं। मेरा जीवन अब आपकी अमानत है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।' रीमा ने कहा, उसी अल्लाह ने तो आपको और मुझे ये खुशी बख्शी है। हम सब उसकी ही अमानत हैं। इस अनुभव ने मन में यह सवाल जरूर छोड़ा कि किसी बीमारी से जूझता इंसान अगर संसाधनों से लैस न हो तो सिर्फ इलाज के लिए उसे कितने स्तरों पर, कितनी तरह से और कितने लोगों का अहसान लेना पड़ता है।

चलते-चलते...

चील, गिद्ध, बाज जैसे लंबे समय तक आसमान में रहने वाले पक्षी अपने डैनों को बहुत कम फड़फड़ाते हैं। वे हवा की दिशा में ग्लाइड करते हैं, जो रोमांचक लगता है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानियों की टीम ने बताया है कि उड़ने वाले पक्षी ऐसा करने के लिए अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। यह स्टडी हाल ही में मशहूर नेचर मैगजीन में प्रकाशित हुई है।

रीडर्स मेल

▸ हिंदुत्व की राजनीति

लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होना हिंदुत्व की राजनीति का फेल हो जाना नहीं है। यदि ऐसा होता तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा व अन्य प्रदेशों में उसे एक तरफा जीत नहीं मिलती। इस बार विपक्ष ने मुसलमानों को हर तरह से साधने का प्रयास किया है। मुस्लिम मतदाता शत प्रतिशत वोटिंग करते हैं, वहीं हिंदू मतदाता घर से निकल कर वोट डालने की जहमत तक नहीं उठाते। हिंदुओं का वोटिंग प्रतिशत 60% रहता है, जबकि एग्जिट पोल में इंटरेस्ट 99% और चुनाव परिणाम में 101 पर्सेंट का रुझान होता है।

-विभूति बुपक्या, ईमेल से

▸ मदद की याचना

हाल ही में एक लेख छपा है, जो आरएसएस से जुड़े व्यक्ति का है। उन्होंने अपने लेख में साफ तौर पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से आरएसएस से संपर्क तक नहीं किया गया। इसलिए आरएसएस के जमीनी स्तर पर काम करनेवाले कार्यकर्ता इस चुनाव से दूर रहे। आरएसएस के लोगों ने चुनाव प्रचार में खुलकर हिस्सा नहीं लिया। उनके इस लेख से लगता है कि आरएसएस के लोगों को भी अब अहम संतुष्टि का रोग लग गया है।

-चंद्रा देवत (मुंबई), ईमेल से

▸ मामले की न्यायिक जांच हो

NEET-UG परीक्षा परिणामों को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भविष्य की आकांक्षाओं को लेकर लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में अपारदर्शिता और अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब मांगा है, लेकिन एनटीए इस मामले में खुद को नीट एंड क्लीन होने का पक्ष रख रहा है। इन सब घटनाओं से यह तो साबित हो रहा है कि प्रशासन की लापरवाही और पूरी परीक्षा प्रणाली के व्यावसायीकरण के चलते अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था भी ध्वस्त हो चली है, जिसका खामियाजा पूर्ण रूप से निर्दोष स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले।

-दीपा सिन्हा (मुंबई), ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999; फैक्स:(022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांस: (022) 66353636, 22733636 फैक्स: (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 15 जून • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

खुशबू को इत्र बेचने वाले की सिफारिश की जरूरत नहीं होती

-फ़ारसी कहावत

पुलिस का पहरा नाकाफी

राजधानी दिल्ली में पानी संकट के बीच पुलिस की इंट्री आश्चर्य पैदा करती है। अब पानी को माफिया से बचाने के लिए पुलिस को ज्यादा चौकस रहना होगा। पानी माफियाओं के बढ़ते दखल के बाद अब कम-से-कम पुलिस को ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस बाबत पुलिस फोर्स ने चौकियां स्थापित की हैं और दिल्ली को पानी की आपूर्ति करने वाली नहर के हरियाणा की सीमा पर 15 किलोमीटर के हिस्से पर गश्त शुरू कर दी है। दरअसल, राजधानी इस सीजन में पानी का अभूतपूर्व संकट झेल रहा है। गर्मी की शुरुआत से ही यहां पानी की भारी किल्लत होने लगी थी, मगर न तो दिल्ली की सरकार ने और न केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। जब तपिश अपने चरम पर पहुंची और जल के लिए त्राहिमाम हुआ तब इधर-उधर से पानी मांगे जाने का प्रपंच शुरू हुआ। वैसे, यह सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है। हर साल पानी को लेकर दिल्ली की दुश्वारियां चरम पर रहती है। इस बार ज्यादा गर्मी की वजह से मामला चर्चा में आया।

बहरहाल, भले टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई हो, मगर जो हालात पानी को लेकर दिल्ली की दिखती है उसमें खाकी की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। उसकी वजह बहुत साफ है। एक तो दिल्ली का अपना पानी का कोई सिस्टम नहीं है। पानी का ज्यादातर हिस्सा यमुना नदी का है। कुछ बोरवेल दिल्ली सरकार ने लगवाए हैं। मगर ये सब कार्य पानी की अभी की स्थिति के सामने बहुत छोटी है। यही वजह है कि पानी के लिए कभी हरियाणा तो कभी उत्तर प्रदेश तो कभी हिमाचल प्रदेश के आगे चिरौरी करनी पड़ती है। अगर दिल्ली को पानी के संकट से निजात पाना है तो उसे सबसे पहले पानी के पूर्व के स्त्रोतों पर काम करना होगा। इसके अलावा पानी माफिया पर कड़ा रुख दिखाना होगा। पानी की चोरी और उसके बेवजह बह कर बर्बाद होने पर भी नजर रखनी होगी। छोटे-छोटे प्रयास के दम पर ही हम दिल्ली को इस समस्या से उबार सकते हैं। अदालत की चौखट तक जाने से पहले हमें उन पारंपरिक जल स्त्रोतों पर गंभीरतापूर्वक काम करना होगा। हिमाचल या हरियाणा से पानी मंगाने का चलन अब बंद होना चाहिए। दिल्ली की जनता को भी इस मामले में ईमानदार और सजग रहने की जरूरत है क्योंकि अंततः भोगना उन्हीं को पड़ता है। दिल्ली में पानी की समस्या बड़ी तो है, मगर उतनी बड़ी नहीं कि उसका निदान न हो।

दुरुस्त हो योजना

अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीन सेवाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसकी घोषणा जून 2022 में की गई। योजना के तहत भर्ती जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। सरकार ने अब इस योजना की समीक्षा का कार्य दस अलग-अलग मंत्रालयों के सचिवों को सौंपा है। वे इस भर्ती को अधिक आकर्षक बनाने के सुझाव भी देंगे। इसकी कमियों को दूर भी किया जा सकता है। यह भर्ती चार साल के लिए होती है, जिसमें नियमित वेतन के अतिरिक्त चार साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों को लगभग बारह लाख रुपए मिलते हैं। निश्चित संख्या में तकरीबन पच्चीस फीसद अग्निवीरों को स्थायी सेवा का अवसर भी मिलता है। माना जा रहा है कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत वेतन भत्तों में बढ़ोतरी व अन्य लाभ का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

चूंकि यह योजना सरकार के प्रथम सौ दिन के एजेंडे में शामिल है इसलिए अधिकारी अपनी विस्तृत प्रस्तुति जल्दी ही प्रधानमंत्री कार्यालय को देंगे। आम चुनाव के दौरान इस योजना को विपक्ष द्वारा लगातार निशाने पर रखा गया था। वे अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के प्रति खिलवाड़ की तरह पेश कर रहे थे। साथ ही सत्ता में आने पर इसे समाप्त करने की भी बात की जा रही थी। यह मोदी सरकार की रोजगार योजना का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि विशेषज्ञों व पूर्व सैनिकों की दलील है कि मात्र छह माह के प्रशिक्षण से सैनिक नहीं तैयार होता। दूसरे, पूर्व-अग्निवीरों को अर्ध-सैनिक बलों या पुलिस बलों जैसी सेवाओं में शामिल न किए जाने को लेकर सरकार की बहुत आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि इसे मायावी रोजगार कहा जा रहा है। इन्हें देश के सशस्त्र बलों में सेवा के लिए अयोग्य भी घोषित किए जाने को लेकर विवाद है। सेवा की इस अल्प अवधि यानी चार साल बाद ये युवा पुनः बेरोजगारों की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसे में इन्हें अप्रशिक्षित कामगारों के तौर पर काम के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बाइस साल उम्र में जब ये युवा सेवा से बाहर होंगे तो नए सिरे से इन्हें काम की तलाश में भटकना पड़ सकता है। लाजमी है, सरकार ने इसी तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए समीक्षा व सुझाव की कोशिश की है। उम्मीद की जानी चाहिए, इसमें अग्निवीरों के बेहतर भविष्य की बुनियाद रखी जा सके।

कटाक्ष/ कबीरदास

पेपर लीक की गारंटी!

विरोधियों की ये क्या बात हुई। खामखां में नीट की परीक्षा में गड़बड़ियों का इतना शोर मचा दिया। उस पर तुर्रा ये कि ये एक परीक्षा में ही गड़बड़ी का मामला नहीं है। डबल इंजनिया राज में, न जाने कैसे हरेक परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है! सिंपल है। पेपर लीक की गारंटी है। अब प्लीज यह बचकाना सवाल कोई न उठाए कि मोदी की गारंटियों में पेपर लीक की गारंटी तो थी ही नहीं।

पेपर लीक तो था कि नहीं, गारंटियों से भी पहले से। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक, लेखपाल भर्ती पेपर लीक, वगैरह, वगैरह। छूट गई होगी पेपर लीक की गारंटी, चुनाव की हड़बड़ी में। पेपर लीक की गारंटी भी नहीं दी, फिर भी गारंटी कर रहे हैं, यही तो मोदी की गारंटी है। जो नहीं भी दी हैं, वो गारंटियां भी पूरी करने की गारंटी! फिर भी पता नहीं क्यों पब्लिक ने अब की दिल्ली वाले इंजन के नीचे बैसाखियों के जैक लगवा दिए।

खैर! नीट में तो पेपर लीक की बात ही गलत है। शिक्षा मंत्री ने साफ-साफ कह दिया है-पेपर लीक का तो कोई सबूत ही नहीं मिला है। सबूत नहीं, तो पेपर लीक कैसे? क्या हुआ कि गुजरात के किसी परीक्षा केंद्र से दूर-दूर से जाकर बच्चों के परीक्षा देने की और तीस-तीस लाख रुपए में अच्छे रैंक से पास कराने की गारंटी की खबरें आई हैं। क्या हुआ कि हरियाणा में किसी परीक्षा केंद्र से आधे दर्जन बच्चों के सौ फीसद नंबर लेकर टॉप करने की खबरें आई हैं। क्या हुआ कि बिहार से पर्चा ज्यों का त्यों एक दिन पहले मिल जाने की खबरें आई हैं। क्या हुआ कि सोलह सौ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने की बात मानी गई और वह भी दो-चार नंबर नहीं, सैकड़ों तक। क्या हुआ 67 बच्चों को पूरे में पूरे नंबर, इसके बावजूद मिले हैं कि पूरे नंबर मिलना नामुमकिन है। पर यह सब तो कुछ परीक्षार्थियों को अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी की बात हुई। गारंटियों के इस जमाने में, ऐसी छोटी-मोटी गारंटियां तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दे ही सकते हैं। फॉलो योर पीएम!

पर बाकी कुछ भी हो, इसमें पेपर लीक का सबूत कहां है? अब पेपर लीक की जांच भी सरकार ही कराएगी, तो गड़बड़ी की शिकायत करने वाले क्या करेंगे; मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र!

कुछ रह सा गया

शपथ ग्रहण

अजय तिवारी

नौ जून को सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विदेशी मेहमान (पड़ोसी देशों के प्रमुख), फिल्मी मेहमान, कारोबारी मेहमान सब थे, लेकिन देश का विपक्ष नदारद था। राष्ट्रपति भवन के मैदान में हुए बड़े जलसे में देश-विदेश से 8000 से ज्यादा मेहमान बुलाए गए थे। विपक्ष को सम्मानपूर्वक आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए वहां देश की प्रमुख नेता सोनिया गांधी और शरद पवार नहीं दिखे। वाम राजनीति के बड़े चेहरे सीताराम येचुरी और डी राजा भी नहीं थे। जम्मू कश्मीर के बड़े नेता फारुख अब्दुल्ला और लोक सभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी नहीं पहुंचे।

न पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन नजर आए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखिवंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अनुपस्थिति भी खल रही थी। ये सभी देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं। विदेशी मेहमान विपक्षी नेताओं से भी परिचित हैं, इसलिए स्वाभाविक है उनके मन में भी यह सवाल आया होगा कि देश की सरकार बनने जैसे खास मौके पर विपक्ष क्यों उपस्थित नहीं रहा? इसे किस तरह से लिया होगा कहने की जरूरत नहीं है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने जब सोनिया गांधी का परिवार गया होगा तब अन्य बातों के साथ विदेशी मेहमान ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके सरकार के साथ रिश्तों पर भी बात की होगी। विपक्ष का कहना है कि उसे शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित ही नहीं किया गया था। विपक्ष के सांसदों की भी ऐसे ही शिकायत थी। विपक्ष सच बोल रहा है अथवा झूठ यह तो वह जानता है या फिर सरकार। हालांकि यह भी सच है कि विपक्ष के आरोपों का सरकार ने कोई खंडन नहीं किया। सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण समारोह के आमंत्रण पत्र पार्टी दफ्तर से लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जो राज्य सभा में विपक्ष के भी नेता हैं सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। बेमन से राष्ट्रपति भवन पहुंचे खरगे ने कहा कि वह संवैधानिक बाध्यता की वजह से यहां हैं, अपनी खुशी से नहीं। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट करके उनको बधाई दी अथवा नहीं, इसकी जानकारी दोनों नेताओं ने नहीं दी। सरकार बनने के बाद शिष्टाचारवश भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता नहीं मिले। विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर

भी सरकार को बधाई देने में संकोच किया। पुरानी परंपराएं टूटने लगी है। संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों ने सबसे बड़े विपक्षी दल के नेताओं से भी मुलाकात नहीं की।

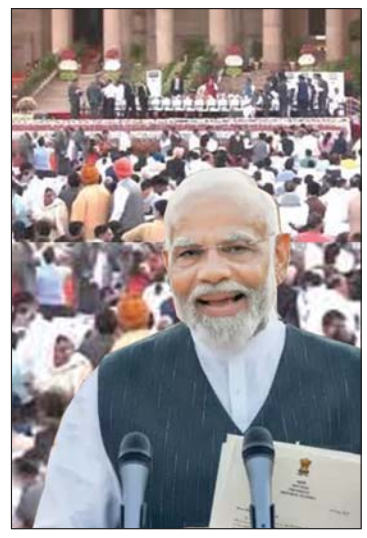

संसद के भीतर कानून सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों को मिलकर बनाना है इसलिए उनके बीच दुआ-सलाम तो हर हाल में बनी ही रहनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रिश्तों में खिंचाव का असर गठबंधन सरकार और संसद पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। नई लोक सभा के अध्यक्ष का 26 जून को चुनाव होना है। लोक सभा का अध्यक्ष निर्विरोध चुनवाने के लिए सरकार को विपक्ष की मदद की जरूरत होगी। चूंकि दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं है इसलिए इसमें कठिनाई जाएगी। विपक्ष दो ही स्थिति में सरकार को सहयोग कर सकता है। या तो सरकार विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देने का प्रस्ताव करे अथवा ऐसे सांसद को लोक सभा अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाए जो सर्वमान्य हो।

कारपोरेट नहीं कोऑपरेटिव वाली

गठबंधन सरकार जिन क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाना चाहती है उनमें से एक क्षेत्र है सहकारिता। इसके जरिए सरकार यह धारणा भी बनाना चाहती है कि वह कारपोरेट को नहीं कोऑपरेटिव (सहकारिता) को बढ़ावा दे रही है। सरकार प्रायः सभी क्षेत्र कोऑपरेटिव के लिए खोलना चाहती है। पेट्रोल पम्प और दवाओं की बिक्री जैसे उपक्रम पिछले कार्यकाल में उसने कोऑपरेटिव संस्थाओं को दिए थे। सरकार कोऑपरेटिव संस्थाओं में दशकों से जमे नेताओं को भी हिलाना चाहती है। इसीलिए कोऑपरेटिव संस्थाओं में चुनाव के लिए चुनाव आयोग जैसी संस्था बनाने का प्रस्ताव है। सरकार पहले ही सारी कोऑपरेटिव संस्थाओं का डेटा तैयार करवा चुकी है, संस्थाओं को कंप्यूटराइजेशन के लिए भी सख्ती से बाध्य किया गया है। सहकारिता मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह के पास होने से कोऑपरेटिव की सारी बड़ी संस्थाएं चाहे वह अमूल हो या इफको सब सहयोग कर रही हैं।

कृषि और किसान दोनों चुनौती

कृषि क्षेत्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्योंकि किसानों का विश्वास सरकार पर नहीं है। सरकार ने पुराने वादे पूरे नहीं किए हैं इसलिए उसके लिए इस क्षेत्र में कोई सुधारवादी कदम उठाना बेहद मुश्किल होगा। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य) कानूनी गारंटी को लेकर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। पंजाब में चल रहा किसान आंदोलन फिर गति पकड़ने लगा है। किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। पंजाब में किसानों का बड़ा वर्ग कंगना को किसान विरोधी मानता है। इधर, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने किसान नेताओं को फोन करके कहा है कि वह आंदोलन का समर्थन करती हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के पांच सांसद भी पंजाब में किसानों के धरना स्थल पर भेजे। अगले महीने जुलाई में किसान नेता दिल्ली में सांसदों से मिलेंगे और आंदोलन के लिए आगामी कार्यक्रम बनाएंगे।

रोजगार नहीं है और श्रमिक भी नाखुश

सरकार की चुनाव में सबसे ज्यादा आलोचना बेरोजगारी की वजह से भी हुई। इस मुद्दे पर सरकार चलाने वाली भाजपा और उसके सहयोगी कोई जवाब नहीं दे सके। नए कार्यकाल में भी उसके समक्ष रोजगार देने की चुनौती है। पिछले कार्यकाल में सरकार ने हर बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के सदस्यों की संख्या के आधार पर रोजगार के मोर्चे पर अपना बचाव किया लेकिन विफल रही। पिछली संसद में सरकार ने चार लेबर कोड पारित कराए थे, लेकिन श्रमिकों के विरोध के चलते इसे लागू नहीं कर सकी थी। बड़ी संख्या में श्रम कानून को समाप्त करके श्रम सुधार के नाम पर लाए गए लेबर कोड को लागू करना अब भी सरकार के लिए चुनौती है। सभी श्रमिकों को पेंशन दी जानी है यह विषय भी सरकार को हल करना है।

> सरकार की चुनाव में सबसे ज्यादा आलोचना बेरोजगारी की वजह से भी हुई। इस मुद्दे पर सरकार चलाने वाली भाजपा और उसके सहयोगी कोई जवाब नहीं दे सके। नए कार्यकाल में भी उसके समक्ष रोजगार देने की चुनौती है। पिछले कार्यकाल में सरकार ने हर बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के सदस्यों की संख्या के आधार पर रोजगार के मोर्चे पर अपना बचाव किया लेकिन विफल रही। पिछली संसद में सरकार ने चार लेबर कोड पारित कराए थे, लेकिन श्रमिकों के विरोध के चलते इसे लागू नहीं कर सकी थी

वैश्विक हवाई यात्री यातायात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी

- कैलेंडर वर्ष 2023 में वैश्विक यात्री यातायात में भारत की हिस्सेदारी 4.2 फीसद जबकि 2019 में 3.8 फीसद थी
- इक्रा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ नये मार्गों के जुड़ने से भारतीय यात्री यातायात कोविड-पूर्व के मुकाबले 106 फीसद तक पहुंच गया है रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय हवाई यात्री यातायात के वैश्विक रुझान से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है

(इक्रा)

राजनीति के इस असीमित ओवरों के टेस्ट मैच में कांग्रेस को काफी फासला तय करना है। चेहरे पर ही गेंद डाल देने वाले बॉडी-लाइन गेंदबाजों, तरफदारी करने वाले अंपायरों और अराजक टिप्पणीकारों के बीच खराब पिच पर पूरे थकाऊ दिन 99 नॉट आउट कोई इतना खराब स्कोर तो नहीं ही है।

योगेन्द्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता
@_YogendraYadav

सपा की जीत के मायने

उत्तर प्रदेश | रजनीश कपूर

अचानक कहीं कुछ नहीं होता, अंदर ही अंदर कुछ घिस रहा होता है, कुछ पिस रहा होता है।' इन पंक्तियों में कवि ने इस बात पर इशारा किया है कि किसी भी काम का विपरीत अंजाम आने पर हमें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा कैसे हो गया? जबकि उसके पीछे के कारणों पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा ही कुछ हुआ 2024 के उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनाव परिणाम के बाद। यहां बीजेपी को पहले के मुकाबले इस बार बहुत कम सीटें मिलीं। ऐसा क्या कारण था कि भाजपा का प्रदर्शन इतना बुरा रहा? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। अनुच्छेद 370 का हटाना। तीन तलाक को खत्म करना। ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जिन पर भाजपा को पूरा विश्वास था कि वह 'अबकी बार 400 पार' के अपने नारे को सच कर दिखाएंगे, परंतु ऐसा न हो सका।

ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो परिणाम रहा उसने सत्तारूढ़ दल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसी कौन सी कमी उनकी नीति में थी जो वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में विफल रही? ऐसा क्या हुआ कि पार्टी कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं था जो पिछले दो लोक सभा चुनावों में देखा गया? क्या संगठन के काम करने के ढंग या उनके द्वारा लिये गए गलत फैसलों ने जमीनी कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित किया? क्या उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में, जहां भाजपा का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था वहां पर उम्मीदवारों के चयन में गलती हुई? हिंदुओं के लिए पूजनीय अयोध्या, रामेश्वरम में मिली हार और प्रधानमंत्री को वाराणसी में पिछली बार के मुकाबले बहुत कम अंतर से मिली जीत भी सवालों के घेरे में है। इन नतीजों के बाद सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का 'अहंकार' की ओर इशारा करना भी क्या इस बुरे प्रदर्शन का कारण बना? सूत्रों के अनुसार इस बार के चुनाव में कम सीट आने के पीछे भाजपा में अंदरूनी कलह ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह केंद्र के नेतृत्व द्वारा राज्य की सरकारों व राज्यों के नेताओं की उपेक्षा की गई और वो फिर जनता के सामने आई वह भी इन नतीजों का कारण बनी। भाजपा और संघ के बीच हुए मतभेदों को भी अनदेखा नहीं

किया जा सकता। यदि केंद्र और राज्य के नेतृत्व में कोई मतभेद थे तो उन्हें समय रहते एक मर्यादा के तहत हल किया जाना चाहिए था। भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं का इस बार के चुनावों में सक्रिय योगदान नहीं दिखाई दिया उससे देश भर में एक संदेश गया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जमीन से कट गया है। इस बार के चुनाव को इतने चरणों में बांटने से भी कार्यकर्ताओं की सहभागिता में कमी नजर आई। कार्यकर्ताओं को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि पिछले दस वर्षों में देश में ऐसे कई बदलाव आए हैं, जो तीसरी बार भी मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत दिलाएंगे। इसी के चलते भी कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह दिखाई नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर देखें तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के चप्पे-चप्पे पर अपनी नजर बनाए रखी और भागदौड़ की वो काफी फायदेमंद रहा। सपा के उम्मीदवारों का चयन और 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों का उन पर भरोसा, दोनों ही इन चुनावों में सही साबित हुए। यदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसी ऊर्जा और रणनीति से अभी से जुटे रहेंगे तो 2027 के विधान सभा चुनावों में भी उनका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। उत्तर प्रदेश के अगले विधान सभा चुनाव में यदि सही रणनीति और सही उम्मीदवारों का चयन हो, यदि वहां की जनता की समस्याओं के समाधान की एक ठोस योजना हो तो उन मतों को भी अपने पाले में लाया जा सकता है जो बुनियादी मुद्दों से भटका दिये गए हैं।

इतना ही नहीं, जिस तरह समाजवादी पार्टी को एक विशेष वर्ग के लोगों की पार्टी माना जाता था, उसका भी भ्रम इस बार के चुनावों में टूटा है। सभी हिंदू तीर्थ स्थलों में सपा ने भाजपा को शिकस्त दी है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह 'एम-वाई' फैक्टर को नए रूप में पेश किया वह भी काम कर गया है। जिस तरह भाजपा हर समय चुनावी मूड में रहती है यदि विपक्षी पार्टियां भी उसी मूड में रहें तो भाजपा को कड़ी टक्कर दे पाएंगी। इसके साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को ही इस बात पर भी तैयार रहना चाहिए कि यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन की सरकार ही विकल्प होता है। यदि कोई भी दल इस अहंकार में रहे कि वो एक बड़ा और प्रभावशाली राजनैतिक दल है और विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए है तो फिर उसे तब झटका लगेगा ही जब उसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के आगे झुकना पड़ेगा। हर दल को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। गठबंधन की सरकार में हर वो दल जिसके पास अच्छी संख्या हो वह किसी न किसी बात पर उखड़ भी सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि अपनी गलतियों से सबक लिया जाए और 'सबका साथ और सबका विकास' अमल में लाया जाए।

अज्ञानता से मुक्ति | संत राजिन्दर

हम अपना जीवन जीते हुए बाहर की दुनिया में खुशी पाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम अपना अधिकतर समय धन-संपति एकत्र करने, मान-सम्मान को पाने और शरीर को स्वस्थ रखने आदि में लगा देते हैं, लेकिन यह सब करने के बावजूद भी हम अंदर से खुश नहीं हो पाते। संत-महापुरुष हमें समझाते हैं कि सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंतर में है। यह सच्ची खुशी हमारी आत्मा मन, शरीर और संसार की मन-माया की परतों से ढकी हुई है, इस बात से हम अनजान हैं। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हम संतों-महात्माओं की शिक्षा का आश्रय ले सकते हैं, जोकि धर्म-पुस्तकों में लिखित है। वे हमें समझाते हैं कि प्रभु, जोकि सत, चेतनता और आनंद के महासागर हैं, ने यह सृष्टि बनाई है। शुरू-शुरू में वह अकेले थे, फिर उन्होंने एक से अनेक होने का संकल्प लिया एवं अपने अंशों को अपने से अलग किया, जिन्हें हम आत्मा कहते हैं और उन्हें इस भौतिक सृष्टि में रहने के लिए भेज दिया। जब आत्मा इस संसार में आती है तो यहां कार्य-व्यवहार के लिए इसे एक भौतिक शरीर और मन दिया जाता है। होना तो यह चाहिए था कि हमारी आत्मा के बस में शरीर और मन होता, लेकिन दुर्भाग्यवश उल्टा हो गया। आत्मा, शरीर और मन के साथ लिप्त होकर इसी का रूप बन बैठी है और अपने आपको भूल गई। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है और हर समय मौज-मस्ती में रहना चाहता है। यह जल्द ही बाहरी चमक-दमक में फंस जाता है। यह हर सुंदर दृश्य, मधुर आवाज, अच्छी खुशबू, लजीज जायके एवं मनमोहक स्पर्श की ओर खिंचा चला जाता है। हमारी सभी इंद्रियां मन को बाहर की ओर खींचती रहती हैं क्योंकि इस शरीर में आत्मा और मन साथ-साथ रहते हैं। इसलिए आत्मा भी बेबस होकर इंद्रियों के भोग-रस में खिंची चली जाती है। समय के साथ हमारी आत्मा इस संसार के खेल में खो गई है और अपने असली रूप को भूल गई है। आत्मा सत्य, चेतनता और आनंद से परिपूर्ण अपनी असलियत की ओर ध्यान देने के बजाय बाहरी संसार में लिप्त हो गई है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह पाक-पवित्र होता है और इस दुनिया से अनजान होता है। अगर हम उसकी आंखों में देखें तो वह प्यार और खुशी से भरपूर होता है।

रीडर्स मेल

रचनात्मक राजनीति का समय

भारत एक लोकतांत्रिक है। इसका तात्पर्य यही है कि देश की जनता ही भारत की असली सरकार है। लोक सभा चुनावों के बाद अब देश में सरकार और विपक्ष की भूमिका भी तय हो गई है। जनता ने जहां नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजग को बहुमत दिया है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को एक बार फिर से सत्ता से दूर कर दिया है। अब चुनाव हो चुके हैं, इसलिए लोकतांत्रिक देश होने के नाते आवश्यक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार के बयान दिए गए, उससे यही लगता है कि इसकी प्रतिध्वनि आगे भी सुनाई देगी। आज के राजनीतिक हालातों का अध्ययन किया जाए तो यह कहना सर्वथा उचित ही होगा कि दलीय आधार की राजनीति करना केवल चुनाव तक ही सीमित रहना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही चाहिए कि वह अब देश हित की राजनीति करने वाले ही कदम उठाए।

सुरेश हिन्दुस्तानी, ग्वालियर, मप्र

दुर्भाग्यपूर्ण घटना

कुवैत की एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग से 45 भारतीयों की जान गंवाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। रोजगार की तलाश में कुवैत गए इन सभी भारतीयों का इस तरह से जान गंवाने की घटना से अनेक तरह के सवालों का उठना लाजिमी है। कुवैत की आबादी का लगभग दो तिहाई हिस्सा विदेश से आने वाले मजदूरों का है। यहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इन मजदूरों पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में इन मजदूरों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भी कुवैत सरकार की ही होनी चाहिए। बहरहाल, मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कुवैत में विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल से मुलाकात की है और घायलों का हालचाल पूछा है। कुवैत सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है। इस घटना से सबक लेते हुए कुवैत सरकार को ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के प्रयास करने चाहिए। भारत सरकार को भी इस घटना में आहत हुए मजदूरों के परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने सहित उनको न्याय दिलाने में तेजी दिखानी चाहिए।

हितेंद्र डेढा, दिल्ली

खराब नहीं है ओटीटी

ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता का मतलब यह नहीं है कि पारंपरिक मीडिया समाप्त हो गया है। टेलीविजन अभी भी लोकप्रिय है और कुछ लोग अभी भी प्रिंट मीडिया को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन नया मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म भविष्य है और इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जाएगी। हम कह सकते हैं कि नया मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरंजन के क्षेत्र में एक क्रांति ला रहे हैं। वे न केवल लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि फिल्म और टेलीविजन कलाकारों के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में नए मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म किस तरह विकसित होते हैं और वे हमारे मनोरंजन के अनुभव को कैसे और अधिक बेहतर बनाते हैं।

चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-33, अंक 302

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान 1936

नीट से न्याय

नीट या मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद को सुलझाने की कवायद जारी है, इसी कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नीट-यूजी परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली सात याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। खास यह कि एक याचिका में इस बार के नीट-यूजी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की गई है। न्यायालय ने केंद्र सरकार के अलावा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या एनटीए से भी जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 8 जुलाई को बड़े फैसले की उम्मीद है। अब तक के घटनाक्रम से यह तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इस बार की प्रवेश परीक्षा में कुछ बड़ी कमियां रह गई हैं। इस बात के भी स्पष्ट संकेत हैं कि परीक्षा के साथ कोई न कोई गंभीर खिलवाड़ हुआ है। यह सुखद है कि एनटीए ने भी ग्रेस मार्क्स के खेल पर ध्यान दिया है और 1,563 छात्रों को फिर टेस्ट में बैठना पड़ेगा। टेस्ट का यह फैसला न्यायोचित है, जिन बच्चों के साथ ग्रेस मार्क्स की वजह से नाइंसाफी हुई है, उन्हें अब न्याय मिलने की संभावना बढ़ गई है।

बहरहाल, पूरी परीक्षा को नकार देने की कवायद ठीक नहीं है। लाखों विद्यार्थियों ने बहुत संसाधन और समय लगाकर परीक्षा दी है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं होते, वे फिर से परीक्षा की मांग करते हैं, पर यहां किसी भी परीक्षा को न्यायोचित ढंग से ही देखना चाहिए। यहां भावना के ज्यादा मायने नहीं हैं। परीक्षा नियम-कायदे का मामला है, उसकी गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता किसी अन्याय से कम नहीं है।

पूरी परीक्षा को ही नकार देने की कवायद ठीक नहीं है। लाखों विद्यार्थियों ने बहुत संसाधन और समय लगाकर परीक्षा दी है, उनके साथ न्याय होना चाहिए।

बहरहाल, कहीं न कहीं कुछ अन्याय हुआ है, तभी तो जगह-जगह उच्च न्यायालयों में परीक्षा को चुनौती दी गई है और एनटीए उचित ही चाहता है कि तमाम मामलों की सुनवाई एक ही जगह सर्वोच्च न्यायालय में हो। कोई आश्चर्य नहीं, एनटीए की ऐसी ही मांग पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। इस पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ को पूरी कड़ाई के साथ प्रश्नपत्र लीक और कदाचार की सुनवाई करनी पड़ेगी। एक बड़ा खतरा यह है कि अगर कदाचार का सहारा लेने वाले माफिया अभी बच गए, तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। यह संभव है कि इस कदाचार में एनटीए के भी कुछ लोग लिप्त रहे हों, अतः एनटीए की जांच पैनल पर कितना भरोसा किया जाए, यह फैसला अदालत को ही करना चाहिए। यह मांग शायद उचित है कि जांच अदालत की निगरानी में होनी चाहिए।

अपने देश में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च कई निजी संस्थानों में करोड़ों रुपये में पहुंच गया है। ऐसे में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए जद्दोजहद तेज होती जा रही है। ध्यान रहे, मेडिकल प्रवेश परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था। सबसे बड़ा शक तो यही है कि परिणाम 14 जून को घोषित करने के बजाय 4 जून को घोषित किए गए, उस दिन देश में मतगणना चल रही थी। क्या सफेदपोश लोगों ने यह सोचा कि चुनावी नतीजों के हो-हल्ले में उनका अपराध छिप जाएगा? क्या इसमें बड़े कोचिंग संस्थानों की भूमिका है? क्या अब अदालती जंग के पीछे भी चंद कोचिंग संस्थानों की प्रतिद्वंद्विता काम कर रही है? नीट से जुड़े अनेक बड़े सवाल हवा में तैर रहे हैं और सारी उम्मीदें सर्वोच्च अदालत पर टिकी हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 15 जून, 1949

गंदी राजनीति

भारतीय राजनीति में पिछले दिनों से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिन्हें वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता। विदेशी सत्ता से लड़ते समय हमारी राष्ट्रीय संस्था का संगठन ऐसा सुन्दर रहा और हमारे बीच ऐसी एकता रही कि उस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमारी एकता को भंग करने के प्रयत्न न हुए हों या हमारे बीच मतभेद न हुए हों ऐसा नहीं कह सकते, तथापि परतंत्रता की छटपटाहट ऐसी थी कि उसने हम सबको एक राह का राही बनाये रखा। तकलीफें हमने उठाईं, पर उसमें भी शोभा थी। हम उससे विचलित नहीं हुए और ऐसा शानदार अपना सम्मिलित मोर्चा रखा कि आखिर विदेशी सत्ता ने हार मान ली। आपसी समझौते से वह यहां से हट गई और हम अपने घर के मालिक बने। घर चाहे बिगाड़ा जा चुका था, समस्याएं विकराल थीं, लेकिन हमारे स्वामित्व में शक नहीं रहा।

अपनी जिम्मेदारी अपने ही ऊपर आ पड़ने पर हमारा बोझ बढ़ गया। आलोचक से हमें निर्माता बनना चाहिए था। लेकिन तोड़-फोड़ करने वाली क्रांति के बजाय आपसी समझौते से जब हमें आजादी मिली, तो सचाई यह है, हमने परिवर्तन को पूरी तरह महसूस नहीं किया। आज भी हममें से बहुतेरे नहीं समझ पाते कि स्थिति पहले से भिन्न है और अब हमें दूसरों को दोष देने के बजाय खुद ही सब कुछ सम्हालना और करना है। नतीजा यह है कि बढ़ी हुई जिम्मेदारी का जो दबाव हम पर आया, उसे हम ठीक तरह से बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और या तो इस-उस की आलोचना में हमारा समय जाता है, या आपस में हम लड़ते हैं। अभी कल तक जो कंधे से कंधा भिड़ाकर काम कर रहे थे वो और एक-दूसरे को बलवान बनाते थे, उनका सत्ता या सुविधा के आसन पर बैठ हुओं के खिलाफ अहर्निश प्रचार तथा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न यही नहीं तो और क्या बताता है?

कहने को आज भी कांग्रेस ही सर्व-प्रमुख संस्था है और भारत तथा उसके प्रांतों एवं रियासती संघों में उसी का शासन है, परन्तु उसमें भी दल में उपदल कायम होने लगे हैं और आरोपों द्वारा एक-दूसरे की छीछालेदर की जा रही है। यह स्थिति सोचने की अपेक्षा करती है कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं?

दिल्ली में जल का अभाव है और उसके साथ हरियाणा व हिमाचल प्रदेश का विवाद चल रहा है। दरअसल, राज्यों के बीच जल विवाद बहुत पुराने हैं। 29 सितंबर, 1955 को लोकसभा में जल विवाद विधेयक और जल बोर्ड विधेयक पर खूब चर्चा हुई थी, पर समाधानों का आज भी इंतजार है।

आमने-सामने

केंद्र सरकार नदी जल विवाद सुलझाएगी

गुलजारीलाल नंदा | तत्कालीन केंद्रीय मंत्री

यहां स्कैन करें

- अपने देश में कुछ जल विवाद तो बीते 50 वर्ष से चले आ रहे हैं।
- हम जल विवादों को सुलझाने की पुख्ता व्यवस्था बना रहे हैं।
- न्यायाधिकरण बनेगा और दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है।

मैं इस विधेयक (जल विवाद विधेयक) का महत्व बता दूं। यह अंतरराज्यिक नदियों और इन नदियों से संबंधित विवादों के विषय में है। हमारे देश की ज्यादातर नदियां अंतरराज्यिक नदियां हैं। हमारे देश की अधिकांश समृद्धि तथा आर्थिक विकास इन जल संसाधनों के विकास पर निर्भर है और यदि नदियों के विकास में कोई चीज आड़े आती है, तो समस्त देश की उन्नति में गंभीर रुकावट पड़ जाएगी। अंतरराज्यिक नदियों के जल के काम में लाए जाने के संबंध में पहले भी विवाद हो चुके हैं। ...कुछ जल विवाद 50 वर्ष से चलते चले आ रहे हैं और अभी तक निपटाए नहीं गए हैं। ...यदि किसी महत्वपूर्ण सिंचाई तथा विद्युत परियोजना को लागू करने में एक वर्ष की भी देरी हो जाती है, तो समस्त राष्ट्र को उससे हानि पहुंचती है और करोड़ों रुपये की क्षति हो जाती है।...

फिलहाल, ऐसे विवाद को निबटाने के लिए योजना आयोग और करार की संभावना के अतिरिक्त अन्य कोई मशीनरी देश में इस समय नहीं है। संविधान बनाते समय यह अनुभव किया गया था कि यह आवश्यकता उत्पन्न होगी और इस प्रयोजन विशेष के लिए अनुच्छेद 262 में उपबन्ध किया गया। संसद को ऐसा विधान पारित करने के लिए शक्ति देने वाला एक विशिष्ट उपबंध किया गया है, जिसके द्वारा अंतरराज्यिक जल-विवाद के निबटारे के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। इसी के अनुसार, इस विधेयक को हमने यहां रखा है।...

यदि किसी राज्य सरकार को इस प्रकार की आशंका हो अथवा जिसको विवाद का सामना करना पड़ रहा हो या जो यह समझती हो कि राज्य या उसके निवासियों के हितों की अंतरराज्यिक नदी घाटी के जल के संबंध में हानि हुई है अथवा होने की संभावना है, तो नए कानून के तहत उसे संबोधित किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य सरकार इस मामले को केंद्रीय सरकार के पास भेज सकती है। तत्पश्चात केंद्र सरकार इस प्रश्न का भार अपने ऊपर लेती है। ऐसे विवाद के निबटारे के लिए जिन उपायों की व्यवस्था की गई है, वे बताए जा चुके हैं। ... अब न्यायाधिकरण को नियुक्त करना केंद्रीय सरकार का दायित्व हो जाता है। इस न्यायाधिकरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा केवल एक ऐसे व्यक्ति का नाम निर्देशन किया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों का न्यायाधिपति हो या रह चुका हो। इसके अतिरिक्त न्यायाधिकरण को विधिक सहायता देने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार को इसका दायित्व सौंपा गया है। इस संबंध में सिफारिश करने में केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकार का उपयोग किया जा सकता है।

हम कुछ ही समय बाद एक अन्य विधेयक (जल बोर्ड विधेयक) पर विचार करने जा रहे हैं। इन दोनों में क्या संबंध है? ...ये दोनों विधेयक एक दूसरे के पूरक हैं। वे अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित हैं। बहरहाल, यह विधेयक केवल विवादों के प्रश्न से ही संबंधित है। मुझे इस खंड की शब्दावली दुहराने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः विवाद जल के बंटवारे और नदियों से विद्युत पैदा करने की क्षमता के आवंटन के संबंध में उत्पन्न होते हैं। ये विवाद नदी के जल को एक मैदान से दूसरे मैदान में मोड़ने पर भी उत्पन्न होते हैं। विवाद का दूसरा कारण यह है कि परियोजना को लागू करने के लिए अपेक्षित निर्माण किसी अन्य राज्य में करने पड़ते हैं और उससे लाभ दूसरे राज्य के लोगों को होता है। अतः जो राज्य जल या विद्युत आदि से लाभ उठाने का अधिकारी होता है, वह तब तक उससे लाभ नहीं उठा सकता, जब तक कि दूसरा राज्य उससे सहयोग न करे।... विद्युत परियोजना में विभिन्न स्थितियों का प्रश्न भी पैदा हो सकता है। एक स्थिति एक राज्य में हो सकती है और दूसरी दूसरे राज्य में। ऐसी दशा में समायोजन की भी जरूरत होती है।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

अंतिम निर्णय अदालत को करने दिया जाए

पंडित ठाकुर दास भार्गव | वरिष्ठ राजनेता व सांसद

यहां स्कैन करें

- जल विवादों को न राज्य सरकार सुलझा पाई और न भारत सरकार।
- कहीं पानी का इंतजाम किया गया और कहीं पानी से महरूम रखा गया।
- कोई मजबूत शक्ति होनी चाहिए, जो इन विवादों का समाधान करे।

हमारे हिन्दुस्तान में जिस कदर परमात्मा ने बरकतें दी हैं, उसका अंदाजा हम सब लोग लगा सकते हैं। हिन्दुस्तान में बड़े से बड़े दरिया, बड़े से बड़े पहाड़, बड़ी से बड़ी नहरें और बहुत सी दूसरी चीजें ऐसी हैं, जो शायद दूसरे मुल्कों को नसीब नहीं हैं।... परमात्मा की कृपा से हम इतने खुशनसीब हैं कि हमारे मुल्क में हवा, पानी, रोशनी, धूप और ऐसी-ऐसी दूसरी चीजें मौजूद हैं, जो इंसानी जरूरतों के लिए निहायत जरूरी हैं...।

वंदे मातरम् में हम गाया करते हैं, सुजलां, सुफलां, शस्य श्यामलां आदि, आदि, पर यह सब होते हुए भी हम अपने को मुसीबतों में पाते हैं।... पानी ही हमारी आफत बना हुआ है। गरमी के मौसम में हम देखते हैं कि धूप ही हमारी मुसीबत का बायस बनी हुई होती है, पर मुझे यकीन है कि अगर हम इन चीजों का सदुपयोग करें, तो हम अपने देश में इंसान की जरूरत की वे चीजें पैदा कर सकते हैं, जो दूसरे देशों को नसीब नहीं हैं।

बतलाया जाता है कि इस देश में हम अपने पानी का सिर्फ सात फीसदी काम में लाते हैं और 93 फीसदी बगैर इस्तेमाल हुए समुद्र में चला जाता है। हम देखते हैं कि हमारे यहां ऐसे इलाके हैं, जो यहां सदन में रोज झगड़ते हैं कि हमारे यहां पानी नहीं है, इसलिए हम पिछड़ गए हैं। इससे मालूम होता है कि कहीं तो हमारे देश में पानी बहुत ज्यादा है और कहीं पानी बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूं कि यह हर एक हिन्दुस्तानी के लिए चुनौती है कि वह अपने देश की इन नेमतों को इस तरह से इस्तेमाल करे कि ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हों। मुझे याद है कि जब सन 1946 में भाखरा डैम बनाया जा रहा था, उस वक्त की पंजाब सरकार ने गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा था कि अगर हमको 70 करोड़ रुपया और आप दें, तो हम हिन्दुस्तान की सारी जरूरत लायक अनाज पैदा कर सकते हैं। अगर पानी का ठीक इंतजाम हो, तो अकेला पंजाब इतना अनाज पैदा कर सकता है कि इस देश में किसी के दिमाग में भी यह बात न आए कि यहां कभी अनाज की कमी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं कि अगर वहां पानी का ठीक से इंतजाम हो, तो वे इतना गल्ला पैदा कर सकते हैं, जो इस देश की जरूरत से काफी ज्यादा होगा।

...लेकिन जहां उत्तर-पश्चिम पंजाब में पानी का इंतजाम किया गया, वहीं दक्षिण पूर्व पंजाब को पानी से महरूम रखा गया। ...सिंध और पंजाब में भी पानी का झगड़ा चला। इस झगड़े में बहुत अर्से तक गवर्नमेंट आफ इंडिया उलझी रही। सिन्ध वाले कहते थे कि अगर पंजाब में यह डैम बनाया जाएगा, तो उनकी नहरों के पानी का स्तर नीचा हो जाएगा। यह मामला विलायत तक गया और आखिर यह फैसला हुआ कि आर्बिट्रेटर मुकर्रर करो, पंजाब इतना रुपया सिन्ध को दे, उसके बाद यह तय होगा कि यह डैम बने या न बने। ...मतलब यह है कि वह दक्षिण पूर्व पंजाब का ऐसा इलाका है, जिस पर 40 साल से न वहां की गवर्नमेंट ने तवज्जो दी, न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तवज्जो दी और न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने तवज्जो दी। एक गवर्नर साहब ने तो हिसार में आकर यहां तक फरमा दिया कि अगर इस जिले को हम पानी दे दें, तो हम को रिक्रूट कहां से मिलेंगे, यहां जो अच्छे मवेशी पैदा होते हैं, वे कैसे पैदा होंगे? इन वजूहात से हिसार जिले को पानी से महरूम रखा गया। ...ये इंटर स्टेट झगड़े बहुत जबरदस्त हैं। ...मामलों को तय नहीं होने दिया जाता। हमारे यहां झगड़ा चल रहा है कि गुड़गांव से होकर नहरें उत्तर प्रदेश को चली जाती हैं, पर हमारे यहां के गांवों को जल से महरूम रखा जाता है।

...कोई शक्ति होनी चाहिए, जो इन विवादों का समाधान करे। हमने संविधान में लिख दिया है कि इन झगड़ों का फैसला करने का अख्तियार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं होगा। मेरा निवेदन है, अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ही करे।... केंद्र सरकार उसके निर्णय को गलत कहकर रद्द नहीं कर सकती।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

कृत्रिम बुद्धिमता पर निर्भरता से कितनी बदलेगी पत्रकारिता

संजय द्विवेदी | पूर्व महानिदेशक, आईआईएमसी, दिल्ली

यहां स्कैन करें

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नित नए रूप में सामने आ रहा है। अब इसकी 'टेक्स्ट टु स्पीच' फीचर की बदौलत भारतीय न्यूजरूम में भी मशीन को इंसानी चेहरे में ढालकर खबरें पेश की जाने लगी हैं। आज मीडिया कंपनियां अपने कंटेंट को अधिक बेहतर बनाने से लेकर बुलेटिन प्रसारित करने तक में एआई का सहारा लेने लगी हैं। इससे एक तरफ तो काम आसान और तेजी से पूरे होने लगे हैं, तो दूसरी तरफ कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं, जिनमें साख का संकट सबसे पहले है।

इंसान की जगह मशीन के इस्तेमाल का पहला खतरा इंसानों पर ही पड़ता है। 'न्यूजजीपीटी' दुनिया का पहला समाचार चैनल है, जिसका पूरा कंटेंट एआई द्वारा तैयार किया जा रहा है। चैनल के प्रमुख एलन लेवी ने इसे खबरों की दुनिया का गेमचेंजर कहा था, क्योंकि न इसमें कोई रिपोर्टर है और न ही यह किसी से प्रभावित है। यही बात मीडिया जगत में काम करने वालों के लिए बड़ा खतरा है। जैसे-जैसे मीडिया के क्षेत्र में एआई का प्रभुत्व बढ़ रहा है, वहां मौजूदा लोगों की नौकरियां पर तकनीक का कब्जा होने की आशंका बढ़ रही है। लेखन, संपादन, एंकरिंग, प्रस्तुति तक के सारे कामों में एआई का सहारा लिया जा रहा है।

बीबीसी द्वारा प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, साल 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ी संख्या में *एमएसएन* वेबसाइट के लिए लेखों के चयन, क्यूरेटिंग, हेडलाइन तय करने और एडिटिंग करने वाले पत्रकारों की जगह स्वचालित सिस्टम को अपनाने की योजना बनाई। इस योजना के सफल होने के बाद लगभग 50 न्यूज प्रोड्यूसर्स को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ठीक इसी तरह, साल 2022 के अंत में अमेरिकी टेक्नोलॉजी न्यूज वेबसाइट *सीएनईटी* ने एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दर्जनों फीचर लेख तैयार किए और प्रकाशित किए। एसोसिएटेड प्रेस ने भी अपनी कहानियों के लिए एआई का इस्तेमाल किया। ये सारी बातें यही बताती हैं कि कैसे मीडिया पेशेवरों की नौकरियां एआई लील रही है।

भारत समेत कई देशों में न्यूज एंकर के तौर पर कंप्यूटर जनित मॉडल, यानी एआई एंकर समाचार पढ़ते नजर आने लगे हैं। बहुत हद तक इंसानी तौर पर दिखने वाले

आज मीडिया कंपनियां अपने कंटेंट को बेहतर बनाने से लेकर बुलेटिन प्रसारण में एआई का सहारा लेने लगी हैं। इससे काम तेजी से पूरे होने लगे हैं, मगर साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं।

ये एंकर 24 घंटे और सातों दिन डेटा के आधार पर काम कर सकते हैं। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर सना के लॉन्च के समय इसी तरह के शब्द कहे गए थे कि यह बिना थके लंबे समय तक काम कर सकती है। *द गार्जियन* के अनुसार, साल 2018 में चीन की न्यूज एजेंसी *शिन्हुआ* पहला एआई न्यूज एंकर दुनिया के सामने लेकर आई। इस एजेंसी के किउ हाओ पहले एआई एंकर थे, जिसने डिजिटल वर्जन पर समाचार प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष चीन ने एआई महिला न्यूज एंकर को भी लॉन्च किया। खबरों में कहा गया था कि इस एआई न्यूज एंकर ने हजारों न्यूज एंकर्स से स्किल सीखे हैं और वह 365 दिन 24 घंटे लगातार खबरें बता सकती है। चीन के अलावा कुवैत भी एआई न्यूज एंकर लॉन्च कर चुका है। रूस का *स्वोए टीवी* भी ऐसा कर चुका है।

यह स्थिति तब है, जब एआई अपने शुरुआती चरण में है, लिहाजा यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पत्रकारिता को किस तरह से बदलेगी, क्योंकि आज क्लिकबेट (सनसनी पैदा करने वाली हेडलाइन लगाने) और प्राइम टाइम में चिल्लाने वाली पत्रकारिता का दौर है। ऐसे में, क्या रोबोट इंसानी रवैये के इतर विवेक के साथ पत्रकारिता करेंगे? दुनिया के प्रसिद्ध मीडिया स्तंभकार पामेल फिलिपोज ने कहा है कि एआई बहुस्तरीय समस्या पैदा कर सकती है और अधिक दुष्प्रचार फैला सकती है। कई पत्रकार और मीडिया पेशेवर भी यही मानते हैं कि एल्गोरिद्म और ऑटोमेशन पर बढ़ती निर्भरता से पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम हो सकती है।

स्पष्ट है, एआई न्यूज एंकर या पत्रकारिता में एआई की निर्भरता सूचना क्षेत्र के भविष्य के लिए दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ, इससे मीडिया के नएपन और संचार के क्षेत्र की अपार संभावनाएं पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं इसे नैतिक और जिम्मेदारी तय करने के लिए, नियमन और निरीक्षण की आवश्यकता भी है। फिलहाल, इसका बढ़ता प्रभाव सूचनाओं से मानवीय पक्ष को खत्म करने वाला ही ज्यादा नजर आ रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अपनेपन में अपमान कहां

जब कोई व्यक्ति आपके साथ असभ्य और रूखा व्यवहार करता है, तब आप क्या करते हैं? विचलित हो जाते हैं, आप भी रूखेपन से जवाब देते हैं, हताश हो जाते हैं, भविष्य में उस व्यक्ति से दूर रहने लगते हैं या फिर उसे उचित व्यवहार की शिक्षा देते हैं। मगर इनमें से कुछ भी, कोई भी तरीका आपको सबल नहीं बनाएगा। फिर उपाय क्या है?

किसी के रूखे व्यवहार को इस दृष्टि से देखिए कि उसका व्यवहार उसके तनाव और असंवेदनशीलता को प्रकट करता है। उसके पालन-पोषण की ओर इशारा करता है। उसमें ज्ञान का अभाव दर्शाता है। अपने ही मन, संवेदनाओं को समझने की उसकी अयोग्यता को दर्शाता है। यह आपको जताता है कि दूसरों से ऐसा व्यवहार नहीं करना है। आपके लिए एक अवसर है कि रूखेपन का स्वागत कीजिए, उसे स्वीकार करिए। अगली बार कोई आपके साथ रूखा व्यवहार करे, तो ध्यान रखें कि आप विचलित नहीं होंगे। यदि आप रूखेपन को स्वीकार कर सकते हैं, तो कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता।

अपमान आपको सबल बनाता है। जब आपमें अपनेपन का भाव रहता है, तब आप अपमानित नहीं महसूस करते। जितना अधिक आपमें अहं है, उतना ही अधिक आप अपमान महसूस करते हैं। मगर जब आप बच्चे जैसे हो जाते हैं, विशाल अपनत्व का भाव रखते हैं, तब आप अपमान नहीं महसूस करते। इसी प्रकार, जब आप सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, अपने अहं के प्रति नहीं, तब भी आप अपमानित नहीं महसूस करते। इसलिए अपमान से निकलने का उपाय है कि अपमानित हो जाएं, बच्चे जैसे हो जाएं, ईश्वर के प्रेम में डूब जाएं।

श्री श्री रविशंकर

दलित राजनीति की एक नई उम्मीद

मायावती के राजनीतिक पराभव के साथ ही नई चेतना लेकर चंद्रशेखर आजाद का अभ्युदय हिंदी प्रदेश में नई दलित राजनीति की उम्मीद पैदा करता है। इस बार बेहद जटिल चुनावी माहौल में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उम्मीदवार के रूप में संसद के लिए आजाद का चुना जाना न सिर्फ प्रतीकात्मक है, वरन महत्वपूर्ण भी है। वह बहुकोणीय मुकाबले में भाजपा, सपा, बसपा, तीनों दलों को हराकर विजयी हुए हैं। जाहिर है, बसपा की लंबी सियासी निष्क्रियता से निराश और हताश दलित समुदाय ने चंद्रशेखर की बातों में रोशनी देखी और धीरे-धीरे वह उनकी ओर आकर्षित हुआ। आजाद सरकारी दमन का सामना करते हुए निर्भीक होकर दलित जागरण के अपने न्यायसंगत ध्येय की दिशा में बढ़ते रहे। विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक ने उन्हें अपने साथ शामिल नहीं किया, हालांकि उनके संघर्ष से इंडिया को और इंडिया के प्रति जनता के झुकाव से आजाद समाज पार्टी को मदद मिली है। सबसे उल्लेखनीय बात है कि भारत के अति ताकतवर प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र वाराणसी से डेढ़ लाख वोट से जीते और चंद्रशेखर भी नगीना से डेढ़ लाख वोट से ही जीते! आजाद का जीतना दलित राजनीति में एक नए दौर के आविर्भाव का द्योतक है।

अजय तिवारी, टिप्पणीकार

उम्मीद की लौ

उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद व कैराना से इकरा हसन की जीत के गहरे निहितार्थ हैं। चंद्रशेखर में गजब का आत्मविश्वास और संघर्ष का जज्बा है। एक आम आदमी की भाषा में बात करते हुए सीमा के भीतर दृढ़ता देखकर मेरी कामना थी कि ऐसे लोगों को संसद में होना चाहिए। विरासत की बात तो दूर, इनको न मायावती ने और न ही अखिलेश ने प्रश्रय दिया। यह युवा अकेले शेर की तरह लड़ता हुआ संसद में पहुंचने में सफल रहा। इसी तरह, इकरा हसन ऐसी मुस्लिम युवती हैं, जो इंग्लैंड से पढ़ी हैं। एक ऐसे समुदाय में, जिसे अपेक्षाकृत बंद समाज माना जाता है, इकरा हसन एक प्रेरक प्रतीक बन सकती हैं। उनकी शालीनता और हर समुदाय की युवतियों व स्त्रियों से अपनापे का व्यवहार समाज की सोच को प्रभावित करेगा। यह बात जरूर है कि चंद्रशेखर जैसे नेता को अपने संकल्प के साथ संसद जाने वालों को ही राजनीति बदल देती है। मगर इसका यह अर्थ नहीं कि हम हर कोशिश को संदिग्ध मान नकारात्मक ही सोचें। अगर मान लें कि ऐसा ही होता है, तब भी हम अगले किसी चंद्रशेखर आजाद और इकरा हसन की प्रतीक्षा करेंगे। गहन और विराट अंधकार में हम तो एक टिमटिमाती लौ से ही आह्लादित होने वाले लोग हैं।

कमेंदु शिशिर, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

चंद्रशेखर आजाद

वंचितों की मुक्ति का कोई विजन नहीं

चंद्रशेखर आजाद को अभी ही दलित राजनीति का युवा और भरोसेमंद चेहरा बता देना जल्दबाजी होगी। इसकी एक बड़ी वजह तो यही है कि खुद दलितों का उन पर विश्वास नहीं जम सका है। अगर यह भरोसा बना होता, तो छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चंद्रशेखर की पार्टी आसपा को हार नहीं मिलती। चंद्रशेखर की जीत मूलतः उनकी निजी कोशिशों का नतीजा है। संघर्ष को उन्होंने अपना हथियार बना लिया है, इसलिए लोगों ने उनको पसंद किया, लेकिन यह पसंद व्यक्तिगत स्तर पर है, पार्टी के स्तर पर नहीं। अगर उनको वाकई दलित राजनीति का एक स्थायी चेहरा बनना है, तो सबसे पहले दलित मुक्ति का एक व्यावहारिक नजरिया पेश करना होगा। दलित चिंतक कंवल भारती के शब्दों में कहें, तो वह तात्कालिक परिस्थितियों पर ही प्रतिक्रिया देते हैं, निजीकरण, उदारीकरण से लेकर दलित उत्थान के बारे में उनका अपना कोई विचार अब तक सामने नहीं आ सका है।

वास्तव में, जिस तरह से बिहार की पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को जीत मिली है, चंद्रशेखर की जीत को भी इसी चश्मे से देखा जाना चाहिए। इसका दलित राजनीति पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह आक्रामक तो हैं, पर संगठन क्षमता के मामले में उन्हें अभी खुद को साबित करना है। यहां हमें इस सच को भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज में बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति अब भी ठीक-ठाक है। माना यही जाता है कि अब भी उसके पास तकरीबन नौ फीसदी कोर वोटर हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी की तो बस शुरुआत ही हुई है।

इसका साफ संकेत है कि बसपा के दिन अभी नहीं लदे हैं। चुनावी हार के बाद जिस तरह से मायावती सक्रिय हो गई हैं, वह एक बड़ा संकेत है। बीच चुनाव में ही उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी तमाम दायित्वों से मुक्त कर दिया था। स्पष्ट है, वह अपनी कमजोर पड़ती उपस्थिति को मजबूत बनाना चाहती हैं और इसके लिए प्रभावी कार्य-योजना तैयार की जा रही है। माना यह जा रहा है कि वह अब कहीं बड़े दिल के साथ उम्मीदवारों का चयन करेंगी, क्योंकि 2007 में जब वह सत्ता में आई थीं, तब उनके साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और गैर-जाटव, तमाम वर्गों के लोग थे। एक बार फिर वह इसी रणनीति को अपना सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो चंद्रशेखर की राह और मुश्किल हो जाएगी। देश की दलित राजनीति में मायावती एक स्थापित नाम हैं, जबकि चंद्रशेखर को जमीनी स्तर पर अभी अपनी पहचान बनानी है।

रंजीत राम, टिप्पणीकार

दैनिक जागरण

कड़े फैसले ही बड़े परिवर्तन का निमित्त बनते हैं

एक साथ चुनाव का एजेंडा

यह शुभ संकेत है कि एक देश-एक चुनाव संबंधी रिपोर्ट शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष रखी जा सकती है। इसका अर्थ है कि मोदी सरकार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के बाद भी अपने अन्य एजेंडों के साथ एक साथ चुनाव कराने के अपने एजेंडे को लेकर भी गंभीर है। इस गंभीरता का पता इससे भी चलता है कि कानून मंत्रालय ने अपने लिए सौ दिन का जो एजेंडा तय किया है, उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना भी है। कानून मंत्री ने अपने इस एजेंडे को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए यह आशा व्यक्त की थी कि सहयोगी दल भी इस पहल का समर्थन करेंगे। चूंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते चले आ रहे हैं, इसलिए तेलुगु देसम पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अन्य सहयोगी दलों और विशेष रूप से जनता दल-यू से भी इस पहल को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसका कारण कुछ माह पहले जनता दल-यू के नेताओं की पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से हुई मुलाकात है। इस मुलाकात में इस दल के नेताओं ने एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन किया था। ज्ञात हो कि राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली समिति ने एक साथ चुनाव के विषय पर विचार करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। एक तथ्य यह भी है कि विगत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक साथ चुनाव की पहल का समर्थन कर चुके हैं।

यह सही है कि कई विपक्षी दल एक साथ चुनाव के विचार पर आपत्ति जताते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी यह आपत्ति विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति से ही अधिक प्रेरित है। वे इस पर ध्यान देने के लिए जानबूझकर तैयार नहीं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने से सभी दलों के राजनीतिक एवं आर्थिक हित सधेंगे और राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ भी कम होगा। इसके अतिरिक्त आम जनता की परेशानी भी कम होगी। यह ठीक है कि एक साथ चुनाव के विचार को अमल में लाने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे, लेकिन यह ऐसा कोई काम नहीं, जिसे न किया जा सके। उचित यह होगा कि जो दल एक साथ चुनाव के विचार का विरोध कर रहे हैं, वे दलगत राजनीति से ऊपर उठें और राष्ट्रीय हितों की चिंता करें। उन्हें ऐसा इसलिए करना चाहिए, क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। विपक्षी दलों की ओर से दिए जा रहे इन तर्कों का कोई मूल्य-महत्व नहीं कि एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र एवं संविधान की भावना के प्रतिकूल है और इससे राष्ट्रीय दलों को अधिक लाभ मिलेगा। हाल के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तेलुगु देसम पार्टी को आंध्र प्रदेश में मिली सफलता यही बताती है कि यह एक थोथा तर्क है।

नदियों पर कब्जे

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नाला बन चुकी कुकरैल नदी पर अवैध कब्जा हटाने के लिए राज्य सरकार ने जो इच्छाशक्ति दिखाई है, उसी का परिणाम है कि इस नदी के पुनर्जीवन की संभावनाएं बलवती हो उठी हैं। एक समय था जब गोमती की इस सहायक नदी में हर समय पानी रहता था, लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और नेताओं ने भी ऐसे लोगों को संरक्षण देकर नदी की भूमि पर बसाया। नदी पर किस कदर कब्जा था इसे इस बात से समझा जा सकता है कि चार मंजिला भवन तक खड़े हो गए। छह माह पहले इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इन भवनों पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन अब कब्जे से बसे एक मोहल्ले का एक बड़ा हिस्सा खाली कराया जा चुका है। यह केवल सरकारी कार्रवाई ही नहीं, प्रदेश की उन नदियों के लिए भी जीवन का संदेश है, जिन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। कुकरैल उन सभी छोटी नदियों के लिए मानदंड बनेगी जो खत्म हो गई हैं या फिर खत्म होने की कगार पर हैं। प्रदेश के लगभग हर जिले में ऐसी नदियां हैं जो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और इसका कारण उन पर हुआ अतिक्रमण ही है। महानगरों में गंगा और यमुना किनारे हजारों भवन अतिक्रमण कर बना लिए गए और यह विडंबना ही है कि वोटों की चाह में नेताओं ने वहां सड़क, बिजली, पानी तक उपलब्ध करा दिया। यह अलग बात है कि हर बाढ़ में ऐसी आबादी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले छोटी नदियों को मुक्त करना जरूरी है क्योंकि इनका प्रवाह लौटा तो बड़ी नदियों में भी प्रवाह बना रहेगा। सरकार ने कुकरैल नदी को जिंदगी देने के लिए जो प्रयास शुरू किए हैं, वह अन्य नदियों तक भी पहुंचना चाहिए।

कुकरैल उन सभी छोटी नदियों के लिए मानदंड बनेगी जो खत्म हो गई हैं या फिर खत्म होने की कगार पर हैं

आतंक के नए दौर की वापसी

दिव्य कुमार सोती

पाकिस्तान ने जम्मू में आतंकी हिंसा का जो सिलसिला प्रारंभ किया है, वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है

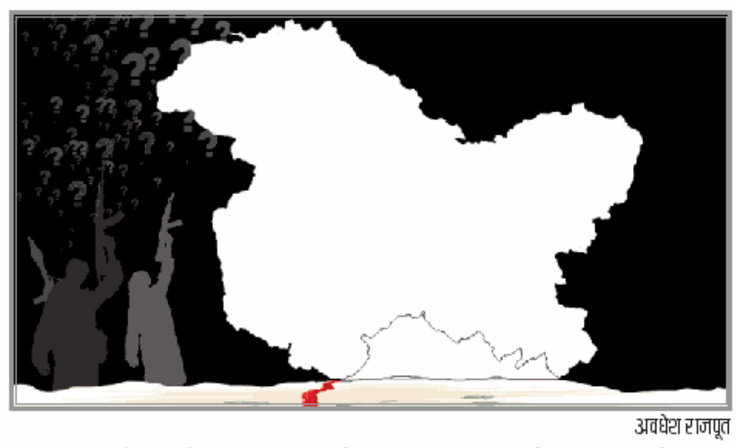

अवधेश राजपूत

पीर-पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित जम्मू क्षेत्र में फिर से आतंकी हमलों का सिलसिला चल निकला है। जम्मू के रियासी जिले में हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर ऐसे ही एक हमले में नौ लोगों की जान चली गई और 33 घायल हो गए। इसके अगले ही दिन कठुआ के हीरानगर में आतंकियों ने एक हिंदू गांव पर हमला किया, परंतु सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कठुआ में इस हमले के समय ही वहां से लगभग 200 किमी दूर डोडा में सेना और पुलिस के संयुक्त नाके पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें छह जवान घायल हो गए। एक घंटे के घमासान के बाद आतंकी भाग निकलने में सफल रहे। इनमें से रियासी हमला उस समय हुआ, जब दिल्ली में नई राजग सरकार शपथ ले रही थी। इस हमले को शपथ ग्रहण से भी जोड़कर देखा गया। इसके पहले पुंछ-राजौरी में भी कई आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में एक समानता यह है कि इनमें आतंकियों ने सड़क के दोनों ओर के पहाड़ों से सुरक्षा बलों एवं नागरिक वाहनों को निशाना बनाया और हमले को अंजाम देने के बाद पहाड़ियों के घने जंगलों में ओझल हो गए। इस कारण सेना द्वारा चलाए गए सघन तलाशी अभियानों से खास परिणाम नहीं निकले।

जम्मू संभाग में आतंकी हमलों के तौर-तरीकों में पेशेवर बलों की छाप स्पष्ट दिखी। इनमें बख्तर भेदने वाली गोलियों और अमेरिकी मूल की एम-4 उन्नत राइफलों का भी उपयोग देखा गया। पांच मई को वायुसेना के काफिले पर हमले में वांछित आतंकी हादून पाकिस्तान सेना के विशेष कमांडो दस्ते स्पेशल सर्विस ग्रुप (एसएसजी) का सदस्य रह चुका है। इसी तरह हीरानगर हमले के दौरान मारे गए रावलाकोट के रहने वाले आतंकी रेहान अली की पाकिस्तान में इंटरनेट मीडिया पर फौजी वर्दी में तस्वीरें वायरल हैं। उसे फौजी बताकर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। आशंका यही है कि पुंछ-राजौरी क्षेत्र में फैले पीर-पंजाल के पहाड़ों में स्थित घने जंगलों में ठीक-ठाक संख्या में जिहादी आतंकी छिपे हुए हैं। ये जम्मू क्षेत्र में घात लगाकर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और तेजी से वापस घने जंगलों में ओझल हो जाते हैं। ये आतंकी पाकिस्तानी फौज के विशेष बलों में काम कर चुके हैं। इन्हें स्थानीय इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों का सहयोग भी प्राप्त है। ये स्थानीय लोग आतंकियों को न सिर्फ सैन्य आवाजाही की जानकारी मुहैया कराते हैं, बल्कि कड़ाके की सर्दियों के दौरान उन्हें रहने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं।

समस्या यह है कि सैकड़ों वर्ग किमी में फैले इन जंगलों में छिपे इन आतंकियों, जिनकी संख्या का अभी सही-सही अनुमान नहीं है, का सफाया करने के लिए यदि बड़ा सैन्य अभियान चलाया जाए तो आशंका है कि हमें बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को खोना पड़े। हालांकि वायु सैन्य संसाधनों जैसे शरीर की गर्मी पकड़ने वाले टोही और आत्मघाती ड्रोनों आदि का उपयोग कर कुछ सीमा तक संभावित नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है।

जम्मू क्षेत्र में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर अंकुश न लगाया गया तो उससे सटे पंजाब और हिमाचल के इलाकों पर भी इसका असर पड़ सकता है। यदि सैन्य अभियान में आतंकियों का सफाया कर दिया जाए तो भी कुछ वर्षों में फिर से यही स्थिति होगी, क्योंकि पिछला अनुभव बताता है कि विभिन्न भौगोलिक और अन्य कारणों से सीमा पार घुसपैठ पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। भारत को सीमा पार आतंकवाद से लड़ते हुए यह लगभग चौथा दशक है, परंतु हम अभी तक इसकी स्थायी काट नहीं तलाश पाए। मोदी सरकार ने पहली बार हिम्मत दिखाते हुए नियंत्रण रेखा पार करके पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश अवश्य दिया था, जिसके बाद बड़े आतंकी हमलों में गिरावट देखी गई थी। इसके बावजूद ऐसे जवाबी हमले स्वाभाविक रूप से घुसपैठ के उन मार्गों को बंद नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को उपलब्ध हैं। अगर इस सीमा पार आतंकवाद को बंद करना है तो हाजी पीर दर्रे और घुसपैठ के अन्य मार्गों को भारत को अपने नियंत्रण में लेना होगा। इसके बिना अनुच्छेद-370 को हटाने का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आतंकी जम्मू-कश्मीर के बाहर से काम की तलाश में वहां पहुंच रहे कामगारों की हत्या कर रहे हैं। जिन विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को सरकार द्वारा नौकरियां दी गईं, उन्हें भी आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि सही समय आने पर सीमा पार जो भी कदम उठाया जाए, वह स्थायी सामरिक लाभ और सीमा पार घुसपैठ पर हमेशा के लिए लगाम लगाने के लिए होना चाहिए।

रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान का सामरिक महत्व पश्चिम और चीन, दोनों के लिए फिर से बढ़ गया है। पाकिस्तान बनाने वाले भी यह जानते थे कि उसका आर्थिक औचित्य कम ही है और उसे अपने भूराजनीतिक महत्व के बल पर ही अपनी अहमियत बनाए रखनी होगी। ऐसे में पाकिस्तान ने जम्मू में आतंकी हिंसा का जो असामान्य दौर प्रारंभ किया है, वह किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एलएसी पर चीन के साथ अभी भी सैन्य तनाव बना हुआ है। कई स्थानों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हैं। वहीं, पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर भारत का संघर्ष विराम समझौता लागू है। यह समझौता तब हुआ था, जब भारत-चीन तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान ने उन दिनों अपनी बेहद खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत के साथ किसी प्रकार का टकराव मोल लेना सही नहीं समझा था। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से तब फौज के रिश्ते भी खराब चल रहे थे। पाकिस्तानी जनरल इमरान को हटाने की योजना बना रहे थे, जिसमें आंतरिक अस्थिरता की आशंका थी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी फौज भारत-चीन सैन्य तनाव के बीच भारत से संघर्ष विराम को तैयार हुई थी। अब वे स्थितियां बदल चुकी हैं। इस आशंका से इन्कार नहीं कि पाकिस्तानी फौज अब इस संघर्ष विराम समझौते से किनारा कर चीन के साथ मिलकर भारत पर दो मोर्चों पर सैन्य दबाव बनाना चाहती हो।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम

प्रणय कुमार

पाठ्यक्रम में जो बदलाव जरूरी हैं वे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान अविलंब होने चाहिए

प्राथमिकता वाले काम की अनदेखी। फाइल

पिछले 10 वर्षों में देश ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु शिक्षा का क्षेत्र कमोबेश उपेक्षित ही रहा। नई सरकार में फिर से शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू करेंगे। इसका अर्थ है कि अभी तक तेजी नहीं दिखाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार-प्रसार तो खूब हुआ, परंतु धरातल पर उसका क्रियान्वयन, प्रभाव और परिणाम दिखाई नहीं देता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भावी पीढ़ी के भविष्य और निर्माण से जुड़ा विषय समाज और सरकार की प्राथमिकता-सूची में निचले क्रम पर दिखता है। राजनीतिक दलों के लिए जब सत्ता-प्राप्ति का सीमित और तात्कालिक लक्ष्य सर्वोपरि हो जाता है, तब विचारों के गठन और व्यक्ति-निर्माण का प्रश्न पीछे छूट जाता है। निःसंदेह मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में अधिक आइआइटी, आइआइएम, मेडिकल कालेज एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले हैं, परंतु क्या हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा की स्थिति, शिक्षण का स्तर, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, विश्व में उसकी साख एवं विश्वसनीयता, वर्षों से लंबित एवं रिक्त पदों पर नई नियुक्ति, मौलिक शोध एवं नवोन्मेष, कौशल एवं तकनीक की दक्षता, अध्यापकों का प्रशिक्षण, नियमित सत्र, अनुशासित शैक्षिक परिवेश, रोजगारपरक शिक्षा, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त परीक्षा तथा भारी धन खर्च कर भी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की बढ़ती लालसा आदि पर समाधानपरक काम नहीं किया जाना चाहिए? उम्मीद थी कि बीते दस वर्षों की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में पाठ्यक्रम में सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल की जाएगी, परंतु इस दिशा में अभी तक खानापूर्ति ही अधिक हुई है। जहां बुनियाद बदलने की शर्त हो, क्या वहां केवल साज-सज्जा से काम चलाया जा सकता है? आवश्यकता संशोधन-संक्षिप्तीकरण की नहीं, अपितु राष्ट्र की आकांक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन से जुड़ी है।

निःसंदेह भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीतिशास्त्र और दर्शन जैसे मानविकी के विभिन्न विषयों के माध्यम से सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मजबूती मिलनी चाहिए। इसी तरह भारतीय ज्ञान-परंपरा को पोषण मिलना चाहिए, अस्तित्ववादी विमर्श एवं विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए। सहयोग, संतुलन, सामाजिकता, संवेदनशीलता एवं देशभक्ति जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में व्याप्त बहुलता, शांति एवं सह-अस्तित्व के मूल स्रोत की पहचान की जानी चाहिए।

यह कैसी विडंबना है कि हमारे बौद्धिक-राजनीतिक-अकादमिक विमर्श में 'भारतवर्ष में व्याप्त विविधता में एकता' का उल्लेख तो भरपूर किया जाता है, परंतु उसे पोषण देने वाले मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, प्रमुख घटकों, मंदिरों, मठों, तीर्थों और त्योहारों आदि की कोई चर्चा नहीं होती? क्या पाठ्यक्रम में इन्हें यथोचित स्थान नहीं मिलना चाहिए? इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विवेचना की गई है और भारतीयों के साहस, संघर्ष एवं प्रतिरोध को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। देश के वैशिष्ट्य एवं गौरवशाली अध्यायों की अपेक्षा केवल दिल्ली-केंद्रित इतिहास को केंद्र में रखा गया है तथा देश के अमर सपूतों, बलिदानी धर्मरक्षकों, महान संतों, समन्वयवादी समाज-सुधारकों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों को नेपथ्य में रख, दो-चार का महिमामंडन किया गया है! क्या यह सत्य नहीं कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था और पाठ्य-सामग्रियों में आस्था एवं विश्वास पर संदेह, अनास्था एवं अविश्वास को वरीयता दी गई है? उसमें अधिकार भाव की प्रबलता है, कर्तव्य-भावना गौण है। वर्गीय चेतना के नाम पर अलगाववादी वृत्तियों तथा पारस्परिक मतभेद एवं संघर्ष को शिक्षा के माध्यम से पाला-पोसा-बढ़ाया गया है। मूल बनाम बाहरी, उत्तर बनाम दक्षिण, राष्ट्रभाषा बनाम क्षेत्रीय भाषा जैसी कृत्रिम लड़ाइयां शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के माध्यम से खड़ी की गई हैं। परिवार, समाज एवं राष्ट्र की इकाइयों को परस्पर विरोधी मानने वाली खंडित एवं विभेदकारी दृष्टि के स्थान पर क्या शिक्षा-व्यवस्था में समन्वय-समग्रता पर आधारित सनातन दृष्टि को स्थान नहीं मिलना चाहिए?

स्वतंत्र भारत की अनेक गौरवशाली उपलब्धियां पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की बाट जोह रही हैं। क्या भारत की सफल लोकतांत्रिक यात्रा के क्रमिक सोपानों का उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए? क्या आपातकाल के दौरान किए गए संघर्ष और यातनाओं की व्यथा-कथा पढ़कर लोकतंत्र के प्रति भावी पीढ़ी की आस्था मजबूत नहीं होगी? क्या चंद्रयान, मंगलयान की सफलता की गाथा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयोग, अनुसंधान और व्यवहार की कसौटी पर कसे जाने वाले गणित और विज्ञान जैसे विषयों में भी बीते कई दशकों से परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन-अध्यापन की भाषा के रूप में मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं की पैरवी की गई है, परंतु अभी तक इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ है। विभिन्न स्तरों की परीक्षा-पद्धति, प्रश्नपत्र के प्रारूप, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि में सुधार आवश्यक हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या विकराल होती जा रही है। अभी नीट का मामला सुर्खियों में है। यह दर्शाता है कि शिक्षा के साथ परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं हो सके हैं। यह समय की मांग है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिक्षा-क्षेत्र में सुधारों को गति एवं दिशा मिले तथा पाठ्यक्रम में अविलंब व्यापक परिवर्तन हो।

(लेखक शिक्षाविद् एवं सामाजिक संस्था 'शिक्षा-सोपान' के संस्थापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संयम का महत्व

चूंकि यह संसार विविधताओं से परिपूर्ण है तो हमारे मन को विचलित होने के लिए अनगिनत दिशाएं उपलब्ध हो जाती हैं। हमारा मन अभिलाषाओं का भंडार है। एक इच्छा के तृप्त होते ही तुरंत उसमें एक नवीन इच्छा का अंकुर फूट पड़ता है। एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि सांसारिक विषय एवं मायामोह मन के लिए एक सशक्त आकर्षण केंद्र की भूमिका निभाते हैं। परिणामस्वरूप मन पर विभिन्न दिशाओं से अनेक खिंचाव आरोपित होते हैं। ये मन में अशांति की अवस्था को जन्म देते हैं। यहीं पर संयम हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यदि समय से संयम के सूत्र आत्मसात कर लिए जाएं तो भटकाव से बचा जा सकता है।

संयम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी सहायता से मन में व्याप्त अशांति एवं विक्षोभ से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि संयमरूपी ब्रह्मास्त्र की सिद्धि इतनी सरल भी नहीं है। संयम को अपने जीवन में उतारने के लिए मनुष्य को कठोर साधना से गुजरना पड़ता है। विषयों के प्रति आसक्त मन को समझाने का प्रयास करना पड़ता है कि संसार में जो कुछ भी है, वह नश्वर है एवं उसका अस्तित्व अधिक समय तक विद्यमान रहने वाला नहीं है। मन को यह सत्य भलीभांति समझाने में जो सफल हो जाता है, वह संयम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संयम की साधना में उन्मुख होने से पहले यह जान लेना भी आवश्यक है कि संयम एवं दमन में अंतर है। जहां संयम बाह्य विषयों के प्रति आकर्षण को न्यूनतम करने का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास है, वहीं दमन अपनी इच्छाओं पर की गई एक तरह की जोर-जबरदस्ती है। दमन की प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।

संयम मनुष्य को प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। संयमी व्यक्ति आत्मिक रूप से निरंतर शुद्ध होता रहता है। संयम की सहायता से हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए स्वयं को पवित्रता के उच्चतम स्तर तक ले जाने में सफल हो सकते हैं।

प्रेरणा अवस्थी

सिविल सेवा में महिलाओं की भूमिका

कौशल किशोर

पिछले कुछ वर्षों के दौरान शीर्ष स्तर की परीक्षाओं में महिलाओं ने अपना परचम फहराया है

पिछले कुछ वर्षों की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम पर गौर करने से महिलाओं की बढ़ती भूमिका का पता चलता है। इस साल के टाप टेन में आधा दर्जन लड़कियां शामिल हैं। कुल 1016 सफल उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या 352 है।

नौकरशाही में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह 2018 में 24 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 34 प्रतिशत हो गई। आज महिलाएं संघर्ष व ताकत की अद्भुत कहानियां लिखने के लिए मेहनत कर रही हैं। 22 साल की डोनुरु अनन्या रेड्डी अखिल भारतीय रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल करती हैं। यह उनका पहला ही प्रयास था। वह तेलंगाना के एक छोटे से गांव से आती हैं। उन्होंने दिल्ली विवि के मिरांडा हाउस कालेज से भूगोल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी।

शीर्ष दस अभ्यर्थियों में अल्पसंख्यक समूह से आने वाली एकमात्र उम्मीदवार महिला हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन्मी नौशीन चौथे प्रयास में नौवां स्थान हासिल करती हैं। तीसरे असफल प्रयास के बाद वह अवसाद में चली गई थीं। लेकिन अगले परिणाम से पता चलता है कि वह जल्द ही स्वस्थ हो गईं। वह भी दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने वालों में से एक हैं।

वहीं पंजाब ने भी शीर्ष सौ उम्मीदवारों में एक स्थान हासिल किया है। 31 वर्षीय गुरलीन कौर ने अपने चौथे प्रयास में 30वीं रैंक हासिल की। डा. बलविंदर कौर मान (सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी) की बेटी भी एक प्रशिक्षित डाक्टर है। वर्ष 2021 में प्रांतीय लोक सेवा परीक्षा में नौवां स्थान मिलने पर वह प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गईं थीं। उनकी सफलता अपने आप में एक संघर्षपूर्ण कहानी कहती है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्णकालिक नौकरी से अध्ययन अवकाश के बिना ही लक्ष्य साध कर इतिहास कायम किया है।

महिलाओं के संघर्ष और ताकत की कहानी सारिका ए. के. के बिना अधूरी है। 23 वर्षीय इस केरलवासी के पिता शशि कतर में ड्राइवर हैं और मां रागी सामान्य गृहिणी हैं। वह सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं। यह ऐसा विकार है जो मांसपेशियों की गति को प्रभावित करता है। सारिका का दाहिना हाथ पूरी तरह से अक्षम है और उनके बाएं हाथ की केवल तीन उंगलियां ही काम कर रही हैं। शारीरिक रूप से अक्षम इस महिला ने अपने दूसरे प्रयास में ही 922वीं रैंक हासिल किया है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। उपरोक्त तमाम प्रदर्शन इस बात को रेखांकित करते हैं कि सार्वजनिक सेवा भारत में युवा पीढ़ी की शीर्ष आकांक्षाओं में से एक है। नौकरशाही और कार्यकारी तंत्र इस पर निर्भर रहा है। इन साहसी महिलाओं के संघर्ष ने हमें शक्ति की कई हृदयस्पर्शी कहानियों से परिचित कराया है। साथ ही युवा भारत के लिए प्रेरणा का नया स्रोत बन कर उभरी हैं।

(लेखक सामाजिक मामलों के जानकार हैं)

गलतियों से सबक ले भाजपा

'मोदी सरकार के लिए सबक' शीर्षक से लिखे आलेख में विकास सारस्वत का चुनावी विश्लेषण भाजपा के थिंक टैंक के लिए विचारणीय होना चाहिए। आम चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतने पर भी बहुमत तक न पहुंच पाने की कसक भाजपा समर्थकों को साल रही है। यह सही है कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को सहज बहुमत प्राप्त है, लेकिन इससे कुछ निर्णायक फैसलों पर ग्रहण लगने की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। चुनावी परिदृश्य में मजबूत होते विपक्ष के बुलंद हौसले आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती बनने वाले हैं। इस दृष्टि से यदि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेकर सरकार और संगठन के तौर-तरीकों में बदलाव नहीं किया तो 2029 का आम चुनाव भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास घातक होता है। चुनाव में 'चार सौ पार' जैसे नारे भारतीय जनता पार्टी के अति आत्मविश्वास के प्रतीक बन गए। इससे प्रत्याशियों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में यह गलत संदेश गया कि अब ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आभा और देशव्यापी लोकप्रियता से ही बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी ओर, विपक्षी धड़े ने इसी नारे को आधार बनाकर संविधान बदलने एवं आरक्षण खत्म करने जैसा दुष्प्रचार किया। एक प्रकार से यह नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

परीक्षा की विश्वसनीयता

यह पत्र 'परीक्षा की विश्वसनीयता' आलेख से संबंधित है। मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा 'नीट' देश में होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें 23 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। दुर्भाग्यवश इस बार एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हुए कि इस परीक्षा का संदेह के घेरे में आना स्वाभाविक है। पहले इसके पेपर लीक होने की खबर आई, फिर एक रैकेट पकड़ा गया, जिसमें परीक्षा पास करवाने के लिए रुपये लिए गए और फिर जब चार जून को इसका परिणाम आया तब तो सारे रिकार्ड ही टूट गए। ग्रेस मार्क्स के संदेहास्पद निर्णय पर जो जवाब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिया है, वह पचने लायक नहीं है। जब यह देश की सबसे बड़ी परीक्षा है तो इसमें ढिलाई की उम्मीद कतई नहीं है और जरा सोचें उन बच्चों के मां-बाप पर क्या गुजर रही होगी, जिनके बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन अच्छा कालेज नहीं मिला है। हर मां-बाप अपने बच्चों का प्राइवेट कालेज में प्रवेश नहीं करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ग्रेस नंबर पाने वाले छात्रों की रैंक दोबारा से जारी होगी और उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प है, लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया में देरी होगी। एनटीए की जिम्मेदारी बनती है कि ग्रेस नंबर, पेपर लीक और एक ही केंद्र से छह विद्यार्थियों के टाप करने के मामले की जांच कराए।

बाल गोविंद, सेक्टर-44, नोएडा

अप्रासंगिक होते वामपंथी दल

अप्रासंगिक होते वामपंथी दल आलेख में हरेंद्र प्रताप ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण देश से कम्युनिस्ट पार्टियों के क्षरण के कारणों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया है। वामपंथियों का राजनीतिक घर बंगाल आज सूना पड़ा है। 23 साल तक बंगाल में मुख्यमंत्री रहने के साथ ज्योति बसु पांच दशक तक देश के राजनीतिक परिदृश्य पर भी छाए रहे। बसु के व्यक्तित्व का ही करिश्मा था कि वैचारिक भिन्नता के बावजूद विपक्ष के नेता उनका लोहा मानते थे। लेकिन अब बंगाल में तृणमूल का शासन है। कहा जाता है कि वामपंथियों के नक्शे कदम पर चलते हुए तृणमूल ने राज्य में खौफ की स्थिति पैदा कर दी है। बिहार में एक समय वामपंथी व राजद मिलकर सत्ता में रहे। उस दौर में बिहार भी बंगाल के नक्शे कदम पर चल रहा था। कम्युनिस्ट न तो जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कोई मजबूत कार्यक्रम बना पाए और न ही जातिगत समीकरणों के लिए उपयुक्त रणनीति ही विकसित कर सके। युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(12) शनिवार, 15 जून, 2024: ज्येष्ठ शुक्ल - 9 वि. 2081

कड़े फैसले ही बड़े परिवर्तन का निमित्त बनते हैं

एक साथ चुनाव का एजेंडा

यह शुभ संकेत है कि एक देश-एक चुनाव संबंधी रिपोर्ट शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष रखी जा सकती है। इसका अर्थ है कि मोदी सरकार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के बाद भी अपने अन्य एजेंडों के साथ एक साथ चुनाव कराने के अपने एजेंडे को लेकर भी गंभीर है। इस गंभीरता का पता इससे भी चलता है कि कानून मंत्रालय ने अपने लिए सौ दिन का जो एजेंडा तय किया है, उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना भी है। कानून मंत्री ने अपने इस एजेंडे को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताते हुए यह आशा व्यक्त की थी कि सहयोगी दल भी इस पहल का समर्थन करेंगे। चूंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते चले आ रहे हैं, इसलिए तेलुगु देसम पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अन्य सहयोगी दलों और विशेष रूप से जनता दल-यू से भी इस पहल को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसका कारण कुछ माह पहले जनता दल-यू के नेताओं की पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से हुई मुलाकात है। इस मुलाकात में इस दल के नेताओं ने एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन किया था। ज्ञात हो कि राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली समिति ने एक साथ चुनाव के विषय पर विचार करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। एक तथ्य यह भी है कि विगत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक साथ चुनाव की पहल का समर्थन कर चुके हैं। यह सही है कि कई विपक्षी दल एक साथ चुनाव के विचार पर आपत्ति जताते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी यह आपत्ति विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति से ही अधिक प्रेरित है। वे इस पर ध्यान देने के लिए जानबूझकर तैयार नहीं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने से सभी दलों के राजनीतिक एवं आर्थिक हित सधेंगे और राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ भी कम होगा। इसके अतिरिक्त आम जनता की परेशानी भी कम होगी। यह ठीक है कि एक साथ चुनाव के विचार को अमल में लाने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे, लेकिन यह ऐसा कोई काम नहीं, जिसे न किया जा सके। उचित यह होगा कि जो दल एक साथ चुनाव के विचार का विरोध कर रहे हैं, वे दलगत राजनीति से ऊपर उठें और राष्ट्रीय हितों की चिंता करें। उन्हें ऐसा इसलिए करना चाहिए, क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। विपक्षी दलों की ओर से दिए जा रहे इन तर्कों का कोई मूल्य-महत्व नहीं कि एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र एवं संविधान की भावना के प्रतिकूल है और इससे राष्ट्रीय दलों को अधिक लाभ मिलेगा। हाल के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तेलुगु देसम पार्टी को आंध्र प्रदेश में मिली सफलता यही बताती है कि यह एक थोथा तर्क है।

अपराध पर लगे अंकुश

न्याय के साथ विकास के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता पर कभी प्रश्न नहीं उठा। ऐसा कहने वाले लोगों की कमी नहीं है, जो यह मानते हैं कि बिहार रहने लायक बना है, उसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति बनाई। लंबे शासन के बाद अब यह उचित समय आ गया है कि मुख्यमंत्री अपने स्तर से इन दोनों विषयों की निर्मम समीक्षा करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपराध की घटनाओं से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नहीं है। लोग आराम से दिनचर्या के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन, अपराध की छोटी-छोटी घटनाएं जिस तरह हो रही हैं, उसपर समय रहते नियंत्रण की जरूरत है। ये घटनाएं ऐसी नहीं हैं, जिनपर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। थाना स्तर की सक्रियता से इन टुच्चे अपराधियों पर काबू पाया जा सकता है। कुछ साल पहले तक पुलिस का इनपर नियंत्रण भी था। दूसरा विषय रिश्वतखोरी है। एक दौर था, जब पकड़ में आने के डर से सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेने से परहेज करते थे। रिश्वत लेने वाले अधिकारी और कर्मचारी पकड़े गए। उन्हें दंडित भी किया गया। हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने वाली इकाइयों की सक्रियता कम हुई है और सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी की शिकायतें बढ़ी हैं। निगरानी तंत्र को मजबूत कर ऐसी शिकायतें कम की जा सकती हैं। बड़े कारोबारी अगर काम के लिए कोई डील करते हैं तो उसकी चर्चा बाहर तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन, गांव का कोई आदमी अंचल या थाना में सौ दो सौ रुपये भी देकर आता है तो उसकी चर्चा वह कई दिनों तक करता है। चर्चा गांव से निकलकर जवार में फैल जाती है। सरकार के बारे में गलत अवधारणा बनने लगती है। यह किसी भी ऐसी सरकार के लिए स्वीकार्य नहीं है, जो छवि को लेकर संवेदनशील है और कार्रवाई करने में भरोसा रखती है।

अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति की मुख्यमंत्री अपने स्तर से करें निर्मम समीक्षा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या विराट कोहली को विश्व कप में ओपनिंग के बजाय तीसरे नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए?

आज का सवाल
क्या नीट मामले में सीबीआइ जांच की मांग सही है?

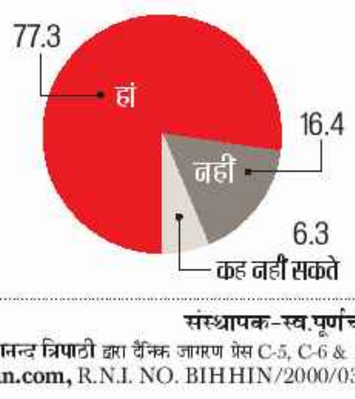

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आतंक के नए दौर की वापसी

दिव्य कुमार सोती

पाकिस्तान ने जम्मू में आतंकी हिंसा का जो सिलसिला प्रारंभ किया है, वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है

पीर-पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित जम्मू क्षेत्र में फिर से आतंकी हमलों का सिलसिला चल निकला है। जम्मू के रियासी जिले में हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर ऐसे ही एक हमले में नौ लोगों की जान चली गई और 33 घायल हो गए। इसके अगले ही दिन कठुआ के हीरानगर में आतंकियों ने एक हिंदू गांव पर हमला किया, परंतु सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कठुआ में इस हमले के समय ही वहां से लगभग 200 किमी दूर डोडा में सेना और पुलिस के संयुक्त नाके पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें छह जवान घायल हो गए। एक घंटे के घमासान के बाद आतंकी भाग निकलने में सफल रहे। इनमें से रियासी हमला उस समय हुआ, जब दिल्ली में नई राजग सरकार शपथ ले रही थी। इस हमले को शपथ ग्रहण से भी जोड़कर देखा गया। इसके पहले पुंछ-राजौरी में भी कई आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में एक समानता यह है कि इनमें आतंकियों ने सड़क के दोनों ओर के पहाड़ों से सुरक्षा बलों एवं नागरिक वाहनों को निशाना बनाया और हमले को अंजाम देने के बाद पहाड़ियों के घने जंगलों में ओझल हो गए। इस कारण सेना द्वारा चलाए गए सघन तलाशी अभियानों से खास परिणाम नहीं निकले।

जम्मू संभाग में आतंकी हमलों के तौर-तरीकों में पेशेवर बलों की छाप स्पष्ट दिखी। इनमें बख्तर भेदने वाली गोलियों और अमेरिकी मूल की एम-4 उन्नत राइफलों का भी उपयोग देखा गया। पांच मई को वायुसेना के काफिले पर हमले में वांछित आतंकी हाटून पाकिस्तान सेना के विशेष कमांडो दस्ते स्पेशल सर्विस ग्रुप (एसएसजी) का सदस्य रह चुका है। इसी तरह हीरानगर हमले के दौरान मारे गए रावलाकोट के रहने वाले आतंकी रेहान अली की पाकिस्तान में इंटरनेट मीडिया पर फौजी वर्दी में तस्वीरें वायरल हैं। उसे फौजी बताकर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। आशंका यही है कि पुंछ-राजौरी क्षेत्र में फैले पीर-पंजाल के पहाड़ों में स्थित घने जंगलों में ठीक-ठाक संख्या में जिहादी आतंकी छिपे हुए हैं। ये जम्मू क्षेत्र में घात लगाकर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और तेजी से वापस घने जंगलों में ओझल हो जाते हैं। ये आतंकी पाकिस्तानी फौज के विशेष बलों में काम कर चुके हैं। इन्हें स्थानीय इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों का सहयोग भी प्राप्त है। ये स्थानीय लोग आतंकियों को न सिर्फ सैन्य आवाजाही की जानकारी मुहैया कराते हैं, बल्कि कड़ाके की सर्दियों के दौरान उन्हें रहने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। समस्या यह है कि सैकड़ों वर्ग किमी में फैले इन जंगलों में छिपे इन आतंकियों, जिनकी संख्या का अभी सही-सही अनुमान नहीं है, का सफाया करने के लिए

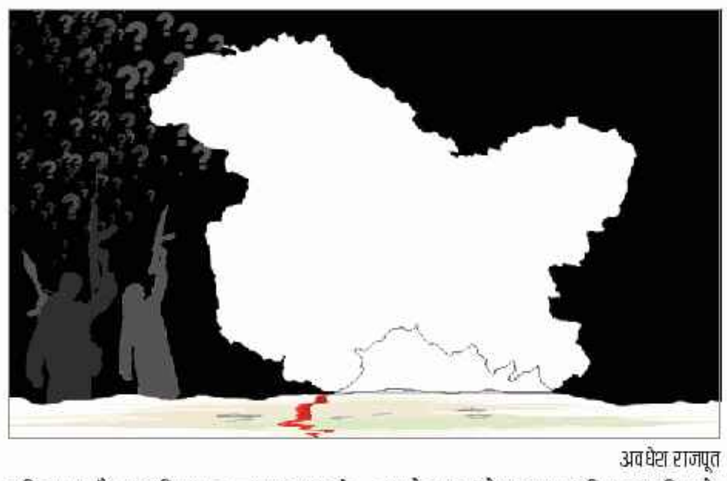

अवधेश राजपूत

यदि बड़ा सैन्य अभियान चलाया जाए तो आशंका है कि हमें बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को खोना पड़े। हालांकि वायु सैन्य संसाधनों जैसे शरीर की गर्मी पकड़ने वाले टोही और आत्मघाती ड्रोनों आदि का उपयोग कर कुछ सीमा तक संभावित नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है।

जम्मू क्षेत्र में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर अंकुश न लगाया गया तो उससे सटे पंजाब और हिमाचल के इलाकों पर भी इसका असर पड़ सकता है। यदि सैन्य अभियान में आतंकियों का सफाया कर दिया जाए तो भी कुछ वर्षों में फिर से यही स्थिति होगी, क्योंकि पिछला अनुभव बताता है कि विभिन्न भौगोलिक और अन्य कारणों से सीमा पार घुसपैठ पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। भारत को सीमा पार आतंकवाद से लड़ते हुए यह लगभग चौथा दशक है, परंतु हम अभी तक इसकी स्थायी काट नहीं तलाश पाए। मोदी सरकार ने पहली बार हिम्मत दिखाते हुए नियंत्रण रेखा पार करके पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश अवश्य दिया था, जिसके बाद बड़े आतंकी हमलों में गिरावट देखी गई थी। इसके बावजूद ऐसे जवाबी हमले स्वाभाविक रूप से घुसपैठ के उन मार्गों को बंद नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को उपलब्ध हैं। अगर इस सीमा पार आतंकवाद को बंद करना है तो हाजी पीर दर्रे और घुसपैठ के अन्य मार्गों को भारत को अपने नियंत्रण में लेना होगा। इसके बिना अनुच्छेद-370 को हटाने का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आतंकी जम्मू-कश्मीर के बाहर से काम की तलाश में वहां पहुंच रहे कामगारों की हत्या कर रहे हैं। जिन विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को सरकार द्वारा नौकरियां दी गईं, उन्हें भी आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि सही समय आने पर सीमा पार जो भी कदम उठाया जाए, वह स्थायी सामरिक लाभ और सीमा पार घुसपैठ पर हमेशा के लिए लगाम लगाने के लिए होना चाहिए।

रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान का सामरिक महत्व पश्चिम और चीन, दोनों के लिए फिर से बढ़ गया है। कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद वह अपने बढ़े महत्व का लाभ उठाने से नहीं चूकेगा। पाकिस्तान बनाने वाले भी यह जानते थे कि उसका आर्थिक औचित्य कम ही है और उसे अपने भूराजनीतिक महत्व के बल पर ही अपनी अहमियत बनाए रखनी होगी। ऐसे में पाकिस्तान ने जम्मू में आतंकी हिंसा का जो असामान्य दौर प्रारंभ किया है, वह किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एलएसी पर चीन के साथ अभी भी सैन्य तनाव बना हुआ है। कई स्थानों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हैं। वहीं, पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर भारत का संघर्ष विराम समझौता लागू है। यह समझौता तब हुआ था, जब भारत-चीन तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान ने उन दिनों अपनी बेहद खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत के साथ किसी प्रकार का टकराव मोल लेना सही नहीं समझा था। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से तब फौज के रिश्ते भी खराब चल रहे थे। पाकिस्तानी जनरल इमरान को हटाने की योजना बना रहे थे, जिसमें आंतरिक अस्थिरता की आशंका थी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी फौज भारत-चीन सैन्य तनाव के बीच भारत से संघर्ष विराम को तैयार हुई थी। अब वे स्थितियां बदल चुकी हैं। इस आशंका से इन्कार नहीं कि पाकिस्तानी फौज अब इस संघर्ष विराम समझौते से किनारा कर चीन के साथ मिलकर भारत पर दो मोर्चों पर सैन्य दबाव बनाना चाहती हो।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

परिवर्तन की बाट जोहता पाठ्यक्रम

पिछले 10 वर्षों में देश ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु शिक्षा का क्षेत्र कमोबेश उपेक्षित ही रहा। नई सरकार में फिर से शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू करेंगे। इसका अर्थ है कि अभी तक तेजी नहीं दिखाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार-प्रसार तो खूब हुआ, परंतु धरातल पर उसका क्रियान्वयन, प्रभाव और परिणाम दिखाई नहीं देता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भावी पीढ़ी के भविष्य और निर्माण से जुड़ा विषय समाज और सरकार की प्राथमिकता-सूची में निचले क्रम पर दिखता है। राजनीतिक दलों के लिए जब सत्ता-प्राप्ति का सीमित और तात्कालिक लक्ष्य सर्वोपरि हो जाता है, तब विचारों के गठन और व्यक्ति-निर्माण का प्रश्न पीछे छूट जाता है। निःसंदेह मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में अधिक आइआइटी, आइआइएम, मेडिकल कालेज एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले हैं, परंतु क्या हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा की स्थिति, शिक्षण का स्तर, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, विश्व में उसकी साख एवं विश्वसनीयता, वर्षों से लंबित एवं रिक्त पदों पर नई नियुक्ति, मौलिक शोध एवं नवोन्मेष, कौशल एवं तकनीक की दक्षता, अध्यापकों का प्रशिक्षण, नियमित सत्र, अनुशासित शैक्षिक परिवेश, रोजगारपरक शिक्षा, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त परीक्षा तथा भारी धन खर्च कर भी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की बढ़ती लालसा आदि पर समाधानपरक काम नहीं किया जाना चाहिए? उम्मीद थी कि बीते दस वर्षों की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में पाठ्यक्रम में सुधार की दृष्टि से निर्णायक पहल की जाएगी, परंतु इस दिशा में अभी तक खानापूर्ति ही अधिक हुई है। जहां बुनियाद बदलने की शर्त हो, क्या वहां केवल साज-सज्जा से काम चलाया जा सकता है? आवश्यकता संशोधन-संक्षिप्तीकरण की नहीं, अपितु राष्ट्र की आकांक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन से जुड़ी है।

प्रणय कुमार

पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन आवश्यक हैं वे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान अविलंब होने चाहिए

प्राथमिकता वाले काम की अनदेखी ● फाइल

निःसंदेह भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीतिशास्त्र और दर्शन जैसे मानविकी के विभिन्न विषयों के माध्यम से सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मजबूती मिलनी चाहिए। इसी तरह भारतीय ज्ञान-परंपरा को पोषण मिलना चाहिए, अस्तित्ववादी विमर्श एवं विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए। सहयोग, संतुलन, सामाजिकता, संवेदनशीलता एवं देशभक्ति जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में व्याप्त बहुलता, शांति एवं सह-अस्तित्व के मूल स्रोत की पहचान की जानी चाहिए।

यह कैसी विडंबना है कि हमारे बौद्धिक-राजनीतिक-अकादमिक विमर्श में 'भारतवर्ष में व्याप्त विविधता में एकता' का उल्लेख तो भरपूर किया जाता है, परंतु उसे पोषण देने वाले मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, प्रमुख घटकों, मंदिरों, मठों, तीर्थों और त्योहारों आदि की कोई चर्चा नहीं होती? क्या पाठ्यक्रम में इन्हें यथोचित स्थान नहीं मिलना चाहिए? इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विवेचना की गई है और भारतीयों के साहस, संघर्ष एवं प्रतिरोध को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। देश के वैशिष्ट्य एवं गौरवशाली अध्यायों की अपेक्षा केवल दिल्ली-केंद्रित इतिहास को केंद्र में रखा गया है तथा देश के अमर सपूतों, बलिदानी धर्मरक्षकों, महान संतों, समन्वयवादी समाज-सुधारकों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों को नेपथ्य में रख, दो-चार का महिमामंडन किया गया है। क्या यह सत्य नहीं कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था और पाठ्य-सामग्रियों में आस्था एवं विश्वास पर संदेह, अनास्था एवं अविश्वास को वरीयता दी गई है? उसमें अधिकार भाव की प्रबलता है, कर्तव्य-भावना गौण है। वर्गीय चेतना के नाम पर अलगाववादी वृत्तियों तथा पारस्परिक मतभेद एवं संघर्ष को शिक्षा के माध्यम से पाला-पोसा-बढ़ाया गया है। मूल बनाम बाहरी, उत्तर बनाम दक्षिण, राष्ट्रभाषा बनाम क्षेत्रीय भाषा जैसी कृत्रिम लड़ाइयां शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के माध्यम से खड़ी की गई हैं। परिवार, समाज एवं राष्ट्र की विभिन्न इकाइयों को परस्पर विरोधी मानने वाली खंडित एवं विभेदकारी दृष्टि के स्थान पर क्या शिक्षा-व्यवस्था में समन्वय और समग्रता पर आधारित सनातन दृष्टि को स्थान नहीं मिलना चाहिए?

स्वतंत्र भारत की अनेक गौरवशाली उपलब्धियां पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की बाट जोह रही हैं। क्या भारत की सफल लोकतांत्रिक यात्रा के क्रमिक सोपानों का उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए? क्या आपातकाल के दौरान किए गए संघर्ष और यातनाओं की व्यथा-कथा पढ़कर लोकतंत्र के प्रति भावी पीढ़ी की आस्था मजबूत नहीं होगी? क्या चंद्रयान, मंगलयान की सफलता की गाथा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयोग, अनुसंधान और व्यवहार की कसौटी पर कसे जाने वाले गणित और विज्ञान जैसे विषयों में भी बीते कई दशकों से परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन-अध्यापन की भाषा के रूप में मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं की पैरवी की गई है, परंतु अभी तक इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ है। विभिन्न स्तरों की परीक्षा-पद्धति, प्रश्नपत्र के प्रारूप, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि में सुधार आवश्यक हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या विकराल होती जा रही है। अभी नीट का मामला सुर्खियों में है। यह दर्शाता है कि शिक्षा के साथ परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं हो सके हैं। यह समय की मांग है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिक्षा-क्षेत्र में सुधारों को गति एवं दिशा मिले तथा पाठ्यक्रम में अविलंब व्यापक परिवर्तन हो।

(लेखक शिक्षाविद् एवं सामाजिक संस्था 'शिक्षा-सोपान' के संस्थापक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

संयम का महत्व

चूंकि यह संसार विविधताओं से परिपूर्ण है तो हमारे मन को विचलित होने के लिए अनगिनत दिशाएं उपलब्ध हो जाती हैं। हमारा मन अभिलाषाओं का भंडार है। एक इच्छा के तृप्त होते ही तुरंत उसमें एक नवीन इच्छा का अंकुर फूट पड़ता है। एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि सांसारिक विषय एवं मायामोह मन के लिए एक सशक्त आकर्षण केंद्र की भूमिका निभाते हैं। परिणामस्वरूप मन पर विभिन्न दिशाओं से अनेक खिंचाव आरोपित होते हैं। ये मन में अशांति की अवस्था को जन्म देते हैं। यहीं पर संयम हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यदि समय से संयम के सूत्र आत्मसात कर लिए जाएं तो भटकाव से बचा जा सकता है।

संयम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी सहायता से मन में व्याप्त अशांति एवं विक्षोभ से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि संयमरूपी ब्रह्मास्त्र की सिद्धि इतनी सरल भी नहीं है। संयम को अपने जीवन में उतारने के लिए मनुष्य को कठोर साधना से गुजरना पड़ता है। विषयों के प्रति आसक्त मन को समझाने का प्रयास करना पड़ता है कि संसार में जो कुछ भी है, वह नश्वर है एवं उसका अस्तित्व अधिक समय तक विद्यमान रहने वाला नहीं है। मन को यह सत्य भलीभांति समझाने में जो सफल हो जाता है, वह संयम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संयम की साधना में उन्मुख होने से पहले यह जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है कि संयम एवं दमन में भारी अंतर है। जहां संयम बाह्य विषयों के प्रति आकर्षण को न्यूनतम करने का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास है, वहीं दमन अपनी इच्छाओं पर की गई एक तरह की जोर-जबरदस्ती है। दमन की प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।

संयम मनुष्य को प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। संयमी व्यक्ति आत्मिक रूप से निरंतर शुद्ध होता रहता है। उसके भीतर विषयजनित दुर्गुण समाप्त होने लगते हैं। संयम की सहायता से हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए स्वयं को पवित्रता के उच्चतम स्तर तक ले जाने में सफल हो सकते हैं।

प्रेरणा अवस्थी

पाठकनामा
pathaknama@pat.jagran.com

गलतियों से सबक ले भाजपा

'मोदी सरकार के लिए सबक' शीर्षक से लिखे आलेख में विकास सारस्वत का चुनावी विश्लेषण भाजपा के थिंक टैंक के लिए विचारणीय होना चाहिए। आम चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतने पर भी बहुमत तक न पहुंच पाने की कसक भाजपा समर्थकों को साल रही है। यह सही है कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को सहज बहुमत प्राप्त है, लेकिन इससे कुछ निर्णायक फैसलों पर ग्रहण लगने की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। चुनावी परिदृश्य में मजबूत होते विपक्ष के बुलंद हौसले आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती बनने वाले हैं। इस दृष्टि से यदि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेकर सरकार और संगठन के तौर-तरीकों में बदलाव नहीं किया तो 2029 का आम चुनाव भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास घातक होता है। चुनाव में 'चार सौ पार' जैसे नारे भाजपा के अति आत्मविश्वास के प्रतीक बन गए। इससे प्रत्याशियों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में यह गलत संदेश गया कि अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की आभा और देशव्यापी लोकप्रियता से ही बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी ओर, विपक्षी धड़े ने इसी नारे को आधार बनाकर संविधान बदलने एवं आरक्षण खत्म करने जैसा दुष्प्रचार किया। एक प्रकार से यह नारा भाजपा के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ।

pandeyvp1960@gmail.com

कम्युनिस्टों का तथ्यात्मक विश्लेषण

'अप्रासंगिक होते वामपंथी दल' शीर्षक आलेख में हरेंद्र प्रताप ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण देश से कम्युनिस्ट पार्टियों के क्षरण होने के कारणों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया है। भारत में ही नहीं यूरोप या किसी अन्य महाद्वीप में आज कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत मजबूत नहीं रह गई हैं। वामपंथियों का राजनीतिक घर पश्चिम बंगाल आज सूना पड़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक ज्योति बसु भारतीय मार्क्सवादी सिद्धांतकार और राजनीतिज्ञ थे। 23 साल तक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री रहने के साथ ज्योति बसु लगभग पांच दशक तक देश के राजनीतिक परिदृश्य पर भी छाए रहे। बसु के व्यक्तित्व का ही करिश्मा था कि वैचारिक भिन्नता के बावजूद विपक्ष के सभी नेता उनका लोहा मानते थे। उन्होंने बंगाल के सीएम रहते हुए पंचायती राज और भूमि सुधार की दिशा में ऐतिहासिक काम किए। आज बंगाल में स्थिति बदल गई है। सत्ता पर तृणमूल कांग्रेस काबिज है। कहा जाता है कि वामपंथियों के नक्शेकदम पर चलते हुए तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में खौफ की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसी ही तस्वीर कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में भी हुआ करती थी। जिसका नुकसान आज स्वयं वामपंथी दलों को भुगतना पड़ रहा है। खौफ, हिंसा आदि की राजनीति एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। समय के साथ जब जाति सामाजिक पूंजी के तौर पर तब्दील होने लगी और राजनीतिक तौर पर एकजुट होने की वजह बनने लगी, तब वामपंथियों के लिए किनारे खड़े होकर देखने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। वे जाति व्यवस्था के उन्मूलन की रणनीति नहीं बना सके।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

सामान्य यात्रियों की भी सुध ली जाए

भारतीय रेलवे का इतिहास 177 वर्ष पुराना है। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे लंबे रेल नेटवर्कों में चौथे नंबर पर है। यह 68,000 किलोमीटर से अधिक में फैला है। प्रतिदिन 13523 ट्रेनें चलती हैं। यात्रा करने के लिए ज्यादातर लोगों की पहली पसंद रेलवे ही है। प्रतिदिन 2.30 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। ट्रेनों की गति बढ़ाने, यात्रा को सुरक्षित करने के अनेक उपायों के साथ प्लेटफार्मों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मुंबई व गुजरात के मध्य 508 किमी रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैय्यारी के साथ वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रहीं हैं, परंतु स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे कम करके थ्री टीयर के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं। जिसका किराया मध्यम श्रेणी के यात्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये डिब्बे खचाखच भरे होते हैं। टिकट है या नहीं, लोग बैठे रहते हैं, कुछ भी कर लीजिए उठने को तैयार नहीं होते। रेलवे प्रशासन को सामान्य यात्री की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। गंतव्य स्थान के लिए आम लोगों को ट्रेनें आसानी से मिलने के साथ डिब्बे में बैठने का स्थान भी मिलना चाहिए। गति बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। अभी भी कुछ ट्रेनें मात्र 60 किमी के रास्ते को पूरा करने में दो घंटे से अधिक लगा देती हैं। त्रिवेणी एक्सप्रेस लखनऊ से शक्तिनगर की 507 किमी की दूरी 16 घंटे में तय करती है। इसकी औसत गति 30-35 किमी ही है। बेटिंग समाप्त कर कन्फर्म टिकट मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गा देवी मंदिर मार्ग चौक पटना

पोस्ट

इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी को लेकर बेहद भद्दे मीम्स चल रहे हैं। ये भारत में घटिया हास्यबोध को भी दर्शाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती सीट से लोकसभा चुनाव हार गईं। अब राकांपा ने सुनेत्रा को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया है। यह परिवारवाद है या नहीं?

मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

प्रधानमंत्री मोदी के हैंडल से जारी हो रहे वीडियोज में सिर्फ योग या अपना प्रचार नहीं है। यह एआइ को लेकर सरकार के भविष्य के चिंतन का भी संकेत है। अपनी-अपनी दृष्टि है कि आप क्या देखते हैं। यह वैज्ञानिक चेतना वाले कम्युनिस्टों वाला मामला नहीं है, जिन्होंने पिछली सदी के उत्तरार्ध में कंप्यूटर का विरोध किया था।

सुशांत झा@jhasushant

सरकार को जम्मू पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील करने के तौर-तरीके तलाशने होंगे। खासतौर से उन स्थानों पर जहां पंजाब की सीमा जम्मू से लगती है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें ड्रोन तकनीक में भी भारी निवेश करना होगा।

राहुल पंडिता@rahulpandita

जनपथ

गंगा-यमुना बह रही हैं नदियों का देश,
फिर भी दिल्ली में दिखे सूखे का परिवेश।
सूखे का परिवेश बने टैंकर मजबूरी,
बूंद-बूंद पर रार मांग हो कैसे पूरी??
नहीं भगीरथ कोय करें सब नेता पंगा,
लेकर आए कौन भला दिल्ली में गंगा!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प, बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर वी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 64

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शनिवार, 15 जून 2024

धन सृजित करने का सबसे बड़ा साधन श्रम है। यह अन्य सभी कारकों को प्रेरित करता है। -डेनियल वेब्स्टर

दुनिया के सबसे शक्तिशाली सात देशों के संगठन जी-7 का सदस्य न होने के बावजूद इसकी शिखर बैठकों में पिछले कई वर्षों से भारत को जो महत्व दिया जा रहा है, वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की बढ़ती धमक को ही दर्शाता है।

इटली में मोदी

दुनिया के सबसे शक्तिशाली सात देशों के समूह जी-7 की शिखर बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में पिछले कई वर्षों से भारत को जो महत्व दिया जा रहा है, वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की बढ़ती धमक को ही दर्शाता है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के तौर पर जी-7 देशों के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इटली पहुंचे हैं। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे वर्ष में पहुंच गया है, इस्राइल-हमास युद्ध भी खत्म होता नहीं दिख रहा और यूरोपीय देशों के चुनावों में राजनीति का चेहरा बदलता दिख रहा है, दुनिया की सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मिलकर आगे की रणनीतियों पर विचार कर रही हैं, तब अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया-प्रशांत के बारह विकासशील देशों को भी इस चर्चा में शामिल करने का अर्थ है। दरअसल, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश जी-7 के लिए इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हैं कि ये तीनों ही देश इसके प्रतिद्वंद्वी रूस व चीन के साथ ब्रिक्स समूह का भी हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र जिस तेजी से अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, उसे देखते हुए वैश्विक व्यवस्था में जी-7 जैसे क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ा है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि जी-7 भी अब उतना मजबूत नहीं दिखता है, क्योंकि 1980 के दशक में जी-7 देशों का जीडीपी वैश्विक जीडीपी का करीब 60 फीसदी था, जो अब घटकर 40 फीसदी रह गया है। पिछले दशक भर में भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है, तो उसकी वजहें भी हैं। ऐसे समय में जब ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्थाएं स्थिर बनी हुई हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक मान रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ब्रिटेन के बराबर है, तो फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों से कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत को मिलने वाले महत्व की बड़ी वजह यह भी है कि भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा

लोकतंत्र है, तो जी-7 भी लोकतांत्रिक देशों का समूह है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ चर्चा की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी शिक्षा, रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बात की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी गर्मजोशी से गले से लगाते हुए दोहराया कि युद्ध का समाधान बातचीत है। दरअसल, यह भारत की कूटनीतिक कामयाबी ही है कि आज अमेरिका, रूस और यूक्रेन, तीनों भारत से नजदीकी चाहते हैं। वैश्विक आयोजनों में भारत की बढ़ती भागीदारी वैश्विक चुनौतियों को हल करने में भारत के प्रयासों की बढ़ती मान्यता को ही दर्शाती है।

उन्हें भरने हैं कई पेट

भारतीय मजदूरों को हसीन सपने दिखाकर खाड़ी देशों में ले जाया जाता है, लेकिन वादे के मुताबिक उन्हें वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। उनकी मजबूरी समझी जा सकती है कि उन्हें अपने देश की तुलना में वहां ज्यादा मजदूरी मिलती है और उन्हें अपने परिवार को भी पैसा भेजना होता है।

अनिल त्रिगुणायत
पूर्व राजनयिक

खाड़ी देशों में, जिनमें कुवैत समेत बहरीन, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं, बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों की मांग रहती है। इन श्रमिकों में ज्यादातर भवन निर्माण से जुड़े होते हैं। नर्सिंग सेवा से जुड़े लोग भी जाते हैं। कुवैत की कुल 49 लाख आबादी में दस लाख से ज्यादा भारतीय हैं, जो वहां की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। भारतीय मजदूरों को हसीन सपने दिखाकर खाड़ी देशों में ले जाया जाता है, लेकिन अक्सर वादे के मुताबिक उन्हें वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। चूंकि उन्हें अपने देश की तुलना में वहां ज्यादा मजदूरी मिलती है, और अपने देश में रोजगार का संकट है, इसलिए वे घर-बार छोड़कर बेहतर जिंदगी की तलाश में खाड़ी देशों में जाते हैं।

वादे के मुताबिक, जब श्रमिकों को मानदेय और सुविधाएं नहीं मिलतीं, तो उनके पास दूसरा चारा नहीं होता। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वे वापस आ सकें। कभी-कभी तो उनसे कंपनी मालिकों द्वारा उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। इसलिए मन मारकर वे वहीं काम करने लगते हैं और चुपचाप शोषण सहते रहते हैं। उनके रहने की भी उचित व्यवस्था नहीं होती, अक्सर एक कमरे में चार-पांच लोगों को रखा जाता है। 12 जून को कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत के मंगाफ में एक श्रमिक आवासीय इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 45 भारतीय थे। इस भवन में 196 मजदूर रखे गए थे। आग लगने पर लोग निकल भी नहीं पाए, क्योंकि उस भवन में आपातकालीन निकास और सुरक्षा उपकरण तक नहीं थे। वहां की सरकार ने खुद स्वीकार किया कि जिस भवन में आग लगी, उसमें सुरक्षा के मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया था। यह स्थिति कुवैत की अकेली एक इमारत की नहीं है या सिर्फ इसी देश में ऐसा नहीं होता है, बल्कि लगभग प्रत्येक खाड़ी देश में मजदूरों के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है। खाड़ी देशों

में एक से एक इमारतें हैं और उनमें सुरक्षा के उपाय भी हैं, लेकिन बात जब श्रमिकों की आती है, तो उन्हें भीड़भाड़ वाली जगहों पर अल्प सुविधाओं के साथ रहने की जगह दी जाती है। इसलिए इस तरह के हादसे होते हैं। मैंने खुद हैती में देखा है कि एक कमरे में चार-चार लोगों को रखा गया था। यह वहां के स्थानीय नियम-कानूनों का भी उल्लंघन है।

भारत में विदेशी कंपनियों के जो एजेंट हैं, वे मजदूरों को विदेश भिजवाने का इंतजाम करते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी मजदूर को ले जाना होता है, तो उससे वादा किया जाता है कि तुम्हें 300 डॉलर मजदूरी दी जाएगी, लेकिन वहां पहुंचने पर कम मजदूरी दी जाती है। दरअसल, यह जो एजेंटों का रैकेट है, वही सारी गड़बड़ी करता है। श्रमिक जिन कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं, उनके मालिक काफी अमीर होते हैं। एजेंट कंपनी मालिक से मजदूरों को देने के लिए जितनी रकम लेते हैं, उतनी मजदूरों को देते नहीं। यही नहीं, वहां से जिस काम के लिए उन्हें ले जाया जाता है, वहां दूसरे काम में लगा दिया जाता है। हाल ही में रूस की सेना में भर्ती हुए कई भारतीयों की मौत हो गई। दरअसल उन्हें दूसरे कामों के लिए ले जाया गया था। लेकिन भेज दिया सेना में लड़ने के लिए, नतीजतन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी।

श्रमिकों को विदेशों में कोई परेशानी न हो, इसके लिए भारत सरकार ने काफी नियम बनाए हैं और संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावास भी उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। अभी कुवैत में जो हादसा हुआ, उसके तत्काल बाद भारत सरकार सक्रिय हो गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक करके प्रत्येक मृतक के परिजन को तत्काल दो लाख रुपये के अनुदान देने का एलान किया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री से बात की और विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन को वहां पर भेजा गया। वहां के राजदूत ने भी घटनास्थल और उन अस्पतालों का दौरा कर घायलों का हालचाल जाना, जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। हालांकि कुवैती सरकार भी हरसंभव मदद कर रही है। खाड़ी देशों में अन्य देशों के श्रमिक भी रहते हैं। लेकिन जितना ख्याल भारत सरकार अपने लोगों का रखती है, उतना अन्य किसी देश की सरकार नहीं।

विदेशों में भारतीयों का शोषण न हो, इसके लिए भारत सरकार ने 'मदद' पोर्टल बनाया है, जिस पर आप सहायता ले सकते हैं। 'ई-माइग्रेट' नामक पोर्टल के जरिये भी मदद मिलती है। इसके अलावा, हर देश में भारतीय दूतावास खुली अदालत लगाते हैं, जहां विदेश में रहने वाला कोई भी भारतीय अपनी समस्या बताकर मदद मांग सकता है। दूतावास द्वारा उनकी हर संभव मदद का प्रयास किया जाता है। हमारी सरकार ने नियम बनाया है कि 35 साल से कम उम्र की कोई महिला खाड़ी देशों में मजदूरी या घरेलू काम करने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि महिलाओं के शारीरिक शोषण तक की शिकायतें मिलती रही हैं। हालांकि पहले के मुकाबले अब हालात बदले हैं। विदेश जाने वाले श्रमिकों को भाषा संबंधी प्रशिक्षण के साथ कई स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मजदूरों को नियुक्त करने वाली नियोक्ता कंपनियों का सारा डाटा निकालकर पूरी छानबीन की जाती है।

हालांकि कई बार विदेशों में रहने वाले भारतीय दूतावासों की एडवाइजरी का पालन नहीं करने के कारण संकट में फंस जाते हैं। जब मैं लीबिया में राजदूत था, तो मैंने भारतीयों से कहा कि यहां कभी भी युद्ध हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द यहां से निकलो, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब बमबारी होने लगी, तो भगदड़ मच गई। भारत में उनके परिजन सरकार से मांग करने लगे कि हमारे परिजनों को निकालो। जैसे-तैसे मैंने खुद 430 लोगों को वहां से निकलवाया। सरकार ने एयर इंडिया की फ्लाइट से उन्हें अपने वतन लौटाया।

निश्चित रूप से भारत सरकार ने विदेश जाने वाले श्रमिकों की सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन उसे अपने तंत्र को और मजबूत करना होगा, ताकि उन देशों की कंपनियां और उन्हें भेजने वाले एजेंट मजदूरों के साथ धोखाधड़ी न करें और वादे के अनुसार उन्हें वेतन एवं सुविधाएं प्रदान करें। इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

ब्रायन ट्रेसी

इन्सान की सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य, दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं।

आप तभी खुश रह सकते हैं जब लक्ष्य स्पष्ट हो

कल्पना करें कि आप किसी बड़े शहर के बाहरी इलाके में खड़े हैं और आपसे उस शहर में किसी खास घर या ऑफिस तक गाड़ी से पहुंचने को कहा जाता है। लेकिन यहां एक पेच है; सड़क पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और आपके पास शहर का नक्शा भी नहीं है। सच तो यह है कि आपको उस घर या ऑफिस का सिर्फ बहुत सतही वर्णन ही बताया गया है। सवाल यह है, आपको क्या लगता है कि नक्शे और साइन बोर्ड के बिना आपको शहर में वह मकान या ऑफिस खोजने में कितना समय लगेगा? जवाब है, पूरी जिंदगी भी लग सकती है। अगर आप कभी उस मकान या ऑफिस को खोज लें, तो यह बहुत हद तक किस्मत का मामला होगा। और दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी तरह जीते हैं।

ज्यादातर लोग जिंदगी भर नक्शे और साइन बोर्ड के बिना दुनिया में निरुद्देश्य यात्रा शुरू करते हैं। यह जीवन में बिना लक्ष्यों और योजनाओं के काम शुरू करने जैसा है। वे बीच राह में चीजें सोचने के आदी होते हैं। नतीजा यह होता है कि आमतौर पर, दस-बीस साल नौकरी करने के बावजूद वे तंगहाल बने रहते हैं, अपनी नौकरी में दुखी नजर आते हैं, अपने जीवनसाथी से असंतुष्ट रहते हैं और बहुत कम तरक्की कर पाते हैं। इसके बावजूद वे हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं और चीजों के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन वे शायद ही कभी बेहतर होती हैं। अपने-आप तो नहीं ही होतीं। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं, जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर कदम-दर-कदम प्रगति कर रहे होते हैं। इन्सान की सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य, दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का एहसास भी दिलाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप ज्यादा ऊर्जावान और प्रभावी महसूस करते हैं। आप ज्यादा कार्यकुशल, योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लक्ष्यों की ओर उठा हर कदम आपके इस विश्वास को बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं। आज जितने लोग भविष्य के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तन से डर रहे हैं, उतने इतिहास में किसी और युग में नहीं रहे। लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि लक्ष्य होने पर आप जीवन में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्य होने पर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी के ज्यादातर परिवर्तन आप खुद तय करें और वे आपकी मनचाही दिशा में हों। लक्ष्य होने पर आप हर काम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इन्सान का हर काम किसी न किसी अर्थ में उद्देश्यपूर्ण होता है। आप सिर्फ तभी खुश रहते हैं, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हों, जो आपको मनचाही चीज की ओर ले जा रहा हो। तो फिर बड़ा सवाल यह है, आपके लक्ष्य क्या हैं? आप किन उद्देश्यों पर निशाना साध रहे हैं? आप दिन के अंत में कहां पहुंचना चाहते हैं?

बेहतर जीवन की संभावना

सूत्र

खुद के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि आप ठीक-ठीक क्या चाहते हैं और आप इसे सबसे अच्छी तरह कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने सच्चे लक्ष्यों के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी।

दूसरा पहलू

कोरोना प्रतिबंध में ढील देने और वहां की मुद्रा येन के कमजोर होने से दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान के पर्यटक जा रहे जापान।

पर्यटकों से परेशान जापान

कोरोना वायरस के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने और जापान की मुद्रा येन के कमजोर पड़ जाने से पिछले कुछ समय से जापान में विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। विगत मार्च में जापान में तीस लाख विदेशी पर्यटक आए थे, जो कि मार्च, 2019 की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा और एक नया रिकॉर्ड है। जापान घूमने आए विदेशी पर्यटकों में दो तिहाई हिस्सेदारी दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन की है। पिछले साल विदेशी पर्यटकों से जो आय हुई, वह जापान के जीडीपी का नौ फीसदी है।

इयान झुआंग

विदेशी पर्यटकों के व्यवहार से जापानियों को परेशानी हो रही है। भारी भीड़ से जापान की प्राचीन शाही राजधानी क्योटो में स्थिति कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाती है।

लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि विदेशी पर्यटकों के व्यवहार से जापानियों को परेशानी हो रही है। भारी भीड़ से जापान की प्राचीन शाही राजधानी क्योटो में स्थिति कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो विदेशी लोग क्योटो के पास के छोटे शहर माउंट फूजी भी पहुंच जाते हैं, जहां कभी पर्यटक नहीं जाते थे। दरअसल पर्यटकों की भीड़ और उनका व्यवहार जापान जैसे शांत और शालीन समाज की परीक्षा ले रहा है। क्योटो की ही बात करें, तो पर्यटकों की मांग से होटल इतने महंगे हो गए हैं कि स्थानीय लोगों को उनमें जगह नहीं मिल पाती। इसके अलावा, बसों और रेस्टोरेंट्स में बढ़ती भीड़ से भी स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। पिछले महीने 65 साल के हिरोशी बान को क्योटो की एक खास जगह तक बस से पहुंचने में तीन घंटे ज्यादा लगे, क्योंकि विदेशी पर्यटक पैसे गिनकर देने में देर लगा रहे थे, जिससे बस को रोकना पड़ा था। बान कहते हैं, 'क्योटो में ऐसा लगता है कि रोज उत्सव हो रहा है। ऐसे में, हम शांति से अपना जीवन भी नहीं बिता सकते।'

जापानियों की यह भी शिकायत है कि बाहरी पर्यटक स्थानीय परंपराओं का सम्मान नहीं करते। कभी वे फोटो खींचने के लिए गेशा नर्तकियों का पीछा करते हैं, तो कभी चलते-चलते खाते हैं, जिसे जापान में असभ्यता माना जाता है। ऐसे ही, टोक्यो के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में पर्यटकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने देर रात घर से बाहर शराब पीने पर रोक लगा दी है। ऐसे ही, क्योटो के बाजार में एक उद्यमी ने अपने रेस्टोरेंट से बाहर अंग्रेजी में, 'नो इटिंग व्हाइल वॉकिंग' (चलते हुए खाना नहीं) का बोर्ड लगा दिया है। हाल ही में क्योटो में नाई शोजी मत्सुमोतो की एक दुकान में दो विदेशी जिस तरह शोर करते हुए घुसे, वह शोजी को अच्छा नहीं लगा। उनका कहना था कि उनकी दुकान में उन लोगों का स्वागत नहीं है, जो जापानी नहीं जानते।

जापानियों की यह भी शिकायत है कि बाहरी पर्यटक स्थानीय परंपराओं का सम्मान नहीं करते। कभी वे फोटो खींचने के लिए गेशा नर्तकियों का पीछा करते हैं, तो कभी चलते-चलते खाते हैं, जिसे जापान में असभ्यता माना जाता है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

मोटे अनाज की मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से मोटे अनाज को बढ़ावा देना शुरू किया है, तब से भारत के मोटे अनाज की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है।

यूएई	17.76%
सऊदी अरब	13.67%
नेपाल	7.35%
बांग्लादेश	4.92%
जापान	4.43%
अमेरिका	4.08%
जर्मनी	3.78%

स्रोत: DGCIS

भगवान शंकर ने शाप से मुक्त कर माहेश्वरी समाज की रक्षा की और अपना नाम भी दिया। तभी से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को महेश नवमी कहते हैं।

भगवान शिव ने दिया नाम

अंतर्यात्रा
संकलित

ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को महेश नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई थी। धर्मग्रंथों के अनुसार, माहेश्वरी समाज के पूर्वज क्षत्रिय थे। ऋषियों ने उन्हें शाप दे दिया था, लेकिन इस दिन भगवान शंकर ने उन्हें शाप से मुक्त कर न केवल रक्षा की, बल्कि इस समाज को अपना नाम भी दिया। इसलिए यह समुदाय 'माहेश्वरी' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

पौराणिक कथा है कि राजा खडगलसेन की कोई संतान नहीं थी। घोर तपस्या के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। जन्म के समय ऋषियों ने राजा को बताया था कि 20 साल की उम्र तक सुजान को उत्तर दिशा की ओर यात्रा न करने दें। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने गए, तो गलती से उत्तर दिशा की तरफ चले गए। वहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि के तप में विघ्न हुआ, तो उन्होंने राजकुमार व उनके सैनिकों को शाप देकर पत्थर का बना दिया। राजकुमार की पत्नी चंद्रावती को पता चला, तो उसने ऋषि से माफी मांगी और शापमुक्ति का उपाय पूछा।

ऋषि ने कहा कि अगर तुम अपने पति को शाप मुक्त करना चाहती हो, तो महेश यानी भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करो। चंद्रावती व सैनिकों की पत्नियों ने ऐसा ही किया। इसके बाद ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राजकुमार शाप से मुक्त हो गए। कहा जाता है कि इसके बाद राजकुमार ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 01 जून, 1954

विशाल मध्य भारत के निर्माण की मांग को न उठाया जाए

विशाल मध्यभारत के निर्माण की मांग को न उठाया जाय

केंद्रीय गृह मंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने उज्जैन में एकत्रित हुए कांग्रेसियों से कहा कि विशाल मध्य भारत के निर्माण की मांग को न उठाया जाए। हालांकि जो गांव-कस्बे मध्य भारत में मिलने चाहिए, उनकी मांग बराबर की जाए।

हिंदी में शपथ लेने के संदेश बहुत गहरे

ज्यादातर मंत्रियों का हिंदी में शपथ लेना हो या तंत्र के शीर्ष का हिंदी में बढ़ता व्यवहार हो, इनसे नीचे तक संदेश जाता है।

उमेश चतुर्वेदी

सम्मान

स्थान राष्ट्रपति भवन, साल 2009 की गर्मियां। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण चल रहा था। मंत्रियों के शपथ लेते ही तालियां बजतीं, और थम जातीं। इसी बीच एक युवा नेता के शपथ वाले शब्द जैसे ही थमे...राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा। बाकी मंत्रियों की तुलना में इस बार ताली कुछ ज्यादा तेज और देर तक बजी। वह युवा मंत्री थीं अगाथा संगमा। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी.ए. संगमा की बेटी अगाथा संगमा की ओर मेहमानों का ध्यान खिंचने की वजह बनी उनकी हिंदी। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि अगाथा पूर्वोत्तर की नेता थीं और तब शपथ ग्रहण में अंग्रेजी का बोलबाला रहता था। हिंदी भाषी क्षेत्रों के पढ़े-लिखे ज्यादातर नेताओं के लिए हिंदी में शपथ लेना हेठी समझी जाती थी।

लेकिन मोदी सरकार में हालात बदल गए हैं। बीते नौ जून की शाम को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली।

इनमें 55 मंत्रियों ने हिंदी में शपथ ली। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद यह पहला शपथ ग्रहण था, जिसमें दो तिहाई मंत्रियों ने हिंदी में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन का संकल्प लिया।

हिंदी के प्रति मोदी सरकार का अनुराग ऐसा मुद्दा है, जिसकी आलोचना उसके कट्टर विरोधी भी नहीं कर सकते। चूंकि शीर्ष नेतृत्व का ज्यादातर हिस्सा हिंदी बोलने-लिखने में सहज है, लिहाजा पहले की तुलना में हिंदी का महत्व मोदी सरकार में बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी हों या गृहमंत्री अमित शाह या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों बड़े नेताओं की प्राथमिक भाषा हिंदी ही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हिंदी में ज्यादा सहज हैं। नितिन गडकरी मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों में सहज हैं। भारतीय भाषाओं में सहज ज्यादातर नेताओं की कामकाज की भाषा चूंकि हिंदी है, शायद इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने हिंदी को ही तवज्जो दिया।

दो सौ साल के अंग्रेजी राज और 160 साल के अंग्रेजी शिक्षण के चलते भारत ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है, जहां अंग्रेजी को नकारा नहीं जा सकता। बेशक आजाद भारत के शुरुआती नेतृत्व ने क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी को बढ़ावा देने की बात की, लेकिन उसमें बढ़ावा देने की औपचारिकता ज्यादा थी, व्यवहारिकता कम। इसी कारण स्वाधीन भारत के सामाजिक और व्यवस्थागत जीवन में भारतीय भाषाओं के मुकाबले अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा।

उदारीकरण के बाद जब पश्चिमी आर्थिक हस्तक्षेप बढ़ा, कॉरपोरेटीकरण भारतीय विकास की समानांतर व्यवस्था बना, तो भारतीय भाषाओं के मुकाबले अंग्रेजी का वर्चस्व फिर से बढ़ने लगा। इसका असर हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के साथ ही नौकरशाही में भी दिखा। ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी का उभार हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के लिए उम्मीद की नई रोशनी बनकर आया। हिंदी का नौकरशाही में व्यवहार बढ़ा। शासन के शीर्ष के ज्यादा संपर्क में आने वाली नौकरशाही भी हिंदी सीखने को आतुर दिखती है। इन पंक्तियों के लेखक से एक दिन एक शीर्ष नौकरशाह ने हिंदी सिखाने की अपील की। भारतीय भाषाओं और हिंदी के प्रति सरकारी तंत्र में आए इस सकारात्मक बदलाव का ही असर कहा जाएगा कि नई शिक्षा नीति में भी प्राथमिक स्तर की पढ़ाई के माध्यम के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की वकालत की गई है।

ज्यादातर मंत्रियों का हिंदी में शपथ लेना हो या तंत्र के शीर्ष का हिंदी में बढ़ता व्यवहार हो, इनसे नीचे तक संदेश जाता है। संघ लोक सेवा आयोग ने शीर्ष नौकरशाही के चयन की जो व्यवस्था स्वीकार की है, उसमें भारतीय भाषाओं और हिंदी माध्यम की पढ़ाई के छात्रों की सफलता दर बेहद कम है। इसलिए अब भी नौकरशाही में अंग्रेजी का बोलबाला बना हुआ है। ऐसे नौकरशाह लोकभाषाओं में काम करने में सहज नहीं हैं। आज भी नौकरशाही के स्तर पर बुनियादी सोच से लोकभाषाएं गायब हैं। चिंतन हो या नीति निर्माण, अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। शायद यही वजह है कि अब भी अंग्रेजी को श्रेष्ठि और नागर समाज की भाषा माना जाता है। ऐसे माहौल में भी अगर 55 मंत्री हिंदी में शपथ लेते हैं, तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। हिंदी में शपथ सामान्य जन को भारतीय भाषाओं के प्रति स्नेह और सम्मान के लिए प्रेरित तो करती ही है, उन्हें भारत की सांस्कृतिक और भाषायी विरासत से प्यार करना भी सिखाती है।

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का होगा दूरगामी असर

कोई भी देश तरक्की की राह पर होता है तो हर क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों की भी गिनती होती है। बात जब भारत की होती है तो ये उपलब्धियां बेशुमार नजर आती हैं। यही वजह है कि दुनिया के दूसरे देशों में यहां के रहन-सहन, खान-पान व परम्पराओं को जानने की रुचि भी बढ़ने लगी है। विदेशों में भारत को समझने की इस रुचि का अंदाजा चार धाम की यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से आसानी से लगाया जा सकता है। यह दुनिया के दूसरे देशों में भारत की बढ़ती धमक का प्रतीक भी कहा जा सकता है कि इस बार 109 देशों से करीब बीस हजार विदेशी लोगों ने हमारे यहां चार धाम यात्रा के लिए, पंजीकरण कराया है।

जाहिर है कि चार धाम की यात्रा से लौटने पर ये सब अपने-अपने देशों में भारतीय संस्कृति के संवाहक भी बनेंगे। वैसे भी चार धाम की यात्रा को लेकर आस्था का आलम यह है कि यह माना जाता है कि चार धाम की यात्रा पूरी करने पर ही व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। विदेशी जब भारत में आते हैं और भक्ति भाव का माहौल देखते हैं तो वे बहुत प्रभावित होते हैं। कई तो इसमें रमते नजर आते हैं। वैसे भी भारतीय संस्कृति व यहां के रीति-रिवाजों को अपनाने में विदेशी आगे रहते आए हैं। हमारे इन चार धामों की कीर्ति और जीवन की शांति, सुकून और सार्थकता से जुड़े आध्यात्मिक भाव को विदेशों में भी इसी शिद्दत से महसूस किया जाने लगा है। चार धाम यात्रा में विदेशियों का यह बढ़ा हुआ पंजीकरण राजस्व बढ़ाने वाला भी होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राजस्व कहीं भी रोजगार, समृद्धि और सुख शांति के लिए नितांत आवश्यक घटक है। चार धाम यात्रा की तरह ही कई ऐसे आस्था स्थल और भी हैं, जहां बड़ी संख्या में विदेशियों की आवाजाही होती है। यह भी देखने में आता है कि विदेशी इन आस्था स्थलों पर भारतीय रंग में रंगे नजर आते हैं। निश्चित तौर से हमारे यहां की वेशभूषा व खान-पान से भी विदेशी खूब प्रभावित होते रहे हैं और संस्कृति के अलग-अलग रंग इन्हें सुखद अनुभूति देते हैं। भारत में सांस्कृतिक, पुरातात्विक और धार्मिक पर्यटन के कई ख्यात दूसरे स्थलों को भी इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए ताकि विदेशी पर्यटक आकर्षित हों। इससे राजस्व तो बढ़ेगा ही रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे।

यह भी सच है कि पिछले सालों में केन्द्र व राज्यों की सरकारों ने भी धार्मिक पर्यटन को न केवल बढ़ावा दिया है बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा के बेहतर प्रबंध भी किए हैं। हमारे धार्मिक व स्थलों पर ऐसे प्रयासों में और मजबूती आएगी तो इसका दूरगामी असर होना ही है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि धार्मिक स्थलों की गरिमा और महिमा बनी रहे। वहां जाने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न न हों, जिनसे वहां का माहौल दूषित होता हो। ये स्थान आस्था स्थल ही बने रहने चाहिए, मौजमस्ती के स्थान नहीं बनने चाहिए।

मन है तो कामना है। मन और कामना दो जान पड़ते हैं। मन को पैदा करने के लिए कामना ही 'मन का बीज' कहलाता है। बीज सोमरूप होता है, अतः उसकी स्त्रैण संज्ञा है। ब्रह्म अग्नि तत्त्व है, पुरुष है। उसके मन में कामना पैदा हुई–"एकोऽहं बहुस्याम्"। कामना ही क्षुधा है।

सृष्टि का आधार अत्रिप्राण

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

सूर्य जगत का पिता है, चन्द्रमा माता है। ये दोनों का मृत्युलोक का दाम्पत्य भाव है। ये दोनों माह में एक ही बार मिलते हैं, अमावस्या को। चन्द्रमा की 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। अन्य दिनों में यह संभव नहीं होता। चन्द्रमा स्वयं अत्रि मूर्ति है।

एक प्रश्न उठता है–मैं क्यों पैदा हुआ? एक ही उत्तर है–ब्रह्म का विस्तार करने के लिए पैदा किया गया। यह 84 लाख योनियों का विस्तार है–विश्व रूप में। हर योनि ब्रह्म की योनि है। एकमात्र ब्रह्म हर योनि का पिता है। हर योनि का प्रजापति भी है। हर शरीर को अपने विस्तार के लिए उपयोग में लेता है। मां, पिता, पुत्र (संतान) सभी तो वह खुद ही है। जन्म-मरण ही उसका विस्तार है। जन्म का आधार ब्रह्म है तो मरण का आधार कर्म है। इसी को ऊर्जा और पदार्थ कहा जाता है। ऊर्जा को सरस्वती तथा पदार्थ को लक्ष्मी कहा जाता है। ऊर्जा अग्नि है, पुरुष है, पदार्थ सोम है, सौम्या है। विज्ञान भी कहता है कि अग्नि ही सोम है, सोम ही अग्नि है। दोनों मूल में एक ही हैं। अतः दोनों में दोनों रहते हैं। मात्राभेद से भिन्न जान पड़ते हैं।

मन है तो कामना है। मन और कामना दो जान पड़ते हैं। मन को पैदा करने के लिए कामना ही 'मन का बीज' कहलाता है। बीज सोमरूप होता है, अतः उसकी स्त्रैण संज्ञा है। ब्रह्म अग्नि तत्त्व है, पुरुष है। उसके मन में कामना पैदा हुई–"एकोऽहं बहुस्याम्"। कामना ही क्षुधा है।

या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै-नमस्तस्यै-नमस्तस्यै नमो नमः।। (देवी भागवत)

ब्रह्म एक अव्यक्त तत्त्व है। 'बहुस्याम्' के लिए उसे व्यक्त होना पड़ता है। ब्रह्म की विशेषता यह है कि वह सदा के लिए ठहरा हुआ है। वही तत्त्व एक क्षण के लिए भी ठहरा हुआ नहीं है। वह नित्य शान्त है, नित्य अशांत है। मन से भी तेज दौड़ने वाला यह तत्त्व अव्यय पुरुष है। अव्यय का स्थिर भाग विद्या है, अमृतरूप, अनेजत् (स्थिर) है। इसका कर्म भाग मृत्यु रूप चर है। बनना-बिगड़ना या स्थिति-गति ही विश्वरूप है। द्विनियति या युगल रूप ही सृष्टि का स्वरूप है।

एक सिद्धान्त है युगल तत्त्व के व्यवहार का–एक से दो होना, दो से एक होते रहना। एक-दूसरे के गर्भ में भी बने रहते हैं। **तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्।**

वह सृष्टि करके सृष्टि के भीतर प्रवेश कर जाता है। आकाश स्थिर है। वही गतिमान वायु बनता है। आकाश उसी में समा जाता है। वायु के घर्षण से अग्नि पैदा होता है। आकाश-वायु दोनों अग्नि में समाहित रहते हैं। अग्नि से स्वेदन (जल) उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी। पृथ्वी में चारों भूत रहने से पंचमहाभूत है। पृथ्वी पर उत्पन्न सम्पूर्ण सृष्टि पंच महाभूतयुक्त है। अग्नि में सोम की आहुति अर्थात् सोम जनक (बीज), अग्नि माता (योनि)। अगले चरण में माता ही पिता बनकर नया निर्माण करती है। जो पैदा हुआ वह अग्निप्रधान है। उसका बीज सौम्य होता है।

आत्मा स्पन्दन ही है–प्रसरण, संकुचन। केन्द्र में अग्नि की प्रतिष्ठा रहती है जैसे विष्णु की नाभि में ब्रह्मा। यह अग्नि इन्द्ररूप बाहर फैलता है अन्न लाने के लिए। यही आगे चलकर सोम बन जाता है। विष्णु बनकर केन्द्र की ओर लौटता है। केन्द्र का पोषण करता है। पुनः अग्नि बनकर बाहर फैलता है। ब्रह्मा ही अग्नि बनता है, अग्नि ही सोम बनता है। मूल में तीनों एक ही हैं। इसी को 'हृदय' कहते हैं। अग्नि से सोम पैदा होता है, सोम ही अग्नि को प्रज्वलित रखता है। वही सोम अग्नि में आहूत होकर नया निर्माण करता है। पुरुष अग्नि है। सृष्टि के लिए स्त्री (रेत) को पैदा करता है। स्वयंभू के स्वेदन से अप् की सृष्टि होती है। वह अप् में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार पुरुष शरीर से बीज भी रेत में प्रवेश कर जाता है। तब रेत के साथ अग्नि में आहूत होता है।

ब्रह्म का रेत पांच बार भिन्न-भिन्न अग्नियों में आहूत होता हुआ स्थूल शरीर में प्रकट होता है। इस आहुति का भी निश्चित काल होता है जिसे मानव शरीर (स्त्री) में ऋतुकाल कहा जाता है। कुछ काल विशेष में आहुतियां निषिद्ध भी होती हैं। मल काल अथवा स्त्री में मासिकधर्म की तरह धरती पर भी एक कालक्रम रहता है, जिसमें बीजारोपण निषिद्ध है। इसका आधार अत्रिप्राण होता है। आज चूंकि खेती का यांत्रिकरण हो गया है अतः हल पूजा, बैल पूजा, इन्द्र पूजा के साथ ऊर्वरा भाग तथा ऋतुकाल के सिद्धान्त लुप्त हो गए। अन्न में दैविक भाग तिरोहित हो गया, आसुरी भाव का प्रभाव बढ़ गया। भोक्ता का मन तामसिक होने लगा है।

मेघ भी बिना मर्यादा के नहीं बरसते। हम रोजाना बादल देखते हैं। बिजली नहीं गिरती रोजाना। बरसने वाले बादल का रंग 'घनश्याम' होता है। यही बादल पानी से लदा हुआ वृत्रासुर होता है। इन्द्र अपने विद्युतरूपी वज्र से इसी का वध करते हैं। अन्य मेघों को इन्द्र अपने प्रहार से मुक्त रखता है। इसी प्रकार ऋतुएं भी इसी अत्रि प्राण की मर्यादा से बंधी हैं। वर्ष में एक मलमास भी आता है। इस में शुभ कार्यों का तो निषेध है ही, प्रजनन क्षमता भी ग्रहों के अनुपात में प्रभावित होती है।

सूर्य जगत का पिता है, चन्द्रमा माता है। ये दोनों का मृत्युलोक का दाम्पत्य भाव है। ये दोनों माह में एक ही बार मिलते हैं, अमावस्या को। चन्द्रमा की 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। अन्य दिनों में यह संभव नहीं होता। चन्द्रमा स्वयं अत्रि मूर्ति है। अमावस्या में चान्द्रसोम बहुलता से पृथ्वी पर आता है- औषधि/वनस्पतियों का पोषण करता है। सूर्य-इन्दु के संगम काल को ही अमावस्या कहते हैं। इस दिन चन्द्रमा का सोम तथा पार्थिव अग्नि साथ रहते हैं। अतः अमावस्या को- "**अग्निना-अमा सह वसति (सोमः)**" कहा जाता है। इस अमासोम में सन्तानसूत्र-प्रवर्तक पितर प्राण प्रबुद्ध रहते हैं। सोम के पितर प्राण भी औषधियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। औषधियां ही पुरुषाग्नि में हुत होकर शुक्र रूप में परिणत होती हैं। शुक्र की योषा-अग्नि मं आहुति से प्रजा उत्पन्न होती है। कृष्णपक्ष ही सोम का आदान काल है। सोम ही देवताओं का अन्न है।

पृथ्वी में रहने वाला सूर्य विरोधी, पारदर्शकता का प्रतिबन्धक प्राण (धामच्छद अर्थात् जगह रोकन वाला) अत्रि है। यह वाक् प्रधान है, अतः आवरण का जनक है। प्रबल वेग से घूमते हुए भूपिण्ड के साथ सूर्य के अग्नि का सम्बन्ध होता रहता है। इससे पार्थिव अत्रिप्राण की (पार्थिव अग्निरस) की गति तेज हो जाती है। अत्रि प्राण पिघलकर भूमि के चिपककर घूमता रहता है। तीन परिक्रमा के बाद अत्रिप्राण सोमरूप बन जाता है। यही तरल सोम भाग अत्रिनेत्र से बहकर घनीभूत होता हुआ चन्द्रपिण्ड रूप में बदल जाता है। सोमरूप अत्रि पार्थिव अत्रि से छिटककर ऋतरूप में व्याप्त हो जाता है। पृथ्वी की ओर बढ़ता है।

पुरुष साक्षात वैश्वानर अग्नि की प्रतिमा है। यह सत्याग्नि है। योषित् अग्नि ऋत रूप है–जो ऋताग्नि से बनता है। इसी ऋताग्नि से स्त्री का आत्मा बनता है। स्त्री ऋताग्निमयी है। स्त्री में ऋताग्नि का विकास ऋतुकाल में ही होता है। ऋतुमति स्त्री के ऋताग्नि में जब सोमाहुति होती है, तभी प्रजा उत्पन्न होती है।

क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

आर्ट एंड कल्चर

स्वरों का महल खड़ा कर देते थे मलिक

दरभंगा-अमता घराने की विरासत संजोते उसे निरंतर समृद्ध करने वाले थे पंडित रामकुमार मलिक

ध्रुवपद के दरभंगा, अमता घराने के पंडित रामकुमार मलिक का निधन ध्रुवपद के एक युग का अवसान है। वह जितने सरल थे, उतना ही उनका गान मधुर-सहज था। उनकी लूंठी लयकारी, धैर्यपूर्ण आलाप और फिर उसका विरल विस्तार सुनते मन नहीं भरता। पिता और गुरु पंडित विदुर मलिक से जो कुछ उन्होंने सीखा, उसमें अपने तईं बढ़त करते उन्होंने ध्रुवपद की विरासत को निरंतर समृद्ध–संपन्न किया। बहुत पहले समित मलिक के साथ गाई उनकी बंदिश 'त्रिवेणी, कालिंदी, सरस्वती...' सुनी थी। स्वरों की जैसे यह छलकती गगरी लगी। प्रयाग में त्रिवेणी को जीवंत करती। विद्यापति के पदों में निहित शृंगार ही नहीं दर्शन को भी जिस तरह से गान में उन्होंने जिया, वह अंदर तक मन को मथता है।

डॉ. राजेश कुमार व्यास
संस्कृतिकर्मी, कवि और कला समीक्षक
@patrika.com

खंडार वाणी और गौहर वाणी के संयोजन में पंडित रामकुमार मलिक ने स्वरों का सौंदर्य रचा है।

ध्रुवपद के दरभंगा घराने के संस्थापक पंडित राधाकृष्ण और पंडित कर्ताराम रहे हैं। तानसेन के उत्तराधिकारियों में से एक भूपत खां से उन्होंने ध्रुवपद सीखा। रोचक वाकया है, दरभंगा क्षेत्र में कभी भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों ने सुना था कि ये दोनों भाई मेघ-मल्हार गाते हैं तो वर्षा होती है। दरभंगा नरेश से इनको गवाने की गुहार की गई। दोनों भाइयों ने गाना शुरू किया। घन गरजे और बरसने लगे। तीन घंटे तक लगातार बारिश होती रही। इतना जल बरसा कि पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। तत्कालीन दरभंगा नरेश महाराज माधव सिंह ने इससे प्रभावित होकर दोनों भाइयों को अमता ग्राम सहित कई सौ एकड़ जमीन पुरस्कार स्वरूप दी। ब्राह्मण जमीन के मालिक बने। कालान्तर में मालिक शब्द मलिक बन गया। अमता गांव संगीत का बड़ा घराना हो गया। पंडित रामकुमार मलिक इसी घराने की बारहवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे।

विद्यापति माने ज्ञान के अधिपति। उन्होंने जो लिखा, शब्द में घुला संगीत ही तो है! विद्यापति के कुछ पदों को जिस तरह से पंडित रामकुमार मलिक ने गाया है, उन्हें सुनेंगे तो लगेगा शास्त्र और लोक में गुंथी गान की मौलिक दृष्टि वहां है। एक पद है, 'बिगलित चिकुर मिलित मुखमंडल..'। जैसे स्वरों की बढ़त में दृश्य की मनोहरी छटाएं यहां हैं। विद्यापति ने क्या तो खूब लिखा है और पंडित रामकुमार मलिक ने उसे वैसे ही गान में जिया है। पद का अर्थ है, दो मुख-मंडल परस्पर सट गए हैं। शशि को घनमाला ने घेर लिया। कानों के जड़ाऊ कुंडल हिलने लगे, तिलक पसीने में बह गया! सुंदरी, तुम्हारा मुख मंगलकारी है। किंकिणियां बज रही हैं किन-किन, किन-किन... कंगन बज रहे हैं कन-कन, कन-कन... घन बज रहे हैं नूपुर। रति-रण में कामदेव ने अपनी हार मान ली है। इन शब्दों में निहित अर्थ खोलते पंडित रामकुमार मलिक अपने गान में होले–होले शृंगार रस के अपूर्व से जैसे साक्षात् कराते हैं। ऐसे ही राग ललित और भैरव में 'नारायण हरि तुम...' सुनेंगे तो लगेगा जैसे बहुत जतन से वह स्वरों का महल खड़ा करते हैं।

खंडार वाणी और गौहर वाणी के संयोजन में पंडित रामकुमार मलिक ने स्वरों का सौंदर्य रचा है। राग भीम पलासी में 'शंभु हर गंगाधर...' में शिव के महादेवत्व को जैसे हम पा लेते हैं तो 'ओम, हरि ओम अनंत हरि ओम' का उनका आलाप भी मन में घर करता है। स्वर-शुद्धता के अन्तः उजास में माधुर्य की सहजता को अनुभव करना हो तो पंडित रामकुमार मलिक को सुनें। मन करेगा, गुनें और बस गुनते ही रहें। उनका निधन स्वर को रंजक और श्रुति मधुर बनाते भावों की गहराई वाले दरभंगा-अमता घराने की ध्रुवपद संगीत-दृष्टि की अपूरणीय क्षति है।

नई सरकार: लघु उद्योगों और किसानों पर भी रहे ध्यान

रोजगार को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता तो बने बात

डॉ. अजीत रानाडे
वरिष्ठ अर्थशास्त्री और विचारक
(द बिलियन प्रेस)
@patrika.com

नई सरकार ने शपथ ले ली है और नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। भले ही उनकी पार्टी लोकसभा में पिछले दो बार की तरह पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाई, पर फिर भी वह सबसे बड़ी पार्टी है। देश के राजनीतिक इतिहास में पूर्ण बहुमत प्राप्त पार्टियों की तुलना में गठबंधन सरकारों का वर्चस्व अधिक रहा है। ऐसे में, पिछले दस वर्षों के बाद भारत की राजनीति अपने सामान्य पूर्व इतिहास के दौर में लौट आई है। यह स्थिति उस देश के लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए जहां हर संभावित पहलू विविधताओं से युक्त हैं। इस लिहाज से, लोकसभा का चुनाव एक नहीं, बल्कि 543 सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव है। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, उनमें से ज्यादातर स्थानीय मद्दे होते हैं। बेशक, कभी-कभी किसी करिश्माई व्यक्तित्व के कारण राष्ट्रीय लहर चल जाती है लेकिन चुनावी जीत में अक्सर अन्य कारकों की तुलना में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं।

सवाल यह है कि नई सरकार की प्रमुख वरीयताएं क्या हों और इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं। सबसे अहम मुद्दा रोजगार और आजीविका का है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 29 वर्ष से कम उम्र के युवाओं का बेरोजगारी प्रतिशत 83 था। ऐसे में युवा बेरोजगारी से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ कारणों से यह चुनौती और भी बढ़ी है। पहला ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से खतरा। ये मौजूदा रोजगार के विकल्पों को खत्म कर सकते हैं। मैकिन्से की रिपोर्ट की मानें तो भारत की विनिर्माण क्षेत्र की लगभग 70 फीसदी नौकरियां इसी संकट की चपेट में हैं। दूसरा कारक है- बेमेल कौशल (उम्मीदवारों का कौशल और दक्षताएं पद की अपेक्षाओं के साथ मेल न खाना)। हमारे यहां तो नौकरियों और कौशल दोनों की कमी एक साथ है। ऐसे में हमें कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने की जरूरत है जो हमारे युवाओं को कल की नौकरियों के लिए तैयार कर सके। काम करने या सीखने से ही कौशल विकास और संवर्धन होता है जो मानव पूंजी के रूप में होता है। नई सरकार जो उपाय कर सकती है, वह है राष्ट्रव्यापी अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम पर जोर देना। इसमें छह से नौ माह का रोजगार भी मिलेगा और नियोक्ता पर कर्मचारी को स्थाई करने का दायित्व भी नहीं रहेगा। इसकी स्वीकार्यता पूरे देश में होनी चाहिए। हालांकि, अनेक राज्यों में अप्रेंटिसशिप पॉलिसी और प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रचनात्मक तरीके से इसके लिए और प्रयास की जरूरत है। रोजगार बढ़ाने का एक और रास्ता है अग्निवीर कार्यक्रम। इसे तीन से चार साल तक बढ़ाना चाहिए क्योंकि चार साल की अवधि बहुत कम है। रोजगार को लेकर सरकार जिस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है, वह है - छोटे उद्यमी। छोटे और लघु व्यवसायों के समक्ष ऋण और कार्यशील पूंजी, बाजार, प्रौद्योगिकी और फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी तक पहुंच चार बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के मद्देनजर केंद्र सरकार एक तंत्र बना सकती है जिससे छोटे उद्यमियों को मदद मिलेगी। बाजार तक पहुंच को ई-कॉमर्स और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे नवाचारों के जरिए आसान बनाया जा सकता है। एमएसएमई में ऋण प्रवाह को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी की मदद से सरकार एक मुफ्त सुपर ऐप भी ला सकती है जो टैक्स, मार्केटिंग और ग्राहक संबंध से लेकर हर चीज का ध्यान रख सके।

ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ने से रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। इसलिए इस चुनौती को भी समझना आवश्यक है।

एक अन्य मद्दा किसानों और सुनिश्चित कीमतों से संबंधित है। अब समय आ गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र को कानूनी शक्ति दी जाए और इसे कानून का रूप दिया जाए। यह जरूर है कि 22 फसलों के लिए एमएसपी तभी लागू होता है, जब बाजार की कीमतें तय सीमा से कम हो जाती हैं। आंकड़ों के आधार पर कहें तो तो ऐसी स्थिति लगभग आधे समय ही आती है। लिहाजा, शुद्ध राजकोषीय बोझ उतना अधिक नहीं है जितना भय था। इसके अलावा, सरकार जब खरीद शुरू करती है तो कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। इस वजह से एमएसपी गारंटी की जरूरत खत्म हो जाती है। इस स्तर पर देखा जाए तो एमएसपी कानून मुख्यतः एक राजनीतिक निर्णय है लेकिन यह किसानों का विश्वास जीतेगा।

सेहत: कई प्रकार के रसायनों की भरमार है खाद्य पदार्थों में

स्वास्थ्य का दुश्मन है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रहें इससे दूर

लीना एस. वेन
जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के मिलकेन इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के लिहाज से देखा जाए तो यह साल काफी बुरा बीता है। जनवरी माह में प्रकाशित ब्रिटेन की एक पत्रिका में 45 अलग–अलग अध्ययनों की एक साथ सामूहिक समीक्षा की गई। इसके माध्यम से दर्शाया गया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सेवन से स्वास्थ्य को क्या-क्या नुकसान होते हैं। दिल के दौरे और हृदयाघात के कारण बढ़ती मौतों की संख्या से लेकर शरीर में मधुमेह, कैंसर, निद्रा संबंधी विकारों का बढ़ना, बेचैनी और अवसाद जैसी बीमारियों के मूल में कहीं न कहीं इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का ही हाथ होता है। गत माह 'न्यूरोलॉजी' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सेवन का डिमेंशिया से गहरा संबंध है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन यदि 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की आशंका 16 प्रतिशत बढ़ जाती है। स्वास्थ्यवर्धक आहार लेने वाले भी कभी-कभार अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करें तो उनके स्वास्थ्य को नुकसान की आशंका भी इतनी ही देखी गई।

इस तरह के आंकड़ों से हमारा आहार संबंधी व्यवहार नहीं बदलेगा। कारण यह है कि आजकल का हमारा खान-पान काफी हद तक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर ही निर्भर है। मतलब हम जो कुछ भी खा रहे हैं, उसमें कई प्रकार के रसायनों की भरमार है। जैसे खाने का स्वाद बढ़ाने वाले इमल्सिफायर जो अलग–अलग फ्लेवर को मिक्स करके रखते हैं, कृत्रिम रंग, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव व थिकनर्स। दैनिक उपभोग की करीब 60 प्रतिशत कैलोरी हम इसी प्रकार के खाद्य पदार्थों के सेवन से प्राप्त कर रहे हैं। समय के साथ अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ा है। सभी आयु वर्ग के लोग ऐसे खाद्य पदार्थों का खूब सेवन कर रहे हैं।

आजकल के खान-पान से अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को पूरी तरह हटाना तो संभव नहीं है लेकिन इसकी कुछ मात्रा कम अवश्य कर सकते हैं। हां, यह थोड़ा मुश्किल जरूर है। आइए, शुरूआत करें उन कुछ आसान उपायों से जो आपके आहार में से अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य को कम कर सकते हैं। ये इस प्रकार हैं-

पहला,ऐसा आहार लें जो प्राकृतिक हो और बहुत कम प्रसंस्कृत हो। सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैं वे आहार जो पशु या पेड़-पौधों से मिलते हैं। जैसे ताजे फल, सब्जियां, चिकन, मछली और अंडे। दूसरे, इस प्रकार तैयार किए गए भोजन,जिसमें थोड़ा बहुत ही बदलाव किया गया हो। जैसे कटी हुई फ्रोजन सब्जियां और सूखे मेवे। इस स्तर पर खाद्य सामग्री तैयार करने में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में खास परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। तीसरे,खाद्य सामग्री को इस प्रकार तैयार करना कि उसमें ऊपर से अतिरिक्त सामग्री मिलाई जाए। जिन्हें बनाने के लिए गेहूं,तेल व नमक डाला जाता है या फिर आटे, यीस्ट, चीनी, नमक व तेल को मिलाकर बेक करके बनाई गई होल ग्रेन ब्रेड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को कुछ अतिरिक्त पदार्थों के साथ पैक किया जाता है। इनमें वे खाद्य पदार्थ आते हैं, जो जंक फूड की श्रेणी में आते हैं, जैसे सोड़ा, चिप्स, कैंडी और डोनट्स। इसके अलावा हॉट डॉग, दुकान से खरीदी गई सफेद ब्रेड, फ्रैंच फ्राइज, बहुत सारे रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ एवं फ्रोजन पिज्जा। जितना संभव हो सके,कम से कम प्रसंस्कृत किया हुआ आहार ही चुनें।

जिस माहौल में हम रह रहे हैं, उसमें अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन इनका इस्तेमाल कम तो किया जा सकता है।

बेहतर तो यह है कि स्टोर में सामने रखे सामान को पहले चुनें। आम तौर पर ग्रोसरी स्टोर वाले दुकानदार ताजा सामान को बाहर की ओर रखते हैं और प्रोसेस्ड व अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को दूसरी पंक्ति में। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सामान सामने रखी पहली पंक्ति से उठाएं। हालांकि जरूरी नहीं कि बाहरी पंक्ति में रखा सारा ही सामान स्वास्थ्यवर्धक हो। बाकी सभी खाद्य पदार्थों के निर्माण में काम में ली गई सामग्री की जानकारी लें। ऐसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को चिह्नित करें, जिन्हें स्वास्थ्यवर्धक बताया जा रहा हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्पादकों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को 'पोषक' बताकर बेचने की छूट मिली हुई है। इसलिए सावधान रहें। इस प्रकार के लेबल वाले कई उत्पाद अन्य जंक फूड उत्पादों से बेहतर नहीं हैं। मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करें। जिस माहौल में हम रह रहे हैं, उसमें अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन इनका इस्तेमाल कम तो किया जा सकता है।

आपकी बात

धैर्य रखें, फायर ब्रिगेड की मदद लें

आवश्यक सावधानी बरतकर आग की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके बावजूद आग लगने पर समझदारी से काम लेना चाहिए। मदद के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। अपने स्तर पर आग बुझाने के लिये पानी, रेत, कंबल आदि का प्रयोग करना चाहिए। बिजली की सप्लाई को बंद कर देना चाहिए।

-नरेश कानूनगो, देवास, मप्र

अतिक्रमण हटाया जाए

सभी इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पुरानी इमारतों में बाहर निकलने की जगह तक नहीं मिलती। मकानों के आगे-पीछे अतिक्रमण आम हो गए हैं। इससे आग लगने पर बचने की जगह भी नहीं मिलती। सरकारी मशीनरी को इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए और अतिक्रमण हटाना चाहिए।

-नरेंद्र विश्नोई, सांचौर, जालोर

गैस एजेंसियों की जिम्मेदारी

गैस सिलेंडर भी आग लगने की प्रमुख वजह बन रहे हैं। इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गैस कंपनियों और एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि वे सिलेंडरों की सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करें। साथ ही गैस रिसाव संबंधी कोई शिकायत आए तो तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे अनहोनी न हो।

-प्रकाश शर्मा, जयपुर

आज का सवाल

आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता कैसे दूर हो सकती है?
ईमेल करें: edit@epatrika.com

कल का सवाल था: आग लगने की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है?

सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता कि तुमने किससे, कहां, क्या कहा।

–राबर्ट बेर्न्स

बेकाबू महंगाई

महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। मई में थोक महंगाई पिछले पंद्रह महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। अब यह 2.61 फीसद पर है, जबकि अप्रैल में यह 1.26 फीसद थी। इसी अवधि में पिछले वर्ष यह नकारात्मक 3.61 फीसद पर थी। जबकि इसके उलट खुदरा महंगाई मई में घट कर 4.75 फीसद पर पहुंच गई, जो इस वर्ष का सबसे निचला स्तर है। थोक महंगाई पिछले तीन महीने से लगातार बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, कच्चे तेल और गैस तथा अन्य विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इस वर्ष मई में थोक महंगाई बढ़ी। खासकर सब्जियों की थोक कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। सब्जियों की थोक महंगाई दर 32.42 फीसद रही। प्याज की थोक महंगाई दर 58.05 फीसद और आलू की 64.05 फीसद दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक आमतौर पर खुदरा महंगाई दर के आधार पर अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव करता है। मगर मई में खुदरा महंगाई पांच फीसद से कम होने के बावजूद उसने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला किया। इसलिए कि उसका अनुमान है कि अभी महंगाई का रुख अनिश्चित बना रहेगा और उसमें उतार-चढ़ाव आ सकता है।

आमतौर पर थोक महंगाई का असर खुदरा महंगाई पर पड़ता है। जो चीजें थोक में महंगी होती हैं, उनकी खुदरा कीमतें भी बढ़ती हैं। मगर बीते मई महीने में यह क्रम उलटा देखा गया। थोक महंगाई बढ़ी, पर खुदरा महंगाई कम हुई। महंगाई बढ़ने के पीछे आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का तर्क दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से रूस-यूक्रेन युद्ध और फिर इजराइल-हमास संघर्ष के चलते दुनिया भर में आपूर्ति शृंखला बाधित हुई है। विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। जाहिर है, इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। मगर यह कोई पहला मौका नहीं है, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कई वर्ष से हो रही है, जिसका प्रभाव माल ढुलाई पर देखा गया है। मई महीने में तेल की कीमतें इतनी बढ़ी भी नहीं कि उसका सीधा प्रभाव थोक महंगाई पर पड़े। फिर, खुदरा महंगाई घटी हुई कैसे दर्ज हुई, जबकि इसका असर उस पर भी पड़ना चाहिए था। दरअसल, खाने-पीने की चीजों की कीमतों में असंतुलन की बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय व्यापार है।

महाराष्ट्र के किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि प्याज को निर्यात के लिए खोल दिया जाए, मगर सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसकी वजह से उन्हें अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही और खुदरा बाजार में औने-पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। इसके उलट, बाहर से दालों, फलों, खाद्य तेल आदि पर आयात शुल्क घटा या हटा देने की वजह से घरेलू जिंस की जगह विदेशी चीजें थोक बाजार में अधिक पहुंचने लगी हैं। यह समझना मुश्किल है कि जो खाद्य वस्तुएं अपने यहां जरूरत से अधिक पैदा हो रही हैं, उनकी घरेलू बाजार में खपत बढ़ाने पर जोर देने के बजाय विदेशी वस्तुओं की आवक क्यों बढ़ाई जाती है। खानेपीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी क्रयशक्ति बढ़ाना पहले ही बड़ी चुनौती है, तिस पर महंगाई की मार उनका जीवन दूभर बना देती है।

निष्पक्षता की दरकार

एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में बंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पाक्सो कानून के तहत गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हालांकि अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, पर इस प्रकरण से उनके दामन पर जो दाग लगा है, वह धुलेगा या नहीं, कहना मुश्किल है। एक किशोरी की मां ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने अपने आवास पर उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। हालांकि येदियुरप्पा के वकील का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला आदतन इसी तरह लोगों का भयादोहन करती रही है। येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। चूंकि मामला पाक्सो कानून के तहत दर्ज किया गया है, इसलिए येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बता कर वे इससे बच पाएंगे, कहना मुश्किल है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनेताओं पर कई बार कुछ ऐसे आरोप उनके प्रतिपक्षियों द्वारा भी साजिशन लगा दिए जाते हैं, ताकि वे उलझे रहें और उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो जाए। येदियुरप्पा कर्नाटक के एक प्रभावशाली नेता हैं और उन्होंने वहां भाजपा की जड़ें मजबूत की हैं। बेल्लारी बंधुओं से निकटता और कुछ ठेकों के आबंटन में पक्षपातपूर्ण निर्णयों की वजह से वे विवादों में जरूर आए थे, पर उनका जनाधार बहुत कमजोर नहीं हुआ। इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का तर्क कुछ देर ठहर भी सकता है, मगर आखिर उनके विवेक और आचरण पर तो सवाल रहेंगे ही। सार्वजनिक जीवन में राजनेता का आचरण बहुत मायने रखता है। कैसे एक किशोरी के साथ उनका व्यवहार ऐसा अमर्यादित रहा, जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में मान लिया गया और अदालत ने भी उसे सही पाया। इस मामले में कितनी सच्चाई है, यह निष्पक्ष रूप से सामने आनी चाहिए। इसे राजनीतिक प्रभाव में दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो उस किशोरी के साथ अन्याय होगा। फिर इस तरह के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल ही रहेगा।

प्रदूषण का प्रहार झेलती महिलाएं

यों प्रदूषण सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण उन पर और अधेड़ उम्र की महिलाओं के स्वास्थ्य पर घातक असर डाल रहा है।

गीता यादव

भारत में वायु प्रदूषण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व की लगभग पूरी आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है, जिसमें प्रदूषक तत्त्व तय दिशा-निर्देशों की सीमा से कहीं अधिक है। 2019 में इसकी वजह से करीब 67 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। यों प्रदूषण सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण उन पर और अधेड़ उम्र की महिलाओं के स्वास्थ्य पर यह घातक असर डाल रहा है। बुजुर्ग महिलाएं अपना अधिकांश समय घरों के भीतर व्यतीत करती हैं। मगर वे घर के भीतर भी वायु प्रदूषण से जूझ रही हैं। प्रदूषण के कारण उनमें नेत्र, त्वचा, नाक, गले में खुजली, चक्कर आना, थकान, रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, अवसाद, अनिद्रा, बहरापन, मानसिक रोग, पेट संबंधी रोगों में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल में हुए शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण से कुछ गंभीर रोग भी तेजी से बढ़े हैं, जो बुजुर्ग महिलाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।

चिकित्सक मानते हैं कि वायु प्रदूषण से फेफड़े और दिल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अध्ययन बताते हैं कि भारत में हर एक हजार में से बीस बुजुर्ग वायु प्रदूषण से मनोभ्रंश के शिकार हुए हैं। बुजुर्ग महिलाओं में इसका प्रसार अधिक बताया गया है। 'इंपीरियल' के पर्यावरण अनुसंधान समूह के प्रमुख और लेखक, प्रोफेसर फ्रैंक केली के मुताबिक इक्कीसवीं सदी में स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के लिए डिमेंशिया सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। येल और पेकिंग विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप से हुए एक अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्गों के मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। अध्ययन के मुख्य आथर जियाबो जैंग का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों की बोलने की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है। दिमाग पर वायु प्रदूषण का इतना बुरा असर होता है कि बहुत से लोग बोलने के लिए शब्द तक मुंह से नहीं निकाल पाते हैं। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक वायु प्रदूषण की चपेट में रहता है, तो उसकी अनुभूति की क्षमता ज्यादा प्रभावित होती है।

जब कभी वायु प्रदूषण की बात उठती है तो घरेलू वायु प्रदूषण को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि घरेलू वायु प्रदूषण कई तरह की जानलेवा बीमारियों की वजह है। अंदरूनी हवा उतनी ही विषैली होती है, जितनी कि बाहरी। शहरी परिवेश के साथ ग्रामीण परिवेश में भी घरों में मौजूद वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। 'जर्नल बीएमसी' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, जो महिलाएं अपने घरों में वायु प्रदूषण के संपर्क में हैं, उनमें याददाश्त, रोजमर्रा के कामों को करने की क्षमता, तार्किक और बौद्धिक क्षमता अन्य महिलाओं की तुलना में कम है। आज भी विकासशील देशों में अधिकांश ग्रामीण घरों में खाना पकाने के लिए दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी मिट्टी का तेल, लकड़ी, फसलों के अवशेषों, गोबर और कोयला आदि इस्तेमाल करती है, जो कि घरों में हानिकारक वायु प्रदूषण का कारण बनता है। ग्रामीण परिवेश में किए शोध और आंकड़े बताते हैं कि यह खतरा बुजुर्ग और अधेड़ महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है। कोयले के संपर्क में रहने वाली महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर का जोखिम दोगुना होता है।

> शहरी परिवेश के साथ ग्रामीण परिवेश में भी घरों में मौजूद वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। 'जर्नल बीएमसी' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, जो महिलाएं अपने घरों में वायु प्रदूषण के संपर्क में हैं, उनमें याददाश्त, रोजमर्रा के कामों को करने की क्षमता, तार्किक और बौद्धिक क्षमता अन्य महिलाओं की तुलना में कम है। आज भी विकासशील देशों में अधिकांश ग्रामीण घरों में खाना पकाने के लिए दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी मिट्टी का तेल, लकड़ी, फसलों के अवशेषों, गोबर और कोयला आदि इस्तेमाल करती है, जो कि घरों में हानिकारक वायु प्रदूषण का कारण बनता है।

मेडिकल जर्नल 'ट्रांसलेशनल साइकेट्री' द्वारा 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि वृद्ध महिलाएं, जो उच्च स्तर के बारीक कण वाले पदार्थ सहित प्रदूषित क्षेत्रों में रहती हैं, वे तेजी से उम्र बढ़ने और दिमाग की कमजोरी का अनुभव करती हैं। उनमें मनोभ्रंश और अल्झाइमर जैसी बीमारियों के लक्षण देखने को मिले। स्पेन के बार्सिलोना में 'यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी इंटरनेशनल कांग्रेस' में प्रस्तुत किए गए नए अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं के लिए डीजल के धुएं में सांस लेना जानलेवा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने डीजल निकास के संपर्क में आने से लोगों के खून में बदलाव की बात कही है। इससे महिलाओं में सूजन, संक्रमण और हृदय रोग से संबंधित रक्त के घटकों में परिवर्तन पाए गए हैं। शोध के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर के लगभग दस में से एक मामले के लिए बाहरी वायु प्रदूषण एक कारण हो सकता है। वायु प्रदूषण के कण कोशिकाओं में डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कैंसर का जोखिम हो सकता है।

हार्वर्ड टीएच के नेतृत्व में एक अध्ययन में पाया गया कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से बुजुर्गों में अवसाद का खतरा बढ़ सकता है। सिर्फ पांच दिनों तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से बुजुर्ग महिलाओं में आघात का खतरा बढ़ सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 'मेलमैन स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ' के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि वातावरण में बढ़ता वायु प्रदूषण महिलाओं की हड्डियों के लिए भी खतरनाक है। अध्ययन के अनुसार बढ़ती उम्र में वायु प्रदूषण का संपर्क महिलाओं में 'बोन मिनरल डेंसिटी' में कमी के साथ आस्टियोपोरोसिस से भी जुड़ा है। इसकी वजह से हड्डियों के टूटने का जोखिम बढ़ जाता है। इससे पहले भी शोध में इस बात के सबूत सामने आए थे कि वायु प्रदूषण महिलाओं की हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। 1990 से 2019 के बीच कम होती 'बोन मिनरल डेंसिटी' और उनमें टूटन के कारण विकलांगता में 121 फीसद की वृद्धि हुई है।

शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण के सूक्ष्म कणों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से रजोनिवृत्ति के बाद की महिला में हृदय संबंधी रोग के जोखिम और मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि स्तन कैंसर की घटनाओं में सबसे अधिक वृद्धि उन महिलाओं में पाई गई, जिनका संपर्क 'पार्टिकुलेट मैटर' स्तर पीएम 2.5 से अधिक था। मोटर वाहन से निकलने वाले धुंए, तेल कोयला जलाने या लकड़ी के धुंए आदि में पीएम 2.5 अधिक होता है। बुजुर्ग महिलाएं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होती हैं। उन्हें उन खतरों के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी हवा कितनी खराब हो सकती है। इसे कम करने और इससे खुद को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। वे जहां रहती हैं, वहां वायु की गुणवत्ता की दैनिक आधार पर निगरानी करें। जहां प्रदूषण अधिक है, वहां न जाएं। औद्योगिक प्रदूषण वाली जगहों से दूर रहें। घर में खाना पकाने और रोशनी के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें। रसोई का क्षेत्र अच्छी तरह हवादार हो। स्टोव, चिमनी और अन्य उपकरणों का रखरखाव करें, ताकि वे कुशलतापूर्वक ईंधन जला सकें। भवन और पेंट उत्पाद, सफाई और घरेलू रसायनों सहित इनडोर प्रदूषकों के अन्य सामान स्रोतों से सावधान रहें। हमारे बुजुर्ग जितने स्वस्थ होंगे, वायु प्रदूषण के संपर्क के बाद स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही कम होंगी।

धन-दौलत की जगह

पूनम पांडे

धन कमाने की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है। मेहनत करके रुपया जोड़ने की इच्छा एक तरह की सकारात्मक चाह है, जो रोटी, कपड़ा और छत हासिल करने में सहायक होती है। संसार में जीने के लिए धन जरूरी है। इसीलिए किसी हुनर पर चिंतन, मंथन और उसमें अभ्यास करके पारंगत होना, फिर उससे धन कमाने की जुगत स्वाभाविक है। इस प्रक्रिया में मेहनत और लगन एक आधारभूत भूमिका निभाते हैं। लगभग सभी अपने मन की सचेतन और जागृत अवस्था में यह सोचते हैं। काम करके रुपया मिलेगा, पैसा आएगा, नकद या डिजिटल। मगर आज के भौतिक सुख प्राप्ति के समय में हर बात पर हर चीज के बदले बस धन की प्राप्ति हो, यही बात जरा नकारात्मक है।

धन पाकर अमीर बनने का स्वप्न इंसान के दिलोदिमाग पर निरंतर प्रवहमान और परिवर्तनशील होते हैं। कुछ लोग अमीर बनकर अपना अतीत भी भूल जाते हैं। आडंबर करने लगते हैं। फिर मानसिक रोगी बनते हैं। बचा-खुचा धन इलाज में खप जाता है। मगर आज इस पर सतत चिंतन की जरूरत है। समझ होनी चाहिए कि रुपया कमाना है, इसलिए कि जी सकें। यह पूरा जीवन ही धन कमाने में लग जाए, यह मानसिक विकार है। येन-केन-प्रकारेण किसी के कंधे पर चढ़कर या किसी का हक मारकर या किसी को बेवकूफ बनाकर या खुद को मशीन बनाकर दौलत जमा करना निंदनीय है। कुछ समय पहले एक विचार गोष्ठी में एक साठ वर्ष का कारोबारी उठा और रोने लगा। उसने ही पैसे खर्च कर उस गोष्ठी का आयोजन कराया था। मगर उसके रोने की वजह यह थी कि उसने पैंतीस साल तक खूब मुनाफे पर 'बेबी फूड' बेचा, मगर मिलावट भी खूब धड़ल्ले से करता रहा। मगर जब उसके जुड़वां पोते विकलांग पैदा हुए और इलाज भी काम न आया, तब उसने इसे अपने कर्म का फल मानकर यह काम ही बंद कर दिया।

इस तरह का अनुभव लोगों के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है कि धन कमाना चाहिए, मगर गलत ढंग से नहीं। धन कमाने की ललक में किसी को धोखा देना भी एक ऐसा कर्म है, जो किसी के हाथों हमें भी चुकाना ही होगा। मौजूदा परिवेश में विकास और भावी योजनाओं की समृद्धि के लिए धनवान होना जरूरी है, मगर इसमें रातोंरात नहीं। मेहनत करते हुए धीरज रखना ही सबसे अच्छा कदम है। धन एकत्र करने की धुन में यथासंभव दूसरों की जेब में डाका कभी भी नहीं डालना चाहिए। बुद्ध राजकुमार थे, लेकिन सब धन त्याग दिया, तब जीवन सफल हुआ। स्वामी विवेकानंद ने राजघरानों में खुद जाकर चंदा मांगा, तब जाकर मानवता के लिए अपना उद्देश्य पूरा कर सके।

धन-दौलत पर एक ही व्यक्ति के विचार समय, स्थिति और स्थान के अनुरूप अलग-अलग हो सकते हैं। माहौल के कारण व्यक्ति लोभी भी बन जाता है और कभी दानी भी। धन को लेकर मन में उठने वाली प्रत्येक बात या सूझ भी उपयोगी नहीं होती है। जुए से कौड़ी को अशर्फी बनाने का विचार उपयुक्त नहीं है। कारण कि इसके मूल में चिंतन की प्रौढ़ता और परिपक्वता नहीं है। बहुत अधिक धन रखने वाले व्यक्ति को धनवान कहा जा सकता है, लेकिन जरूरत पर भी खर्च न कर उसे बहुत अधिक संभाल कर रखने वाले व्यक्ति को विवेकी तो नहीं कहा जा सकता। विवेकवान से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके धन में समाज का हित और आत्मकल्याण का भाव निहित हो। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कविवर निराला एक बार रात के समय कवि सम्मेलन से लौट रहे थे। राह में एक भिखारी कड़ाके की ठंड में कांप रहा था। भूखा भी था। निराला को कवि सम्मेलन से धनराशि का एक लिफाफा मिला था। उन्होंने वह धनराशि उस गरीब पर खर्च कर दी। उसके बाद आनंद से झूमते हुए चले।

हमारा धन किसके लिए उपयोगी है, इन विचारों की त्वरा हमारे अंदर एक नागरिक का भाव पैदा करती है, जबकि मेरा धन मेरे लिए है, इसको बस मैं ही भोगता रहूं, ऐसे भाव हमें अमानुषिकता की ओर ले जाते हैं। धनवान बनकर सामाजिक से साधक तक की मानवता की एक पूरी यात्रा होती है। धन से किसी का भला हो, यह एक तरह का परोपकार है। यह जन कल्याण की उमंग है। यह भूलना नहीं चाहिए कि धन भी समाज कल्याण का माध्यम है। धन को सबसे साझा करना, मन की उन्नत अवस्था का सूचक है। जबकि धन पाकर मन में चंचलता, लोभ और कंजूसी अपरिपक्व मन की निशानी है। शास्त्रों में बताया गया है कि हम अपने धन से समाज में समानता और सौहार्द निरंतर उत्सर्जित करें और संतोष बनाए रखें। कमाई हुई पूंजी समाज कल्याण के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन है, लेकिन कभी-कभी देखने में आता है कि व्यक्ति संसाधनों का दुरुपयोग कर भ्रष्ट तरीके से अपने लिए धन संग्रह कर लेता है।

कई बार गरीब कल्याण योजना के प्रणेता भी लोक कल्याण की आड़ में नकद राशि का दुरुपयोग कर आत्म-उन्नयन में लग जाते हैं। वे किसी खास समुदाय, धर्म या संप्रदाय के उत्थान और उन्नयन का सब्जबाग दिखाकर एक फर्जी फाइल बनाते हैं और उसे ही प्रचारित करते हैं और संस्थाएं स्थापित करते हैं। फिर समर्थकों का एक जनसमूह तैयार करके उसका उपयोग आत्म-उन्नयन और धन संचयन के लिए करते हैं। ऐसी स्थिति में वे केवल लोभी और धन के दास मात्र बनकर रह जाते हैं। इसीलिए अपने समाज को परिवार मानकर उसका कल्याण करने वाले मेहनत करके जो दौलत पाते हैं, उससे वे धन-लोलुप नहीं बनते। ऐसे लोग जब भी नजर आते हैं, उनके निखरे हुए चेहरे, संतोष भरी वाणी, बातचीत आदि इस बात को खुद ही प्रमाणित कर देते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> यह नहीं भूलना चाहिए कि धन भी समाज कल्याण का माध्यम है। धन को सबसे साझा करना, मन की उन्नत अवस्था का सूचक है। जबकि धन पाकर मन में चंचलता, लोभ और कंजूसी अपरिपक्व मन की निशानी है। शास्त्रों में बताया गया है कि हम अपने धन से समाज में समानता और सौहार्द निरंतर उत्सर्जित करें।

अन्न का अपमान

थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद हमारे देश में भुखमरी और कुपोषण पर चिंताजनक खबरें आती रहती हैं। देश में एक तरफ प्रतिदिन टनों पका हुआ भोजन बर्बाद होने की खबरें आती हैं, तो दूसरी तरफ भूख से मरने वालों की। जहां एक ओर रेस्तरां में और शादियों में लोगों की थालियों में जरूरत से ज्यादा भोजन देखा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर भोजन के अभाव में भुखमरी से मौत की खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। सरकार का यह दावा है कि अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है, और लाखों लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है, फिर ऐसे में कुपोषण या भुखमरी की खबरें कहां से आती हैं। क्या पता, भ्रष्टाचार की वजह से राशन गरीबों तक पहुंचने की बजाय बिचौलियों के घरों में पहुंच जाता हो। सरकारों को गरीबों को गरीबी से निकालने के प्रयास करने चाहिए। उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वे आत्मसम्मान से जिंदगी जीने के लिए मेहनत करें और अपना और अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करें और वे लोग जो खाने की बर्बादी करते हैं उन्हें भी यह सिखाना चाहिए कि थाली में उतना ही भोजन लें, जितनी भूख हो। भोजन बर्बाद करके अन्न का अपमान न करें।

– चरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली

आतंक का सिलसिला

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में एक धार्मिक स्थल से हिंदू श्रद्धालुओं की लौट रही बस पर आतंकवादियों द्वारा कायरता पूर्ण हमला करके दस तीर्थयात्रियों को मार दिया गया। यह बेहद शर्मनाक कृत्य है। साफ हो गया है कि यह हमला पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आइएसआइ की शह पर आंतकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने रचा था। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद पाकिस्तान भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवादियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि दो दिन में तीन जगहों पर हमले करने में कामयाब रहे। साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला किया गया। सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। चिंता की बात है कि जम्मू में आंतिकयों की सक्रियता बढ़ रही है। जो लोग इनको अपने घरों में शरण देते हैं, आतंकियों के साथ ही ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना होगा।

– बीर सैन सरल, गाजियाबाद

मणिपुर का दर्द

संपादकीय 'मणिपुर की आग' (12 जून) ने साल भर से हिंसा की आग में झुलस रहे राज्य में भय और आशंकाओं के बीच जी रहे लोगों की मनः स्थिति को रेखांकित किया है। कुकी और मैतेई समाज जिस प्रकार एक-दूसरे को मरने-मारने पर उतारू हैं, वह इस बात का संकेत है कि उनके बीच संघर्ष कितना तीव्र है। बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों का मारा जाना और अथाह संपत्ति का नुकसान न केवल राज्य, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी घातक है। न जाने क्यों केंद्र सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान एक कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। समय रहते अगर इसे नहीं रोका गया तो यह वर्ग संघर्ष हमारी सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि विदेशी ताकतें इस पर नजर गड़ाए बैठी हैं। सरकार को अब इस संघर्ष को सख्ती से दबाना चाहिए।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

बुजुर्गों की सेहत

मस्तिष्क में अमाइलाइड प्रोटीन का जमाव बुढ़ापे में तेज हो जाता है। यह खबर समाचार पत्र में पढ़ी। अक्सर कई बुजुर्ग खुली हवा में घूमने और व्यायाम द्वारा अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। उनका कहना है कि आरोग्य और दीर्घ जीवन के लिए मानसिक शक्ति का बड़ा महत्त्व है। डाक्टरों के अनुसार अगर कसरत साधारण, नियमपूर्वक लेट कर की जाती है, तो बुढ़ापे में शरीर को तंदरुस्त तथा चुस्त रखा जा सकता है। टहलना, योग आदि सबसे सही उपाय है, साथ ही सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करना भी। बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा खजाना है, जिसमें अनुभव,आशीर्वाद, सम्मान के रत्न समाहित हो जाते है। बस नई पीढ़ी बुजुर्गों का सम्मान करें। उन्हें ठुकराएं और झिड़कें नहीं। आखिर हमें भी तो समय आने पर ऐसे रत्नों को अपने जीवन में समाहित कर आगे आने वाली पीढ़ी में बांटना है।

– संजय वर्मा 'दृष्टि', धार, मप्र

https://t.me/AllNewsPaperPdf

www.readwhere.com

चिंतन

जी-7 बैठक से निकले युद्ध समाप्ति की राह

रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल-हमास जंग की समाप्ति होनी चाहिए। युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। इसका उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध से लेकर वर्तमान में रूस व यूक्रेन जंग तक है। युद्ध ने कभी भी शांति का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है। हमास, हूती, हिज्बुल्लाह, इस्लामिक स्टेट, तालिबान, अलकायदा, हिज्बुल, लश्कर, जैश जैसे कट्टर इस्लामिक गुटों के आतंकवाद के खिलाफ भी जी-7 को एकजुट होना चाहिए। अब जब सात विकसित देश इटली की मेजबानी में जी-7 की बैठक कर रहे हैं, तो इसमें चर्चा का मुख्य विषय रूस व यूक्रेन जंग ही है। भारत समेत करीब एक दर्जन देश इटली के विशेष आमंत्रण पर जी-7 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जी-7 की बैठक के एजेंडे में भी रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव (इजराइल-हमास जंग, व हूती व हिज्बुल्लाह का आतंक) को समाप्त करने की राह तलाशने पर चर्चा करना शामिल है। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ बिना सिलेक्टिव हुए सामूहिक लड़ाई की जरूरत है। टेरर फंडिंग के स्रोतों को पहचानने व उसे रोकने की आवश्यकता है। जी-7 की बैठक की सार्थकता तभी अधिक होगी, जब दोनों युद्ध को खत्म करने के रास्ते निकलेंगे। आतंकवाद के खात्मे के लिए एक मैकेनिज्म बनेगा। यह भी विडंबना ही है कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका व चीन के होते हुए भी रूस व यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में भी जारी है। हजराइल व हमास जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जंग के लिए यूक्रेन और इजराइल व हमास को मदद करने वाले मुल्कों को अपनी नीति पर विचार करना चाहिए। रूस ने वादा किया है कि 2022 में उसके भू-भाग में मिलाए गए चार क्षेत्रों से यदि यूक्रेन अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर देता है और नाटो में शामिल होने की योजना छोड़ देता है तो वह 'तुरंत संघर्ष विराम करेगा और बातचीत शुरू करेगा। रूसी राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय आया है जब जी-7 के नेता समेत कई वैश्विक नेता इटली में जुटे हैं और यूक्रेन में शांति कायम करने के प्रयासों के तहत स्विट्जरलैंड इस सप्ताहांत में कई वैश्विक नेताओं के सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जिसमें रूस शामिल नहीं होगा। पुतिन का कहना है कि उनके प्रस्ताव का उद्देश्य यूक्रेन में संघर्ष का ठोस समाधान निकालना है, पर उनके प्रस्ताव से समाधान की उम्मीद कम लग रही है। इसमें रूस की एकतरफा शर्त है। अमेरिका की जिद यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने की है। इसलिए भी रूस की पेशकश के माने जाने की उम्मीद कम है। अमेरिका और जी-7 के यूरोपीय देश अगर यूक्रेन को आर्थिक व हथियारों की मदद बंद कर दें, तो युद्ध को समाप्त होने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। जी-7 में जापान को छोड़कर बाकी सदस्य देशों की रूस के साथ पुरानी अदावत है, इस अदावत के चलते ही अमेरिका व ब्रिटेन खुल कर यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं, ये देश रूस को पस्त करना चाह रहे हैं, पर बर्बादी यूक्रेन की हो रही है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के विवेक पर युद्ध का अंत का सारा दारोमदार ठहर जाता है। जी-7 की बैठक से इतर पीएम नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता में कहा है कि शांति का रास्ता 'बातचीत और कूटनीति' से होकर गुजरता है। इससे पहले भी पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अलग अलग बातचीत में युद्ध छोड़ कर वार्ता के टेबल पर आने की अपील कर चुके हैं। भारत चाहता है कि दोनों युद्ध खत्म हों, विश्व में शांति हो, ताकि वैश्विक विकास को गति मिले। यूक्रेन में शांति के लिए स्विटज़रलैंड में होने वाले सम्मेलन के सफल होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जी-7 बैठक से अमेरिका व विकसित यूरोपीय देशों में युद्ध समाप्ति की दिशा में मोमेंटम बनने की पूरी संभावना है।

नीट परिणाम विवाद

राजेश जैन

दांव पर एनटीए की साख

नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(एनटीए) ने बिना किसी सूचना के 4 जून को अचानक जारी कर दिया। परिणामों ने तब खलबली मचा दी, जब 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 का स्कोर हासिल कर लिया। इससे पहले से चल रही पेपर लीक की आशंकाओं को बल मिला और लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया के करीब सभी प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2024 का रिजल्ट खूब ट्रेंड कर रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को स्कैम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई स्टूडेंट्स रिजल्ट में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। एनटीए ने इस बीच बार-बार सफाई दी, लेकिन हर सफाई पर नए सवाल खड़े हो गए। सवालों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई, एनटीए के मुखिया को ही उसका चेयरमैन बना दिया गया। गड़बड़ी को लेकर दिल्ली, भोपाल, वाराणसी समेत देशभर में हजारों छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पेपर लीक के मामले में भले ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर एनटीए से कहा है कि नीट यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए। पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली और कलकत्ता हाईकोर्ट में नई याचिकाएं दायर की गई हैं और एनटीए की साख दांव पर लगी हुई है। बीते साल नीट यूजी में शामिल अभ्यर्थियों के औसत मार्क्स 279.41 थे, जबकि इस बार यह बढ़कर 323.55 हो गए हैं। काट ऑफ में पहली बार एक ही साल में करीब 45 अंकों की जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालत यह है कि पिछले साल 600 नंबर पर कई जनरल बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल गया था, इस साल 640 नंबर वाले को भी सीट नहीं मिलेगी। पिछले साल 612 नंबर पर करीब 26 हजार रैंक थी, इस साल 76 हजार स्टूडेंट्स ने यह नंबर हासिल कर लिए। टॉपर्स लिस्ट के सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 के स्टूडेंट्स हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं। इनमें किसी छात्र के नाम में सरनेम नहीं है। इन 8 में से 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक हासिल हुए है, वहीं, अन्य दो को 719, 718 हैं। ऐसी ही गड़बड़ी यूपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में आई है। यूपी, तमिलनाडु और गुजरात में रैंक-1 वालों के रोल नंबर काफी करीबी हैं। यह समानता बताती है कि इन स्टूडेंट्स को संभवतः एक ही सेंटर अलॉट हुआ है और एक सेंटर्स से नीट के ज्यादा टॉपर्स निकले। सवाल यह भी उठ रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को 720 में से 719 और 718 अंक कैसे मिल सकते हैं। नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, उसे आनन-फानन में 4 जून को तब जारी कर दिया गया जब देश लोकसभा चुनाव के परिणाम में उलझा हुआ था। आखिरी इतनी भी जल्दी क्या थी? इसके अलावा ओएमआर शीट अपलोड नहीं होने, फाड़ देने, जला देने, ओएमआर शीट और मार्कशीट में अलग अलग अंक होने की शिकायतें भी सोशल मीडिया पर खूब की जा रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर कुछ सेंटर्स पर बच्चों का समय बर्बाद हुआ था तो उनको अतिरिक्त समय दिया जाता ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई। बिना जानकारी के ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। वे बिना ग्रेस मार्क्स के नीट की ओरिजिनल मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्टीकरण जारी कर बताया है कि 5 मई को परीक्षा के दौरान कुछ सेंटर्स पर बहुत से स्टूडेंट्स का समय बर्बाद हुआ था। इसको लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली व छत्तीसगढ़ में रिट पिटिशन दाखिल की गई थी। इसके चलते ग्रेस मार्क्स देने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसने एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी और मौजूद कर्मचरियों की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन किया और यह मामला सही निकला। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किया गया जो कि 13 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्लेट एक्जाम में टाइम लॉस की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया था। बहरहाल, नीट में कुछ छात्रों द्वारा असाधारण अंक प्राप्त करना सामान्य नहीं है। यह परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता कई उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, लेकिन जब परीक्षा में धांधली होती है तो इनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। इससे उन छात्रों के बीच निराशा पैदा कर दी है जो कठोर तैयारी के बावजूद कटऑफ से चूक गए। इससे मेडिकल शिक्षा प्रणाली में भरोसा भी कम होगा। विश्वास बनाए रखना और समान अवसर सुनिश्चित करना अहम है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

विश्लेषण

डॉ. एल. एस. यादव

रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना होगा

केंद्र की नई सरकार गठित हो चुकी है और मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। गठबंधन की इस नई सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह रक्षा क्षेत्र में भी अनेक चुनौतियां हैं, जिनसे रक्षा मंत्रालय एवं तीनों सेनाओं को मिलकर निपटना है। सरकार में राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है। वे पिछली सरकार में भी रक्षा मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। रक्षा मंत्री के लिए चीन और पाक की सीमा पर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने की सैन्य तैयारियां भी बढ़ानी हैं। उनके लिए वित्त मंत्री से अधिक रक्षा बजट की मांग पूरी करवाना भी विशेष कार्य रहेगा। भारत का रक्षा बजट चुनौतियों के हिसाब से हमेशा कम रहा है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार गठित हो चुकी है और मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। गठबंधन की इस नई सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह रक्षा क्षेत्र में भी अनेक चुनौतियां हैं, जिनसे रक्षा मंत्रालय एवं तीनों सेनाओं को मिलकर निपटना है। सरकार में राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है। वे पिछली सरकार में भी रक्षा मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 11 जून को अपना कार्यभार संभाल लिया था। रक्षा मंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह को अग्निपथ योजना की समीक्षा करके उसे आकर्षक बनाने का काम अत्यन्त सामयिक दिया गया है। इसके अलावा सैन्य सुधारों को लागू करना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का गठन, हथियारों के आयात में कमी करना, रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता को बढ़ाना, पाकिस्तान व चीन सीमा पर बने तनाव से निपटने के रास्ते निकालने की जिम्मेदारी के साथ ही रक्षा बजट अधिक करवाना है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रक्षा मंत्री इन सभी से कैसे निपटेंगे?

अग्निपथ योजना में भर्ती होने को लेकर युवाओं ने शुरूआत से ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। इस योजना के विरोध में काफी दिनों तक आन्दोलन चलाए गए। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक युवाओं की यह नाराजगी दिखाई पड़ी थी। यह आत अलग है कि बाद में नवयुवक इस योजना में भर्ती होने लग गए थे। इस योजना का अनेक सेवानिवृत्त सैनिकों ने इसका विरोध करते हुए सवाल उठाए थे। इसके अलावा इस चुनाव में कुछ विपक्षी दलों ने अग्निपथ योजना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। वहीं कुछ लोगों ने इस योजना की समीक्षा की बात की।

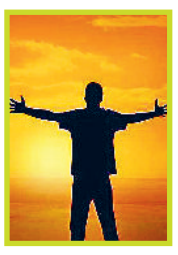

उल्लेखनीय है कि इस योजना में युवाओं को चार साल के लिए भर्ती किया जाता है। यह योजना सेनांगों के लिए थी। इस योजना के 25 प्रतिशत जवानों को ही स्थायी होने का अवसर मिलेगा। शेष जवानों को अन्य क्षेत्रों में रोजगार की तलाश करनी पड़ेगी। स्थायी सैनिकों की तुलना में इनको 30 दिन की छुट्टी मिलती है। अब इस योजना में सुधार को लेकर सेना के भीतर से ही कुछ सुझाव मिले हैं, इसलिए इसकी समीक्षा किए जाने की बात चल रही है और समीक्षा के लिए सचिवों को जिम्मदारी सौंप दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि अग्निपथ योजना में यदि बदलाव की आवश्यकता हुई तो वे करने को तैयार हैं। सैनिक सुधार करना सरकार के एजेंडे में शामिल है। अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने इसे प्रमुखता से शामिल किया था। इन सैन्य सुधारों में सबसे प्रमुख सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना को मिलाकर एकीकृत थिएटर कमांड का गठन करना है। इसमें नए सेनाध्यक्ष की भूमिका प्रमुख होगी। विदित हो कि मोदी सरकार के नेतृत्व में वर्ष 2019 में थिएटर कमांड बनाए जाने का निर्णय हुआ था और उसी समय जनरल विपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। इस योजना

का उद्देश्य छोटी या बड़ी लड़ाइयों के समय अपने निश्चित सामरिक लक्ष्यों के साथ विशिष्ट शत्रु आधारित थिएटरों में संयुक्त अभियानों के लिए थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना को एकीकृत करना है। भरतीय सशस्त्र बल थिएटर कमांड के गठन की तैयारियों को पूरा करने में लगे हुए हैं। वर्ष 2019 से अब तक की इस अवधि में निचले स्तर पर सेवाओं को एकीकृत करने के कुछ प्रयास किए गए हैं। बीते पांच वर्षों में थिएटर कमांड के लिए उत्तम संभव मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनेक मसौदे तैयार किए गए। अब सरकार गठन के बाद इस पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

मार्च 2024 में स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) यानी कि सिपरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत संसार के शीर्ष हथियार आयातक देशों में शामिल है। यह संस्था दुनियाभर में हथियारों की खरीद-फरोख्त पर नजर रखती है और प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जारी करती है। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने वर्ष 2019 से 2023 तक पांच वर्षों में दुनियाभर से 9.8 फीसदी हथियार आयात किए हैं। भारत के लिए इस चुनौती से निपटना जरूरी हो गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को कम किया जाए। यह कार्य कैसे किया जाए इससे रक्षा मंत्री को निपटना होगा। बीते दशक से मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया पर लगातार जोर दिया है। इसी अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को काफी बढ़ावा दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के रक्षा उद्योग में सैन्य साजो-सामान का उत्पादन काफी बढ़ गया है। स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइलें, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर, स्कॉरपियन श्रेणी की पनडुब्बियों ने देश के रक्षा क्षेत्र को काफी आगे बढ़ा दिया है। इस कारण भारत के रक्षा निर्यात में काफी बढ़ोत्तरी हो गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का सैन्य निर्यात 21083 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। फिलीपींस, पोलैंड तथा अफ्रीकी देशों ने भारत में मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों की खरीद में रुचि दिखाई है। अब जरूरत इस बात की है कि भारत रक्षा मैन्यूफैक्चरिंग इतना आगे बढ़े कि रक्षा आयात को कम किया जा सके।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए पाकिस्तान और चीन की सीमा पर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने की सैन्य तैयारियां भी बढ़ानी हैं। जहां पाकिस्तान भारतीय सीमा के नजदीक किसी भी यौद्धिक स्थिति से निपटने के लिए चीन की मदद से बंकर तैयार करने के साथ-साथ अत्याधुनिक हथियार ले रहा है तो दूसरी तरफ चीन के साथ भी तनाव बना हुआ है। वर्ष 2020 में पैदा हुए तनाव के बाद के बाद से अभी तक 21 दौर की वार्ता के बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल नहीं हुई है, इसीलिए चीन और पाकिस्तान की सीमा पर जवान डटे हुए हैं। रक्षा मंत्री के लिए एलएसी तथा एलओसी पर शांति व स्थिरता बनाए रखने की चुनौती होगी।

देश की रक्षा चुनौतियों से निपटने लिए धन की अधिक आवश्यकता होती है। रक्षा मंत्री के लिए वित्त मंत्री से अधिक रक्षा बजट की मांग पूरी करवाना भी विशेष कार्य रहेगा। भारत का रक्षा बजट रक्षा चुनौतियों के हिसाब से हमेशा कम रहा है। भारत का रक्षा बजट 74 अरब डॉलर के लगभग है जबकि अमेरिका का 832 अरब डॉलर, चीन का 227 अरब डॉलर व रूस का 109 अरब डॉलर है। दुनिया के प्रमुख देशों के रक्षा बजट के हिसाब से भारत चौथे नम्बर पर है। चीन का रक्षा बजट भारत से तीन गुना से ज्यादा है। अधिक रक्षा बजट होने पर ही भारत अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण के बाद ही अन्य देशों के बराबर पहुंच सकेगा।

(लेखक सैन्य विज्ञान के प्राध्यापक रहे हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

हर मानव में शुभ व अशुभ इच्छाएं होती है

संकलित

दर्शन

शिव कल्याणकारी हैं। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश का अर्थ ही है कि जहां केवल उत्सव हो, केवल आनंद हो। श्रावण के महीने में संपूर्ण वातावरण उत्सव से भर जाता है। शिव-तत्व अपने चरम पर होता है, यह सहजता से उपलब्ध होता है। इसलिए यह मास भगवान शिव की पूजा करने के लिए सर्वोत्तम मास है। हमारे प्राचीन ऋषि अत्यंत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि हर मानव के भीतर इच्छाएं होती हैं, कुछ शुभ और कुछ अशुभ। जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है कि शुभ इच्छाएं फलित हों। विवेक के उपयोग से मनुष्य यह निर्णय ले सकता है कि कौन-सी इच्छाएं उसके लिए लाभदायक हैं और उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य कर सकता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वह अपने इच्छित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। उसे मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कारण विविध हो सकते हैं, कुछ अत्यंत सूक्ष्म, कुछ अधिक सूक्ष्म नहीं। ऋषियों ने इस समस्या पर विचार किया और एक अद्भुत समाधान निकाला। उन्होंने मानव कल्याण के लिए संकल्प और पूजा की प्रक्रिया तैयार की। पूजा आरंभ करने से पूर्व पूजा करने वाले यजमान द्वारा संकल्प लिया जाता है। संकल्प वह विशिष्ट उद्देश्य है, जिसके लिए पूजा आयोजित की जा रही है। संकल्प का उच्चारण करने से पहले स्थान (देश) और समय (काल) को परिभाषित किया जाता है, जहां पूजा आयोजित की जा रही है।

बिना लड़ाई किए धैर्य से भी जीता जा सकता है

संकलित

प्रेरणा

महाभारत में युधिष्ठिर को चक्रवती सम्राट बनाने के लिए राजसूय यज्ञ किया गया था। इसके लिए सभी राजाओं पर जीत हासिल करनी थी। इस काम के लिए अर्जुन ने विजय यात्रा शुरू कर दी। जहां-जहां अर्जुन जा रहे थे, वहां के राजाओं को पराजित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो राजा अर्जुन की सेवा स्वीकार कर रहे थे, अर्जुन उन पर कर लगाकर आगे बढ़ रहे थे। इस यात्रा के दौरान अर्जुन कुरु नाम के राज्य में पहुंचे। अर्जुन पहुंचे तो कुरु राज्य के द्वारपाल और लोगों ने अर्जुन से कहा कि आप इस नगर को युद्ध करके जीत नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति इस नगर में युद्ध के लिए प्रवेश करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा इस राज्य को वरदान मिला हुआ है। अर्जुन ने सोच-विचार करके कहा कि ठीक है, मैं यहां युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की बात सुनकर लोगों ने कहा कि युद्ध के अलावा अगर आपकी कोई इच्छा है तो वह पूरी हो सकती है। अर्जुन ने कहा कि मैं हमारे भाई युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूं। मुझे आपसे युद्ध नहीं करना है। आप बस मुझे कर के रूप में थोड़ा सा धन दे दीजिए। ये धन लेकर मैं लौट जाऊंगा। लोगों ने अर्जुन की बात मानकर थोड़ा सा धन दे दिया। धन लेकर अर्जुन दूसरे राज्य की ओर बढ़ गए। अर्जुन ने संदेश दिया है कि हर शत्रु को युद्ध करके पराजित नहीं किया जा सकता है, कुछ शत्रुओं के सामने बुद्धि और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग करते हुए भी शत्रुओं की हराया जा सकता है।

अंतर्मन

आज की पाती

कायर आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी

जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में मां वैष्णो देवी के दरबार से दर्शन करके लौटते श्रद्धालुओं की बस पर समाज पर कलंक आतंकवादियों द्वारा हमला करने की कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ ही पाकिस्तान की निरंतर इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कायराना सोच को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हैरानी की बात है कि कायर आतंकवादियों द्वारा जिस तरह से दर्शनों से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग को अंजाम दिया गया, वहीं इस तरह से निर्दोष लोगों पर हमला करके आतंकवादियों ने यह दर्शा दिया है कि वे समूची मानवता पर ही कलंक हैं।

-रोहित गुप्ता, राजनांदगांव

ट्रेंड

करियर से खिलवाड़ नहीं होगा

नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे के करियर से खिलवाड़ नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।

-धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

जीवन की सार्थकता

जैसे नदी की संपूर्णता सागर तक पहुंचने और अपने अस्तित्व को उसमें विलीन कर देने में निहित है, उसी प्रकार जीवन की सार्थकता ईश्वरीय विधान के प्रति समर्पण से सिद्ध होती है। अहंकार के अवसान होते ही जीवन की दिव्यताएं प्रकट होने लगती हैं।

-अवधेशानंद, आध्यात्मिक गुरु

सावधान रहना होगा

अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी जी की मरने की कामना की जा रही है। बीजेपी को दलितों से इतनी नफ़रत है कि अयोध्या से सपा सांसद को मारने की तैयारी चल रही है। पीडीए को बीजेपी जैसी नफरती पार्टी से सावधान रहना होगा।

-संजय सिंह, आप नेता

उनके लिए दुखी हैं

कुवैत में भीषण अग्निकांड में 42 लोगों की मौत हो गई। वे महान व्यक्तिगत बलिदान देकर विदेश गए। वे काम पर गए और अपने पीछे छोड़े गए परिवारों के लिए बेहतर जीवन अर्जित किया। हम उनके लिए दुखी हैं।

-आनंद महिंद्रा, उद्योगपति

करंट अफेयर

ईरान ने सेंट्रीफ्यूज लगाना किया शुरू

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने शुक्रवार को कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर आलोचना का सामना करने के बाद उन्नत सेंट्रीफ्यूज लगाना शुरू किया है और आगामी हफ्तों में अन्य को भी लगाये जाने की योजना है। वहीं, अमेरिका ने इस कदम को परमाणु खतरा बढ़ाने वाला कदम बताया है। नये सेंट्रीफ्यूज लगाये जाने से ईरान के परमाणु कार्यक्रम में और तेजी आएगी, जो पहले से यूरेनियम का संवर्द्धन कर उसे आयुध स्तर का बना चुका है और कई परमाणु आयुध बनाने के लिए इसका पर्याप्त भंडारण कर चुका है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की स्वीकारोक्ति में, ईरान के अधिक संवर्द्धन करने की योजना का कोई संकेत नहीं मिला है। आईएईए ने कहा कि इसके निरीक्षकों ने सोमवार को सत्यापित किया कि ईरान ने अपने नतांज संवर्द्धन केंद्र में उन्नत आईआर-4 और आईआर-6 सेंट्रीफ्यूज के तीन 'कासकेड' में यूरेनियम भरना शुरू कर दिया है। कासकेड, सेंट्रीफ्यूज का एक समूह है जो यूरेनियम के संवर्द्धन में तेजी लाता है।

ऑफ बीट

दुनिया के अकेले पौधे के लिए महिला साथी की तलाश

जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड फोर्टी ने जीवन के विकास के बारे में अपनी पुस्तक में एक पौधे के बारे में लिखा है, 'नि:संदेह यह दुनिया का सबसे अकेला जीव है।'

दरअसल वह दक्षिण अफ्रीका के एक पौधे एन्सेफलार्टोस वुडी (ई. वुडी) के बारे में बात कर रहे थे। ई. वुडी साइकैड परिवार का एक सदस्य है। ये पौधे मोटे तने और बड़ी कड़ी पत्तियों वाले होते हैं और इनकी पत्तियां जैसे एक राजसी मुकुट जैसा बनाती हैं। इन लचीले उत्तरजीवियों ने डायनासोर और कई सामूहिक विलुप्तियों को मात दी है। एक समय इनका अस्तित्व बड़े पैमाने पर था, लेकिन आज ये ग्रह पर सबसे विलुप्त प्रजातियों में से एक हैं। एकमात्र ज्ञात जंगली ई. वुडी की खोज 1895 में वनस्पतिशास्त्री जॉन मेडले वुड द्वारा की गई थी, जब वह दक्षिण अफ्रीका के नगोय वन में वनस्पति अभियान पर थे। उन्होंने आसपास इसके जैसे अन्य पौधों की तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। अगले कुछ दशकों में, वनस्पतिशास्त्रियों ने तने और शाखाएँ हटा दीं और बगीचों में इनकी खेती की। इस डर से कि अंतिम तना नष्ट हो जाएगा, वन विभाग ने 1916 में इसे दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक सुरक्षात्मक बाड़े में सुरक्षित रखने के लिए जंगल से हटा दिया, जिससे यह जंगल से विलुप्त हो गया। तब से यह पौधा दुनिया भर में उगाया गया है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

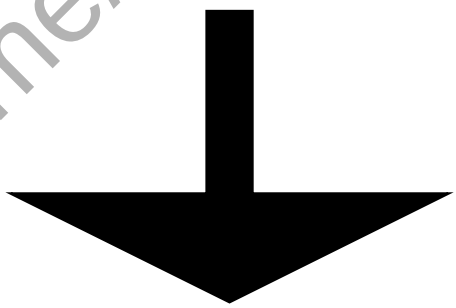

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid